



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236842
CG-DL-E-27062022-236842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]
No. 163]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASADHA 3, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

[किस सं. एडी (एसएसआर)/2021]

विषय: चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट" के आयातों से संबंधित निष्पत्तिक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/26/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 को चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट" के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 28 मार्च, 2017 के प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 25/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम शुल्क लगाया। उसके बाद, दिनांक 13 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/36/2016-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किया गया था जिसमें चीन जन. गण.,

जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय लगाए जाने की पुष्टि की गई थी जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किया गया था। उपर्युक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाये गये थे। कस्टम अधिसूचना संख्या देखें। 19/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 03.06.2022, उक्त शुल्क को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 03.06.2022, उक्त शुल्क 27.09.2022 तक बढ़ा दिया गया था।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पूर्व में न हटाए गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएंगे। प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
3. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:
"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग या उनकी ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
4. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट" (जिसे यहां आगे 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए, अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया था।
6. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23(ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, दिनांक 27 अगस्त, 2021 के मामला संख्या एडी (एसएसआर)-20/2021 के लिए अधिसूचना संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
7. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 13 दिसंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/36/2016-डीजीएडी द्वारा जारी संबद्ध सामानों से संबंधित पूर्व की जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

8. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - (i) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - (ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना जारी की।
 - (iii) प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को दिनांक 27 अगस्त, 2021 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने अनुरोध दें और सूचना उपलब्ध कराएं।

- (iv) संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी। भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- (v) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- (vi) प्राधिकारी ने संगत सूचना मंगाने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
- (क) वायर मैटेरियल साइंस (चीन) कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.।
 - (ख) चांगझौ दहुआ ग्रुप कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.।
 - (ग) शंघाई बीएसएफ पॉलीयूरेथेन कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.।
 - (घ) वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - (ङ) यंताई जूली फाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.।
 - (च) हेनान जीपी केमिकल्स कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - (छ) फुज़ियान पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रियल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - (ज) मित्सुई केमिकल्स एंड एसकेसी पॉलीयूरेथेनेस, जापान।
 - (झ) निप्पॉन पॉलीयूरेथेन उद्योग कं, लिमिटेड, जापान।
 - (ञ) बीएसएफ कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य।
 - (ट) एवरलाइट कोरिया कं, लिमिटेड, कोरिया आर.पी.
 - (ठ) हनवा केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
 - (ड) आईएमएस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - (ढ) ओसीआई कॉर्पोरेशन/ओसीएल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य।
 - (ण) पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
 - (त) कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स (चीन) कंपनी
- (vii) निम्नलिखित कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के रूप में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- क. कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स (चीन) कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - ख. कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - ग. कोवेस्ट्रो (शंघाई) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (एमईटी प्रश्नावली)
 - घ. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - ङ. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर, पीटीई लिमिटेड, चीन जन. गण.)
 - च. वानहुआ केमिकल फुज़ियान कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - छ. वानहुआ केमिकल (यांताई) सेल्स कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - ज. वानहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - झ. बीएसएफ कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
 - ञ. हनवा सॉल्यूशंस कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ट. एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य

- ठ. आईएमएस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य
- ड. पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य
- (viii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार दें:
- (क) आदि पॉलिमर प्रा. लिमिटेड
- (ख) एलाइड फोम प्रा. लिमिटेड
- (ग) ड्यूरापफ (सिलवासा) प्रा. लिमिटेड
- (घ) फैसी फोम प्रा. लिमिटेड
- (ङ) हिन्दुस्तान पॉलीफोम प्रा. लिमिटेड
- (च) जिंदल फोम एंड कंपनी
- (छ) कुर्लोन लिमिटेड
- (ज) एमएच पॉलिमर प्रा. लिमिटेड
- (झ) तिरुपति फोम लिमिटेड
- (ञ) प्यारेलाल फोम (साउथ) प्रा. लिमिटेड
- (ट) प्राइम कंफर्ट प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड
- (ठ) स्प्रिंगवेल मैट्रेसेस प्रा. लिमिटेड
- (ड) शीला ग्रुप कं, लिमिटेड
- (ढ) श्री मलानी फोम्स प्रा. लिमिटेड
- (ण) सनराइज फोम उत्पाद प्रा. लिमिटेड
- (त) स्प्रिंगफिल पॉलीयूरेथेनेस प्रा. लिमिटेड
- (ix) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर उत्तर दिया है:
- क. बीएसएसएफ इंडिया लिमिटेड
- ख. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- ग. फ्लेक्सिपोल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
- घ. एम.एच. पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. पीयू फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
- च. श्री मलानी प्राइवेट लिमिटेड
- छ. शीला फोम लिमिटेड
- ज. तिरुपति फोम लिमिटेड
- झ. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- (x) इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन द्वारा कानूनी अनुरोध भी दायर किए गए हैं।
- (xi) सभी हितवद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितवद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं थी।

- (xii) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के व्यौरे दें, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन तथा क्षति विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। विश्लेषण किया गया है और यह पाया गया है कि प्राधिकारी और आवेदक द्वारा किए गए विश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
- (xiii) घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक टेबल सत्यापन किया गया था। इस प्रकटन विवरण के प्रयोजन के लिए केवल आवश्यक सुधार के साथ ऐसी सत्यापित सूचना, जहां कहीं लागू हो, पर विश्वास किया गया है। आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक और अन्य हितवद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी।
- (xiv) क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और निर्माण एवं विक्री लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। यह क्षतिरहित कीमत इस प्रकार निकाली गई है कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xv) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितवद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 27 दिसंबर, 2021 को मौखिक सुनवाई की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई की गई। जो पक्षकार मौखिक सुनवाई में उपस्थित थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे लिखित अनुरोध दायर करें ताकि इसके बाद विरोधी हितवद्ध पक्षकार प्रत्युत्तर दायर कर सकें।
- (xvi) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्ष, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल हैं।
- (xvii) जांच प्रक्रिया और मौखिक सुनवाई के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस प्रकटन विवरण में हल किया गया है।
- (xviii) हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपान्तर उपलब्ध कराएं।
- (xix) जहां कहीं किसी हितवद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- (xx) नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को दिनांक 13 मई, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- (xxi) प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.22 रुपये ली गई है।
- (xxii) इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

9. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में वर्णित था:

टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$ है। यह संभावित आइसोमर्स में से दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं: 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएस: 91-08-7)। 2,4-टीडीआई का उत्पादन शुद्ध अवस्था में किया जाता है, लेकिन टीडीआई का विपणन प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का संबंध (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से है और अन्य कोई ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।"

टीडीआई एक स्पष्ट तरल है और इसका उपयोग लचीले पॉलीयूरेथेन फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गार्केट, खेल और चिकित्सा उपयोग के लिए सुरक्षात्मक पैड, ऑटोमोबाइल: सीटों, फर्नीचर, अस्तर, सन वाइजर आदि, पैकिंग: इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्रोजन फूड्स, दवाओं, ऑडियो-वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) आवेदक वीएचटी मुक्त सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकता है, जबकि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों ने टीडीआई, जो वीएचटी मुक्त नहीं है, के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तरदाता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे यह जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में वीटीएस मुक्त टीडीआई का उत्पादन और बिक्री की थी। तदनुसार, वीटीएस मुक्त टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ख) आवेदक 80:20 के अनुपात में टीडीआई और एमडीआई मिश्रण का निर्माण कर रहा है। तथापि, वे 65:35 के अनुपात के साथ टीडीआई और एमडीआई मिश्रण का निर्माण करने में असमर्थ हैं। अतः, इसे स्पष्ट रूप से उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ग) आईपीयू का कहना है कि टीडीआई 80:20 और 65:35 के दो आइसोमेट्रिक सांद्रता में निर्मित होता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में विशेष रूप से 80:20 के अलावा अन्य अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई को बाहर रखा जाना चाहिए।
- (घ) इसके अतिरिक्त, आवेदक यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि क्या याचिका में निर्धारित आंकड़े केवल 80:20 अनुपात वाले टीडीआई से संबंधित हैं और क्षति विश्लेषण के विरूपण से बचने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करते समय अन्य रूपों को अलग किया गया है।
- (ङ) प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और भारत में आयात किए जा रहे टीडीआई के 80:20 को छोड़कर विभिन्न ग्रेडों को स्पष्ट नहीं किया है और क्या घरेलू उद्योग के आंकड़े और आयात आंकड़े उन उत्पादों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- (क) वर्तमान आवेदन पत्र निर्णायक समीक्षा के लिए एक आवेदन पत्र होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि प्राधिकारी ने अपने पूर्व के जांच परिणाम में परिभाषित किया था।
- (ख) प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा उत्पादित सामान घरेलू बाजार में आयात किए जाने वाले सामानों की समान वस्तु है। प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं हुआ है और आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद समान वस्तु की तरह बना हुआ है।
- (ग) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात के लिए वीएचटी मुक्त सामग्री की आवश्यकता वाले प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर, आवेदक वीएचटी मुक्त संबद्ध सामानों की आपूर्ति कर सकता है।
- (घ) वीएचटी मुक्त टीडीआई की मांग काफी नहीं है, और यह अनुरोध केवल प्राधिकारी का ध्यान आधारहीन तर्कों की ओर ले जाने के लिए किया गया है।
- (ङ) कोई भी प्रयोक्ता जो निर्यात प्रयोजन के लिए वीएचटी मुक्त सामग्री का प्रयोग करना चाहता है, अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत किसी पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना उसका आयात कर सकता है।
- (च) आवेदक आइसोमर सामग्री 65:35 वाले टीडीआई का उत्पादन नहीं कर रहा है।

(छ) आवेदक ने टीडीआई-एमडीआई मिश्रण को बाजार में बेचा है और सम्मिश्रण की प्रक्रिया बहुत साधारण है तथा मिश्रण के अनुपात को उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार बदला भी जा सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. मूल जांच में, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया था:

"टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$ है। यह संभावित आइसोमर्स में से दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं: 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएस: 91-08-7)। 2,4-टीडीआई का उत्पादन शुद्ध अवस्था में किया जाता है, लेकिन टीडीआई का विपणन प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का संबंध (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से है और अन्य कोई ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है।"

टीडीआई एक स्पष्ट तरल है और इसका उपयोग लचीले पॉलीयूरेथेन फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गार्सकेट, खेल और चिकित्सा उपयोग के लिए सुरक्षात्मक पैड, ऑटोमोबाइल: सीटों, फर्नीचर, अस्तर, सन वाइजर आदि, पैकिंग: इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्रोजेन फूड्स, दवाओं, ऑडियो-वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है।

13. विचाराधीन उत्पाद के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध करने पर कि 80:20 के अलावा अन्य अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई को विशेष रूप से क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र आइसोमर सामग्री 80:20 वाले टीडीआई तक सीमित है और कोई अन्य आइसोमर सामग्री वाला टीडीआई विचाराधीन उत्पाद से बाहर है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पहले से ही 65:35 के आइसोमेट्रिक सांद्रता वाले टीडीआई को बाहर कर देता है। विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं है।

14. 65:35 अनुपात के टीडीआई-एमडीआई मिश्रण को हटाने के लिए अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टीडीआई और एमडीआई के सम्मिश्रण में एमडीआई (एक अन्य रसायन) के साथ टीडीआई 80:20 (विचाराधीन उत्पाद) का साधारण मिश्रण शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टीडीआई-एमडीआई मिश्रण से फोम उत्पादित होता है और फोम की कठोरता इसमें टीडीआई और एमडीआई की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। टीडीआई और एमडीआई को अलग-अलग अनुपात में मिश्रित किया जा सकता है जैसे क्रमशः 70% - 30%, 80% - 20%, 50% - 50% आदि।

15. इस प्रकार, टीडीआई-एमडीआई मिश्रण एक पूरी तरह से अलग उत्पाद है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं है।

16. यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतिम उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक वीएचटी मुक्त टीडीआई के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वीएचटी मुक्त टीडीआई की मांग नगण्य है और प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान किए बिना अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत वीएचटी मुक्त टीडीआई का आयात कर सकते हैं।

17. आवेदक ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं और हितवद्ध पक्षकारों ने भी आवेदक द्वारा उत्पादित सामान और आयातित उत्पाद में कोई अंतर सिद्ध नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विशिष्टियों, तकनीकी विशिष्टियों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक के आधार पर विवाद करते हुए कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
- (ख) आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है।
- (ग) आवेदक न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातक से संबद्ध है और न ही भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध है।
- (घ) आवेदक नियमावली की अपेक्षा को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

22. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में आयातक से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन पत्र नियम 5(3) के तहत 'आधार' की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ङ. विविध अनुरोध**ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

23. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) प्राधिकारी ने अमोनियम नाइट्रेट की समीक्षा जांच में इंडोनेशिया को स्कोप देशों से बाहर रखा था और अनकोटेड कॉपियर पेपर समीक्षा जांच में थाईलैंड को बाहर रखा था। इसी प्रकार, कोरिया को जांच के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि कोई क्षति नहीं है अथवा पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- (ख) विशेष रूप से, कोरिया से आयात में 72% तक गिरावट आई है, कोरिया का एलवी जांच की अवधि के दौरान अन्य संबद्ध देशों से एनआईपी और एलवी की तुलना में काफी अधिक (6.2%) है। इसके अतिरिक्त, वीएसएफ कंपनी का क्षमता उपयोग क्षति की पूरी अवधि के दौरान उसी रेंज में रहा।
- (ग) आवेदक ने एफटीए के साथ-साथ उल्टे शुल्क ढांचे के तहत जापान और कोरिया से संबद्ध सामानों के आयातों पर प्रशुल्क रियायतों का मुद्दा उठाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी इन मुद्दों को उठाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं हैं।
- (घ) आवेदक आयात के लगभग सभी प्रमुख स्रोतों से शुल्क ले रहा है।
- (ङ) आवेदक एक अनिश्चित मूल्य निर्धारण नीति अपनाता है और अपनी एकाधिकार स्थिति एवं पाटनरोधी शुल्क संरक्षण के कारण महीने में औसतन 2-3 बार कीमतों में बदलाव करता है।
- (च) मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता होती है क्योंकि आवेदक पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

- (छ) आवेदक की उत्पादन सुविधाएं देश के पश्चिमी कोने में स्थित हैं, जिससे पूर्वी और गहरे दक्षिणी ग्राहकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला मुश्किल हो रही है। आयात एकमात्र उत्पादक पर निर्भर होने के बजाय बंदरगाहों से अधिक अर्थक्षम हो जाता है।
- (ज) पाटनरोधी शुल्क का विस्तार कोई मानदंड नहीं है बल्कि अपवाद है। वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (झ) पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से, निर्यातक अपनी कीमतें वसूल करने का प्रयास करेंगे और पहुंच कीमत में वृद्धि होगी।
- (ञ) घरेलू प्रयोक्ताओं को आवेदक के प्रतिस्पर्धा-विरोधी और एकाधिकारवादी व्यवहार के विरुद्ध उचित व्यापारिक क्षेत्र की आवश्यकता है।

इ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) अमोनियम नाइट्रेट की समीक्षा जांच के मामले में, इंडोनेशिया को समीक्षा के क्षेत्र से हटा दिया गया था क्योंकि देश से कोई आयात नहीं हुआ था और उस मामले में घरेलू उद्योग पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध नहीं कर पाया।
- (ख) अनकोटेड पेपर की समीक्षा के क्षेत्र से थाईलैंड को बाहर करने का कारण यह था कि (क) पाटन मार्जिन न्यूनतम था (ख) आयात न्यूनतम था और (ग) प्राधिकारी को क्षति की कोई संभावना नहीं मिली।
- (ग) जैसा कि प्रश्नावली के भाग-II में अपेक्षित है, उत्तरदाता उत्पादकों को अपने-अपने देशों में उत्पादन, बिक्री और निर्यात के बारे में सूचना देनी होती है। तथापि, आवेदक के साथ साझा किए गए उत्तर के अगोपनीय रूपांतर के अनुसार, कोवेस्ट्रो पॉलिमर और बीएएसएफ लिमिटेड ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- (घ) आवेदक ने व्यापार सूचना 07/2018 में उल्लिखितानुसार पीडीएफ प्रारूप में आयात आंकड़े प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा किया है। प्राधिकारी सभी हितवद्ध पक्षकारों को ऐसे आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
- (ङ) भारतीय पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन (आईपीयूए) को मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी द्वारा भारत में 1 लाख टन से अधिक की मांग के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कहा गया था और आयात का कारण मांग एवं आपूर्ति का अंतर था, तथापि, कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- (च) आईपीयूए ने वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए अपनी साख सिद्ध नहीं की है।
- (छ) अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध कि संबद्ध देशों में उत्पादक शुल्क की समाप्ति से अपनी कीमतों में वृद्धि करना चाहेंगे, इसका अर्थ है कि उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्कों को खपा लिया है। इसके अतिरिक्त, यह माना जाता है कि निर्यातक अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, तीसरे देशों के निर्यात भारत को भेजे जाने की संभावना है क्योंकि निर्यातक उसे भारतीय बाजार में बेचना लाभदायक पाएंगे।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने एक विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र प्रदान किया है जिसके आधार पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/सूचनाओं के आधार पर शुरू की गई थी और प्राधिकारी ने स्वयं को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करने के बाद कि पाटन के पर्याप्त साक्ष्य हैं और पाटन तथा आवेदक को परिणामस्वरूप क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने से होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है।
- 26. इंडियन पॉलीयूरेथेन एसोसिएशन की भागीदारी के अनुरोध पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ग) और 6(5) के अनुसार, कोई उपभोक्ता एसोसिएशन उन मामलों में किसी पाटनरोधी जांच में भाग ले सकती है जब विचाराधीन उत्पाद को खुदरा स्तर पर बेचा जाए। जिन मामलों में विचाराधीन उत्पाद खुदरा स्तर पर नहीं बेचा जाता है, वहां औद्योगिक प्रयोक्ता भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी हितवद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है और वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सभी अनुरोधों पर विचार किया गया है।
- 27. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई अनिश्चित मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के बिक्री मूल्य के साथ-साथ आयात कीमत में भी काफी उतार-चढ़ाव है। आयातों की पहुंच कीमत और आवेदक की बिक्री कीमत

दोनों जांच की अवधि की पहली तिमाही में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, अगली तिमाही में गिरावट आई और उसके बाद इसमें और वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने आवेदन पत्र में स्वीकार किया है कि जांच की अवधि के दौरान उसके विक्री मूल्य, आयात की पहुंच कीमत और कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। अतः, जब बाजार बलों के कारण कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है, तो इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि आवेदक ने एक अनिश्चित मूल्य निर्धारण नीति रखी है।

28. कई हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उल्टे शुल्क दांचे को प्रस्तुत करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार को निष्क्रिय करना है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क एक सामान्य आधारभूत शुल्क नहीं है, बल्कि केवल एक उपचारात्मक उपाय है, उल्टे शुल्क संरचना के विरुद्ध तर्क तुच्छ और केवल एक तथ्य है। एफटीए के तहत टैरिफ रियायतों के कारण घरेलू उद्योग के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क का उपयोग एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है।
29. डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंकड़ों को भारत में निर्यातक देशों से आयात की मात्रा और मूल्य से संबंधित हितवद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने लेन-देन वार आयात आंकड़ों की पूरी सूची दी है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितवद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़े प्राप्त कर सकता है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना स्वयं का प्रति दावा दायर कर सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात आंकड़ों को साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए छाटे गए आयात आंकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है। और (ii) हितवद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से लेन-देन आयात आंकड़े द्वारा कच्चे लेनदेन के आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त कर सकते हैं। छाटे गए आयात आंकड़ों की हार्ड कॉपी को निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर हितवद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ बनाई गई थी। जिन हितवद्ध पक्षकार ने डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़ों की प्राप्ति के लिए अनुरोध किया था और व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार शपथ-पत्र दिया था, उन्हें डीजीसीआईएंडएस से एक्सेल फाइल में आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया था।
30. संबद्ध देशों के कार्यक्षेत्र से कोरिया गणराज्य को बाहर करने का अनुरोध करने वाले अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया गया है क्योंकि कोरिया गणराज्य से निर्यात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, अथवा पाटन और क्षति की कोई संभावना नहीं है। इस अनुरोध के लिए, हितवद्ध पक्षकारों ने अमोनियम नाइट्रेट की निर्णायक समीक्षा जांच पर विश्वास किया है जिसमें इंडोनेशिया को संबद्ध देशों के क्षेत्र से बाहर रखा गया था और अनकोटेड कॉपियर पेपर की निर्णायक समीक्षा जांच से बाहर रखा गया था जिसमें थाईलैंड को संबद्ध देशों के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितवद्ध पक्षकार द्वारा उल्लिखित जांचों के तथ्य वर्तमान जांच के तथ्यों के समान नहीं हैं। अमोनियम नाइट्रेट की निर्णायक समीक्षा के मामले में, इंडोनेशिया को बाहर रखा गया था क्योंकि जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुआ था और इंडोनेशिया से निर्यात के संबंध में पाटन अथवा क्षति की संभावना सिद्ध नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त, अनकोटेड कॉपियर पेपर की निर्णायक समीक्षा में, थाईलैंड को बाहर रखा गया था क्योंकि जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन न्यूनतम था और पाटन अथवा क्षति की संभावना सिद्ध नहीं की जा सकी। तथापि, वर्तमान मामले में, आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निरंतर क्षति और पाटन अथवा क्षति की संभावना सिद्ध की थी। इसके अतिरिक्त, जांच प्रक्रिया के दौरान, किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने संबद्ध देशों के क्षेत्र से कोरिया गणराज्य को बाहर करने का कोई औचित्य प्रदान नहीं किया है।
31. आईपीयूए ने इनपुट सामग्री के रूप में टीडीआई की खपत करने वाले प्रयोक्ता उद्योग की उत्पादन मात्रा के आधार पर अनुमान प्रदान किया है। फ्लेक्सिबल स्लैब फोम, मोल्डेड फोम, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में चिपकने वाले और इन उत्पादों के लिए खपत पैटर्न सहित तैयार उत्पादों के अनुमानित उत्पादन के आधार पर, आईपीयूए ने कुल मांग 1 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। तथापि, आईपीयूए प्रामाणिक रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा है जो उनके दावे को सिद्ध कर सके।

च. गोपनीयता

च.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. गोपनीयता के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन करता है।
- (ख) आवेदक द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया, खरीद/विक्री नीति, कच्ची सामग्री के नाम, विदेशी उत्पादकों के साथ संबंध आदि का खुलासा नहीं किया गया है।

- (ग) प्राधिकारी ने पिछले जांच परिणाम में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों का खुलासा किया था जिसे आवेदक द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- (घ) वैश्विक क्षमता की सूचना आईसीआईएस रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार है, जिसे गोपनीय होने का दावा किया गया है, भले ही इसमें व्यावसायिक संवेदनशील सूचना शामिल न हो।
- (ङ) घरेलू उद्योग ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के पूर्ण उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

33. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) बीएसएफ लिमिटेड और कोवेस्ट्रो पॉलिमर द्वारा बिक्री चैनल को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- (ख) हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में कीमत समायोजन की मद्दों को गोपनीय रखने का दावा किया गया है।
- (ग) हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन और वानहुआ केमिकल ग्रुप द्वारा दिए गए किसी भी सूचीकरण के साथ संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और मांग की सूचना को गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- (घ) इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कच्ची सामग्री को संबंधित आपूर्तिकर्ता से खरीदा गया है अथवा कैप्टिव रूप से उत्पादित किया गया है, हनवा सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- (ङ) अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, आवेदक ने वास्तव में दोनों संयंत्रों के लिए क्षतिरहित कीमत की रेंज का खुलासा किया है।
- (च) आवेदक ने दिनांक 7 सितंबर की व्यापार सूचना 10/2018 द्वारा अपेक्षानुसार सूचना का पूर्ण प्रकटन किया है।
- (छ) क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा मानी गई सभी संगत सूचना आवेदक द्वारा व्यापार सूचना के मुद्दों के अनुसार दी गई है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने नियम 6(7) और व्यापार सूचना 01/2020 के साथ पठित दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 (अगले नोटिस तक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए गए अनुसार) के अनुसार सभी हितवद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
35. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:
- "गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।
36. प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच संगत मानी गई सीमा की गई थी और तदनुसार समाधान किया गया था। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितवद्ध पक्षकारों के

समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

पाटन का मूल्यांकन – कार्यपद्धति और मापदंड

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

37. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) कोवेस्ट्रो चाइना नियमावली के अनुबंध-I, पैरा 8 के अनुसार गैर-वाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करते हुए निर्धारित मापदंडों को पूरा करती है।
- (ख) कोवेस्ट्रो चाइना कोवेस्ट्रो जर्मनी की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। चीनी सरकार अथवा चीनी कंपनी अथवा व्यक्ति द्वारा कोई होलिंग नहीं है।
- (ग) निदेशक मंडल में 3 सदस्य होते हैं और उन तीनों को कोवेस्ट्रो जर्मनी द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोवेस्ट्रो जर्मनी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है।
- (घ) कोवेस्ट्रो चाइना कोरिया, जापान से टॉलुइन का आयात करती है और स्थानीय स्तर पर इसका स्रोत भी है। कोवेस्ट्रो की कच्ची सामग्री की खरीद कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कीमतों को दर्शाता है।
- (ङ) कोवेस्ट्रो चाइना के व्यापार प्रचालनों पर चीन सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (च) कोवेस्ट्रो चाइना चीन जन. गण. में किसी भी कानून से अपमान अथवा छूट में नहीं है।
- (छ) कोवेस्ट्रो चाइना के वित्तीय विवरण चीन जन. गण. के जीएएपी द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी लेखापरीक्षा 4 बड़ी लेखापरीक्षा फर्मों में से एक के द्वारा की जाती है।
- (ज) टीडीआई बाजार एक कीमत पारदर्शी बाजार है, जिसकी कीमतें पीयू द्वारा दैनिक और आईसीआईएस द्वारा सामाहिक रूप से पोस्ट की जाती हैं। कोवेस्ट्रो चाइना इन कीमतों के आधार पर अपने उत्पाद बेचता है।
- (झ) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टेनसिटी पॉलिएस्टर यार्न की पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने उन्हीं आधारों के आधार पर एमईटी के दावे को स्वीकार किया था।
- (ञ) मूल देश से कच्ची सामग्री की निर्यात कीमत (घरेलू विक्री कीमत नहीं) का प्रयोग करने के लिए सुझाए गए सिद्धांत और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत बिना किसी कानूनी आधार के है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।
- (ट) कुइटन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ के मामले में, माननीय सेसटेट का निर्णय एक उपयुक्त तीसरे देश के चयन के लिए 'विकास के स्तर' की संगतता को बाहर नहीं करता है जब ऐसे तीसरे देश से दूसरे तीसरे देश को निर्यात किया जाता है। देश पर विचार किया जाना है।
- (ठ) प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर ताइवान एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है।
- (ड) लंबे समय तक आयात और निर्यात में लगे रहने के बाद भी, आवेदक के पास कीमतें प्रकाशित करने वाली व्यापार पत्रिकाओं तक पहुंच नहीं है।
- (ढ) आवेदक ने पाटनरोधी करार अथवा सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के असंगत सिद्धांत को अपनाने का चयन किया है।
- (ण) कोलाइन क्लोराइड जैसे मामलों में प्राधिकारी की पिछली परिपाटियों से यह सिद्ध है कि संबद्ध आयातक द्वारा पुनर्विक्रय कीमत पर आयातक के निर्यातक से संबद्ध होने की स्थिति में पहुँच कीमत के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाता है।
- (त) चूंकि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने वर्ष 2018 में ही उत्पादन शुरू किया था, अतः वानहुआ केमिकल ग्रुप के लिए एक अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

- (थ) यह आवेदन पत्र पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3(1) और 3.5 की अपेक्षानुसार तथाकथित आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं करता है।

छ.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

38. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए कोवेस्ट्रो पॉलिमर का दावा पूरी तरह से इस आधार पर है कि पूरी शेयर पूंजी यूरोप में स्थापित एक कंपनी के पास है। बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए कंपनी की शेयरधारिता एकमात्र मानदंड नहीं है।
- (ख) चीन जन. गण. के दो उत्पादकों ने उत्तर दायर किया लेकिन केवल कोवेस्ट्रो चाइना ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है और वानहुआ केमिकल ग्रुप ने नहीं किया है।
- (ग) यदि कोवेस्ट्रो पॉलिमर का दावा है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहा है, तो यह दर्शाने की आवश्यकता है कि इसकी लागत और कीमतें वानहुआ केमिकल ग्रुप के समान स्तर पर कैसे नहीं हैं। दोनों उत्पादकों के घरेलू विक्री मूल्य, कच्ची सामग्री की लागत, यूटिलिटियों की लागत और अन्य खर्चों के बीच तुलना की जानी चाहिए।
- (घ) कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि वह वनहुआ केमिकल, वीएसएफ, डॉव केमिकल और हंट्समैन के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। यह तथ्य कि दोनों उत्पादक चीन के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं, सिद्ध करता है कि चीनी बाजार में कीमत गैर-बाजार स्थितियों के कारण प्रभावित होती है।
- (ङ) चीन में टॉलुइन की कीमत गैर-बाजार स्थितियों के कारण प्रभावित होती है। चीन में टॉलुइन की आयात कीमत स्वाभाविक रूप से चीन में टॉलुइन की कीमत के अनुरूप होगी। चीन में कीमत वैश्विक आयात कीमत और आवेदक की कीमत से कम है।
- (च) सीएफआर कीमतों और दक्षिण पूर्व एशिया की कीमतों की तुलना से पता चलता है कि चीन में कीमतें अधिकतर महीनों में कम होती हैं।
- (छ) घरेलू कीमत और लागत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि चीनी उत्पादक यह नहीं दर्शाता कि लागत और कीमत के निर्धारण में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कीमतें बाजार मूल्य को दर्शाती हैं और घरेलू अथवा निर्यात बाजार में विक्री की मात्रा में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (ज) कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चीन में अपनी संबंधित कंपनियों कोवेस्ट्रो पॉलिमर और अन्य देशों में अन्य संबंधित उत्पादकों से आयात करती है। उत्पाद का कैप्टिव रूप से उपयोग किया जाता है और घरेलू बाजार में भी बेचा जाता है। तथापि, बाजार में देखी गई कीमत प्रवृत्ति के अनुसार, जिस कीमत पर कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आयात करती है, वह उस कीमत से काफी अधिक है जिस पर वह घरेलू बाजार में फिर से विक्री करती है।
- (झ) चीन का संविधान गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के साथ लगने की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, सरकार को एक मध्यस्थताकर्ता की भूमिका दी गई है जो गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारों और हितों की रक्षा से परे है और सरकार उनके विकास को "प्रोत्साहित, समर्थन और मार्गदर्शन" करेगी। संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित किया गया है कि देश समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की परिपाटी अपनाता है और यह स्पष्ट करता है कि यह अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रतिबंधित करने जैसे कई विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है।
- (ञ) चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान का सामान्य कार्यक्रम भी समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें उल्लेख है कि संसाधन आवंटन में बाजार बलों की निर्णायक भूमिका होती है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाए। यह सूक्ष्म आर्थिक विनियमन के लिए एक स्वच्छ प्रणाली सिद्ध करती है। कोवेस्ट्रो चाइना ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आधारभूत कार्यक्रम के तहत कैसे शासित नहीं हैं।
- (ट) राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी कार्य रिपोर्ट, भाषणों और संशोधित सीसीपी संविधान के सामान्य कार्यक्रम में 'सभी कार्यों' पर पार्टी के नेतृत्व की पुष्टि की। यही बात संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 तथा उसके बाद के कानूनों जैसे उद्यमों में सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति संबंधी कानून के अनुच्छेद 1 में भी उल्लिखित की गई है।

- (ठ) चीन ने औद्योगिक आधुनिकीकरण और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक मध्यस्थतावादी औद्योगिक नीति का सहारा लिया है। यह अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं और सरकार के स्तरों को शामिल करने वाली योजनाओं की एक विस्तृत प्रणाली को अपनाकर किया जाता है। यह सिद्ध किया गया है कि कोवेस्ट्रो चाइना चीनी सरकार के समर्थन से कार्य कर रही है।
- (ड) चीनी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका केवल स्वामित्व से परे है। निजी स्वामित्व वाली कंपनियों का सरकार से घनिष्ठ संबंध होना असामान्य नहीं है। कंपनियों को अनिवार्य रूप से उस श्रेणी में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो अंतिम स्वामित्व को दर्शाती है। यह दर्ज किया गया है कि चीनी सरकार 'विशेष प्रबंधन शेयर' बनाकर, अपनी कुछ सबसे बड़ी निजी तकनीकी कंपनियों को सरकार को उनमें हिस्सेदारी और कॉर्पोरेट निर्णयों में प्रत्यक्ष भूमिका की पेशकश करने के लिए प्रेरित कर रही है।
- (ढ) कोवेस्ट्रो चाइना के प्रेसीडेंट ने सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है कि पुडोंग की अत्यधिक दक्ष स्थानीय सरकार और कंपनियों को प्रदान की जाने वाली व्यापक सेवाओं से कोवेस्ट्रो को उस क्षेत्र में जाने में सहायता मिली है।
- (ण) यहां तक कि जब उत्पादन के कारकों के आवंटन की बात आती है, तब भी सरकार वित्त में पूरी तरह से हावी रहती है। यदि कोवेस्ट्रो चाइना ने चीनी बैंकों से किसी प्रकार का उधार लिया है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि किसी रूप में सरकार की मध्यस्थता है।
- (त) शीर्ष चीनी रासायनिक कंपनियों ने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है और अक्सर उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके लिए चीन आयात पर निर्भर था। चीन ने आयात पर निर्भरता कम करने की सरकार की नीति को उपयुक्त करने के लिए प्रयोक्ता उद्योगों के आसपास समर्पित रासायनिक पार्क बनाए हैं। रासायनिक उद्योग में अत्यधिक क्षमता का मुद्दा विशेष रूप से संगत है। चीन में अर्थव्यवस्था काफी हद तक सरकारी नियंत्रण के प्रभाव में है जो सरकार और चीनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा स्थापित इन औद्योगिक पार्कों से सिद्ध है।
- (थ) पेट्रोकेमिकल और रासायनिक उद्योग के लिए 13वीं पंचवर्षीय योजना (2016-2020) इस क्षेत्र द्वारा हासिल की जाने वाली वृद्धि और लाभप्रदता के लिए समग्र मात्रात्मक विकास लक्ष्यों को परिभाषित करती है। यह उत्पादन क्षमता पर सरकार का नियंत्रण भी लगाती है जहाँ वह इसे अधिक मानती है। यह योजना विदेशों में बिक्री के माध्यम से अधिक क्षमता के स्तर को पुनर्संतुलित करने के लक्ष्य की भी पुष्टि करती है। यह विदेशी बाजारों में आपूर्ति/मांग के प्रबंधन को और प्रभावित करती है। शंघाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट गाइड योजना का उल्लेख करती है और गर्व से 'जर्मनी के कोवेस्ट्रो' के मामले का भी हवाला देती है। इससे पता चलता है कि कोवेस्ट्रो ने सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभ प्राप्त किए।
- (द) इस योजना में ऊपर उल्लिखित लक्ष्यों को लागू करने के लिए व्यापार उपचार नियमावली के उपयोग का भी प्रावधान है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे विदेशों में ऐसी कॉर्पोरेट गतिविधि में मध्यस्थता और समर्थन करेंगे।
- (ध) रासायनिक योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए चीन द्वारा उपयोग किए जाने वाले कर प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अलावा, 17% तक के मूल्य वर्धित कर (वैट) पर छूट की एक योजना कुछ रसायनों के निर्यातों और आयातों तथा पुनः निर्यात के लिए परिष्कृत सामानों के विनिर्माण हेतु आयात की जाने वाली कुछ कच्ची सामग्री के लिए उपलब्ध कराई गई है। चीनी अधिकारी औद्योगिक नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैट छूट स्तरों को समायोजित करते हैं।
- (न) कोवेस्ट्रो चाइना के प्रेसीडेंट ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया कि चीन में प्राकृतिक गैस की कीमतें चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। कोवेस्ट्रो ने प्राकृतिक गैस को ऐसी कीमत पर खरीदा है जो बाजार कीमत पर नहीं है और प्राकृतिक गैस का हिस्सा टीडीआई के उत्पादन की कुल लागत में महत्वपूर्ण है और इसलिए, प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से उत्पादक द्वारा दावा की गई लागत को स्वीकार नहीं कर सकता है।
- (प) यूरोपीय आयोग द्वारा तय किए गए एल्युमिनियम कन्वर्टर फॉयल और एल्युमिनियम एक्सट्रूजन के मामले में अन्य प्राधिकारियों द्वारा कई पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी कार्यवाहियों में बाजार की विकृति पाई गई है। यूएसडीओसी ने विस्तृत अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि चीन जन. गण. एक बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हुआ है और एनएमई सिद्धांतों के तहत प्रचालन करना जारी रखता है।
- (फ) यहां तक कि भारतीय प्राधिकारी ने भी विद्युत इंसुलेटर और पैरा नाइट्रो एनिलिन (पीएनए) की पाटनरोधी जांच जैसी विभिन्न जांचों में एमईटी के दावों को स्वीकार नहीं किया है।

- (व) अधिनियम की धारा 9क(ख) के अनुसार, जहां संबद्ध देश में उत्पादक और भारत में संबंधित कंपनी के बीच सहयोग के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है जिस पर आयातित वस्तुएं किसी स्वतंत्र क्रेता को पहले फिर से बेची जाती हैं।
- (भ) वीएएसएफ ने उत्तर में उल्लेख किया है कि उसने भारत को अपना सारा निर्यात संबंधित ग्राहकों वीएएसएफ इंडिया लिमिटेड को किया है। तथापि, आवेदक की बाजार सूचना के अनुसार, वीएएसएफ इंडिया की संबद्ध कंपनी रिकॉर्ड में आयातक नहीं है। या तो आयात आंकड़ों में आयात की महत्वपूर्ण मात्रा की सूचना नहीं दी जाती है या संबंधित कंपनी केवल भारत में एजेंसी सेवाएं प्रदान कर रही है।
- (म) हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन की भारत में एक संबंधित कंपनी है जिसका नाम हनवा केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो सभी प्रकार के रासायनिक उत्पादों के विपणन और वितरण सेवाओं में लगी हुई है और इन उत्पादों की बिक्री के लिए एजेंसी व्यापार करती है। प्रदान की जाने वाली सेवाएं एजेंसी सेवाओं की प्रकृति की होती हैं जिन्हें कमीशन के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है।
- (य) उत्तरदाता उत्पादकों को उनके द्वारा दावा किए गए प्रत्येक समायोजन को स्पष्ट करना अपेक्षित था ताकि एक उचित तुलना की जा सके। तथापि, किसी भी उत्पादक ने दावा किए गए समायोजन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
- (कक) आयात मूल्य में गिरावट कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट से कहीं अधिक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशी उत्पादकों को अधिक आपूर्ति का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने सामानों का वैश्विक बाजार में पाटन करना शुरू कर दिया।
- (खख) व्यापार पत्रिका में प्रकाशित कीमतों से आयात कीमत की तुलना पर भारत में आयात कीमत प्रकाशित कीमतों से भी कम है।

छ.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

39. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

40. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और उनके आयातकों ने अपने संबद्ध निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

- (क) कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड और कोवेस्ट्रो (शंघाई) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कोवेस्ट्रो पॉलिमर (चीन) कंपनी लिमिटेड
- (ख) वन्हुआ केमिकल (सिंगापुर, पीटीई लिमिटेड, वानहुआ केमिकल फुज़ियान कं, लिमिटेड, वानहुआ केमिकल (यांताई) सेल्स कं, लिमिटेड, वानहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं, लिमिटेड के साथ वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड और वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- (ग) वीएएसएफ कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य और वीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
- (घ) एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, आईएमएस कॉर्पोरेशन और पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन।
- (ङ) सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क. चीन जन. गण.

41. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

42. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

43. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के तहत सामान्य मूल्य के परिकलन से संबंधित निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं। जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य नहीं दर्शाती है।"
- (2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।
- (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाए गए विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है। खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसंपत्तियों के ह्रास अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्म के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।
- (4) तथापि, उप पैरा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांचों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

कोवेस्ट्रो पॉलिमर (चीन) कंपनी लिमिटेड, कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड, कोवेस्ट्रो (शंघाई) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और कोवेस्ट्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड

एमईटी विश्लेषण

44. कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स (चीन) कंपनी लिमिटेड ने यह उल्लेख करते हुए एमईटी स्तर का दावा किया है कि टीडीआई पारदर्शी बाजार होने के नाते उत्पादक कोवेस्ट्रो को एमईटी प्रदान किया जाना चाहिए। कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स ने एमईटी प्रश्नावली दायर की है और चीन जन गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई टेनसिटी पॉलिएस्टर यार्न की पाटनरोधी जांच का हवाला दिया है, जिसमें उत्पादक ह्योसुंग केमिकल फाइबर को कोरिया में स्थित मूल द्वारा कंपनी के सीधे नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ कच्ची सामग्री की कीमत को बनाना, और बाजार प्रतिस्पर्धी कीमत पर यूटिलिटियों की बातचीत की दर के आधार पर एमईटी का स्तर दिया गया था।

45. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पादक को तब बाजार अर्थव्यवस्था स्तर दिया जाता है, यदि उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम हो कि भूमि की खरीद, कच्ची सामग्री और यूटिलिटीयों का संधरण, और परियोजना का वित्तपोषण सरकार के किसी किसी हस्तक्षेप के बिना बाजार कीमत पर किया जाए।
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया में स्थित मूल कंपनी द्वारा कंपनी के सीधे नियंत्रण, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ कच्ची सामग्री की कीमत को बनाए रखने, और बाजार प्रतिस्पर्धी कीमत पर यूटिलिटीयों की बातचीत की दर के आधार पर कोवेस्ट्रो द्वारा उल्लिखित अंतिम जांच परिणाम में ह्योसुंग केमिकल फाइबर को एमईटी के दावे स्वीकार किए गए थे। वर्तमान मामले में, कोवेस्ट्रो ने तर्क दिया है कि यह मानते हुए कि कोवेस्ट्रो चाइना को मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कच्ची सामग्री की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुरूप हैं और कोवेस्ट्रो चाइना अवमूल्यन में नहीं है अथवा चीन में किसी भी कानून से छूट प्राप्त नहीं है। कोवेस्ट्रो चाइना ने एमईटी के दावे को सिद्ध करने के लिए शंघाई में स्थानीय प्राधिकारी के साथ भूमि उपयोग अधिकार करार भी प्रस्तुत किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि टीडीआई के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कोवेस्ट्रो चाइना को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा की जाती है, जबकि चीन में प्राकृतिक गैस की कीमत संबंधित सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा नियंत्रित होती है।
47. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में उन मानदंडों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर प्राधिकारी को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के दावों का निर्धारण करते समय विचार करना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- "(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या:
- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और इनपुट, प्रौद्योगिकी और श्रम लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में उस देश में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति और मांग दर्शाने वाले बाजार संकेतों के उत्तर में और इस संबंध में बिना किसी महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के किए जाते हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हैं, के आधार पर किए जाते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे ली गई विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं;
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है।
48. वर्तमान मामले में, कोवेस्ट्रो भूमि प्रयोग अधिकारों के आवंटन, चीन जन. गण. में सरकारी प्राधिकारी द्वारा टीडीआई के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री की लागत पर नियंत्रण, उत्पादन में किए गए श्रम लागत, और उपभोग की गई यूटिलिटीयों के कीमत निर्धारण सहित संगत सूचना प्रदान करने में विफल रहा है, जिसकी एमईटी स्तर के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसकी अपेक्षा, कोवेस्ट्रो ने स्वीकार किया है कि, टीडीआई के उत्पादन के लिए टॉलुइन, कच्ची सामग्री की कीमत, चीनी सरकार अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों द्वारा विनियमित की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों द्वारा कोवेस्ट्रो को प्राकृतिक गैस जैसी यूटिलिटी की आपूर्ति भी की जाती है। अतः, प्राधिकारी अपेक्षित सूचना, जो उनके एमईटी के दावे को सिद्ध करे, साझा करने में विफलता के कारण कोवेस्ट्रो पॉलिमर द्वारा किए गए एमईटी के दावे को रद्द करते हैं।

सामान्य मूल्य

49. चूंकि मेसर्स कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स (चाइना) कंपनी लिमिटेड का एमईटी दावा खारिज कर दिया गया है और चीन पीआर के किसी अन्य उत्पादक ने अपने स्वयं के डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, सामान्य मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ जो निम्नानुसार है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत या जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया गया है। संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश को नामित प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से चुना जाएगा, और उस समय उपलब्ध कराई

गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित हिसाब लिया जाएगा। चयन का। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के मामले में की गई जांच का लेखा भी, जहां उपयुक्त हो, समय सीमा के भीतर लिया जाएगा। जांच के लिए पार्टियों को बिना किसी अनुचित देरी के बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियों की पेशकश करने के लिए उचित समय दिया जाएगा।

50. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रदान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, या जहां यह संभव नहीं है, किसी भी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है।
51. प्राधिकरण शेनयांग मस्तसुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 617112003 दिनांक 2312/2005), मैसर्स सेंचुरी प्लाईवोर्ड्स (आई) लिमिटेड और अन्य-बनाम- भारत संघ और तूर में गुवाहाटी उच्च न्यायालय। (डब्ल्यू.पी. 6568/2017 दिनांक 411012018) और सेस्टेट, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली इन अपोलो टायर्स लिमिटेड, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (अपील संख्या C1768,600,601,773,769/2005- एडी-दिनांक 91912005), कुइटुन जिंजियांगो रासायनिक उद्योग कंपनी लिमिटेड. बनाम भारत संघ (2019 की अपील संख्या 52291 दिनांक 5 अगस्त 2020)। ये निर्णय एडी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में एक उपयुक्त विकल्प के चुनाव और उससे जुड़े दायित्वों के संबंध में निर्देश प्रदान करते हैं।
52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद के मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात कीमतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रासंगिक जानकारी न तो आवेदक या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।
53. तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया जाता है, जिसमें उचित लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाता है।

निर्यात कीमत

54. कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स (चीन) कंपनी लिमिटेड ("कोवेस्ट्रो चाइना") चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है। कोवेस्ट्रो चाइना का एक संबद्ध निर्यातक अर्थात् कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड ("कोवेस्ट्रो हांगकांग") है, घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री में शामिल एक संबद्ध कंपनी, अर्थात् कोवेस्ट्रो (शंघाई) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ("कोवेस्ट्रो शंघाई") और संबद्ध आयातक अर्थात्, कोवेस्ट्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड ("कोवेस्ट्रो इंडिया") है। इन सभी कंपनियों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और निर्धारित प्रारूप में प्राधिकारी को संगत ब्यौरे दिए हैं।
55. कोवेस्ट्रो चाइना ने भारत में संबद्ध आयातक को और अपने संबद्ध निर्यातक कोवेस्ट्रो हांगकांग के माध्यम से भी संबद्ध सामानों का सीधे निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, कोवेस्ट्रो चाइना ने कोवेस्ट्रो इंडिया को सीधे 670 मी. टन संबद्ध सामानों का उत्पादन और निर्यात किया है तथा भारत में संबद्ध और असंबद्ध ग्राहकों को कोवेस्ट्रो हांगकांग के माध्यम से 5,672 मी. टन संबद्ध सामान का निर्यात किया है। कोवेस्ट्रो इंडिया ने मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए संबद्ध सामानों की खपत की है और भारत में असंबद्ध ग्राहकों को कुछ मात्रा में संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री भी की है। कोवेस्ट्रो चाइना ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों तथा ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है।
56. प्राधिकारी द्वारा समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों तथा ऋण लागत के समायोजन को सत्यापित और स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी ने भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात के संबंध में कोवेस्ट्रो हांगकांग की लाभप्रदता की जांच की है और यह नोट किया गया है कि कोवेस्ट्रो हांगकांग भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात पर लाभ कमा रहा है। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री के संबंध में कोवेस्ट्रो इंडिया की लाभप्रदता की भी जांच की है और यह नोट किया गया है कि कोवेस्ट्रो इंडिया भारत में संबद्ध सामानों की पुनः बिक्री पर लाभ कमा रही है। तदनुसार,

इस समूह के लिए कारखानागत पर संबद्ध सामानों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड (उत्पादक) और वानहुआ केमिकल (सिंगापुर-पीटीई लिमिटेड (निर्यातक)

सामान्य मूल्य

57. उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः, सामान्य मूल्य ऊपर वर्णित पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

58. जैसा कि नोट किया गया है, वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड (उत्पादक) और वानहुआ केमिकल (सिंगापुर-पीटीई लिमिटेड (निर्यातक) द्वारा भारत में अपने संबद्ध आयातक, अर्थात् वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सहित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है। उन्होंने चीन में अन्य तीन संबद्ध कंपनी अर्थात् वानहुआ केमिकल फुज़ियान कं, लिमिटेड, संबंधित निर्माता, वानहुआ केमिकल (यांताई) सेल्स कं, लिमिटेड, घरेलू बाजार में संबद्ध व्यापारी, वानहुआ केमिकल (निंगबो) ट्रेडिंग कं, लिमिटेड, रिलेटर ट्रेडर की निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर भी दायर किए हैं। तथापि, ये तीन कंपनियां भारत को बिक्री में शामिल नहीं हैं अतः इन तीन कंपनियों के लिए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों पर निवल निर्यात कीमत के परिकलन के लिए विचार नहीं किया गया है।
59. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को संबद्ध निर्यातक अर्थात् वानहुआ केमिकल (सिंगापुर-पीटीई लिमिटेड) द्वारा किया गया है। निर्यातक द्वारा बिक्री संबद्ध आयातक वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड तथा भारत में असंबद्ध ग्राहकों, दोनों को है। उत्तर से यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, वानहुआ ने *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, जिसमें से 1,300 मी. टन असंबद्ध ग्राहकों को बेचा जाता है और शेष *** मी. टन संबद्ध आयातक को।
60. निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय परिवहन के निमित्त समायोजन का दावा किया है और जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।
61. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातक मैसर्स वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान *** मी. टन संबद्ध सामान को घाटे पर बेचा है। संबद्ध आयातक मैसर्स वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की सतत प्रवृत्ति उच्चतर कीमत पर संबद्ध सामानों का आयात करने और कमतर कीमत पर भारतीय बाजार में उसकी बिक्री करने और हानियां उठाने की है। अन्य की तुलना में अधिक कीमत पर सतत आयात करने को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी ने हानि को निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य दोनों में समायोजित किया है।
62. तदनुसार, समूह के लिए कारखानागत पर निवल निर्यात कीमत का परिकलन किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

अन्य उत्पादक

निवल निर्यात कीमत का निर्धारण

63. चीन जन. गण के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. कोरिया गणराज्य

बीएसएसएफ कंपनी लिमिटेड, कोरिया

सामान्य मूल्य

64. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएसएसएफ कंपनी (जिसे यहां आगे "बीएसएसएफ/निर्यातक" कहा गया है) संबद्ध सामानों का उत्पादक है। निर्यातक ने भारतीय बाजार में अपनी संबद्ध कंपनी बीएसएसएफ इंडिया लिमिटेड को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है जिसने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।
65. बीएसएसएफ ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी. टन संबद्ध सामान की बिक्री की है जबकि उसने भारत को *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या उनकी बिक्री पाटनरोधी नियमावली के

अनुबंध-I के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की जाती है। भारत में निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद लेन-देन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और जिन मामलों में, लाभप्रद लेनदेन 80% से कम हैं, उनमें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में चूंकि केवल ***% घरेलू बिक्री लाभप्रद है अतः सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

66. यह नोट किया जाता है कि बीएएसएफ ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया। प्राधिकारी ने निर्यातक और बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड के उत्तरों का सत्यापन किया है। बीएएसएफ ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह शुल्क, पैकिंग लागत और ऋण लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।
67. उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उत्पादक/निर्यातक ने भारत में ग्राहकों को अपनी संबद्ध कंपनी अर्थात् मैसर्स बीएएसएफ इंडिया के माध्यम से भारत को *** मी. टन निर्यात किया है। संबद्ध आयातक द्वारा दायर किए गए उत्तर से यह देखा गया है कि आयातक द्वारा की गई बिक्री लाभ दर्शाती है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन किया जाता है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में इसका उल्लेख किया गया है।

मैसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, मैसर्स एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, मैसर्स आईएमएस कॉर्पोरेशन और मैसर्स पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

सामान्य मूल्य

68. जांच की अवधि के दौरान, हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने घरेलू बाजार में *** मी. टन संबद्ध सामानों की बिक्री केवल असंबद्ध पक्षकारों को की है। भारत को निर्यात के साथ तुलना करने पर घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेन का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद लेन-देन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और जिन मामलों में, लाभप्रद लेनदेन 80% से कम हैं, उनमें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में चूंकि केवल ***% घरेलू बिक्री लाभप्रद है अतः सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है।
69. हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, पैकिंग व्यय और ऋण लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

70. जांच की अवधि के दौरान, हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने तीन असंबद्ध व्यापारियों अर्थात् एवरलाइट कोरिया कंपनी लिमिटेड, आईएमएस कॉर्पोरेशन और पीपी एंड वाई इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के माध्यम से भारत को बीजक मूल्य *** अमे. डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामान को अप्रत्यक्ष रूप से बेचा है।
71. हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने अंतर्देशीय परिवहन, घरेलू सार-संभाल प्रभार, ऋण लागत, बैंक प्रभार और पैकिंग व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत पर निर्यात कीमत निर्धारित की है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

अन्य उत्पादक

72. कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित मूल्यों का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ग. जापान

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार परिकलित मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.4.3 पाटन मार्जिन

74. ऊपर दिए गए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, पाटन मार्जिन का परिकलन किया जाता है और नीचे दर्शाया गया है। यह देखा जाता है कि मैसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन को छोड़कर और जापान से निर्यात के लिए सभी उत्तरदाता उत्पादकों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

क्रम सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		अमे.कि./डॉ. .ग्रा	अमे.कि./डॉ. .ग्रा	अमे.कि./डॉ. .ग्रा	%	%
क	चीन जन.गण .					
1	कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स चाइना कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2	वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
3	अन्य कोई उत्पादक	***	***	***	***	30-40
ख	कोरिया गणराज्य					
1	बीएसएसएफ लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	Negative
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70
ग	जापान					
1	कोई भी	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**ज1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

75. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- क. यदि क्षति और संभावित विश्लेषण से अप्रैल-जून, 2020 की तिमाही छोड़ दी जाती है, तो यह जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पर्याप्त सुधार को दर्शाएगा।
- ख. शुल्क लगाने से पूर्व भी चीन जन.गणराज्य से आयात बहुत अधिक नहीं रहे हैं और मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने के दृष्टिगत क्षेत्र में यह 5000 से 11000 मी.ट. तक रहा।
- ग. आवेदक 96% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है। आधार वर्ष की काफी समय अवधि बिना किसी आर्थिक कार्यकलाप की थी, उसकी तुलना में 4 प्वाइंट की गिरावट होना आवेदक की अत्यधिक वृद्धि को दर्शाती है।
- घ. वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का बाजार हिस्सा 66% तक बढ़ गया है। आवेदक के बाजार हिस्से में 3% की बढ़ोतरी हुई और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में 49% तक गिरावट आयी है।
- ड. उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में कोई गिरावट नहीं हुई तथा सामान सूची में पर्याप्त गिरावट हुई है।

- च. आवेदक की घरेलू विक्रियों में बढ़ोत्तरी हुई है। विक्रियों में किसी प्रकार की गिरावट होने का कारण मांग में कमी होना है।
- छ. आवेदक को आधार वर्ष में असाधारण रूप में अधिक लाभ हुआ था तथा आधार वर्ष के लाभों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है।
- ज. आवेदक के निष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि आयातों पर शुल्क लगाए जाने से वर्ष 2019-20 में उसे हानियां हो रही थीं तथा जांच अवधि में लाभ कमाना शुरू कर दिया है।
- झ. इन मापदंडों के निष्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागतों की वजह से हुई है जो क्षति अवधि में दुगुनी हो गई हैं।
- ञ. 400 सिरीज की स्टेनलैश स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के बारे में रक्षोपाय जांच में प्राधिकारी ने निर्णय किया कि अधिक मूल्यह्रास और वित्तीय प्रभार हानियों के लिए उत्तरदायी थे जिसकी वजह से कारणात्मक संबंध समाम हो गए।
- ट. अत्यधिक कैप्टिव खपत की वजह से कुल विक्रियों में गिरावट हुई है, जो जांच अवधि के दौरान 100 से 1259 तक 13 गुना से अधिक बढ़ गई है।
- ठ. निर्यात प्रचालन और घरेलू प्रचालनों के लिए आवेदक की विक्रय लागत जांच अवधि के दौरान अनुपातहीन है।
- ड. आवेदक की निवल स्थिर परिसंपत्तियां, चल पूंजी तथा नियोजित पूंजी में क्षमता में संगत बढ़ोत्तरी किए बिना बढ़ोत्तरी हुई है।
- ढ. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसने जांच अवधि में अत्यधिक अच्छा कार्य किया है तथा टीडीआई संयंत्र में हमेशा सबसे अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त किया गया।
- ण. मापदंडों की मासिक तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पीओआई के अगले 7 महीनों में कच्चे माल की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं है, जबकि कोविड-2019 की वजह से पीओआई लॉकडाउन की अवधि थी। इसके अलावा, मासिक आधार पर पूर्वोक्त मापदंडों की जांच करने के लिए यह प्राधिकारी का सुसंगत कार्य नहीं है।
मासिक आधार पर ऐसे आंकड़ों की जांच, संपूर्ण पीओआई के लिए पूर्वोक्त मापदंडों की सटीक तस्वीर नहीं देती है।
- त. आवेदक द्वारा किए गए मांग विश्लेषण में कोविड की अवधि को शामिल नहीं किया, अपितु अन्य मापदंडों के विश्लेषण में कोविड अवधि को छोड़ा नहीं गया था। प्राधिकारी से कोविड अवधि सहित और इसके बिना सूचना का विश्लेषण करने का अनुरोध है।
- थ. घरेलू उद्योग को क्षति होने के कई कारण थे जैसे कोविड, अन्य देशों से आयात, बंदी, जापान से आयात, मांग में कमी, तथा अन्य आंतरिक अक्षमताएं। याचिकाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि पीओआई के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन से उसके आर्थिक निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के बावजूद याचिकाकर्ता का आर्थिक निष्पादन अच्छा रहा है।
- द. इस अवधि के दौरान क्षति से संबंधित याचिकाकर्ता के अनुरोध ठीक नहीं है।
- ध. जांच अवधि के दौरान जीएनएफसी द्वारा टीडीआई संयंत्र के बंद रखने की अवधि के दिनों की संख्या का रिकार्ड भी प्राधिकारी द्वारा मांगना चाहिए।
- न. कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण संबंधी कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करता रहा है।
- प. घरेलू बाजार की प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से इसने निर्यात किया, इस अनुरोध के प्रतिकूल आवेदक ने वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया है कि आयातों की वजह वैश्विक बाजार में उसका प्रमुख स्थान होना है।
- फ. कीमतों में सकारात्मक कटौती करने का कारण यह नहीं है कि पाटित कीमतों पर आयात किए गए हैं, अपितु एकाधिकार की स्थिति में कीमत का निर्धारण करने के तहत आवेदक द्वारा अधिक कीमतें लेना है।
- ब. कोरिया जन.गण. से आयातों को संचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनमें तेजी से गिरावट हो जाती है।

- भ. जापान के निर्यातकों ने पुरानी संविदाओं को ध्यान में रखते हुए उनके नीति-विषयक मानकों एवं वचनबद्धता की वजह से कम कीमत पर कुछ मात्रा का निर्यात किया था जिसके लिए कीमतें अधिक होने के बावजूद आपूर्ति में विलंब हुआ था। इसे अधिक कीमत कटौती के रूप में नहीं मानना चाहिए।
- म. मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि आधार वर्ष से जांच अवधि तक आयातों में काफी एवं निरंतर गिरावट हुई। जांच अवधि में आयातों में बढ़ोतरी केवल लॉकडाउन के दौरान घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति के अंतर को समाप्त करने के लिए की गई है।
- य. कीमत पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि जब कीमत में कटौती सुनिश्चित हुई तब पहुंच-मूल्य में 30% की बढ़ोतरी करना यह दर्शाता है कि आवेदक ने कीमत में कटौती को दर्शाने के लिए अपने घरेलू विक्रय मूल्यों को प्रतिबंधित किया।
- कक. निवेश पर लाभ में गिरावट होने के कारण क्षति अवधि में नियोजित पूंजी में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी करना है।
- खख. सामान सूची में बढ़ोतरी के बारे में घरेलू विक्रियों में बढ़ोतरी के संदर्भ में देखना होगा। सामान-सूची में अलग-से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- गग. यद्यपि पीओआई के बाद उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आयी है, परंतु घरेलू विक्रियों में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के लिए निर्यात विक्रियों में काफी गिरावट आयी है। घरेलू विक्रियों अथवा निर्यात विक्रियों के लिए यथा निर्दिष्ट उत्पादन अलग-अलग न होने की वजह से प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि निर्यात विक्रियों में कमी होने से उत्पादन और क्षमता उपयोग में कमी हुई है।
- घघ. वर्ष 2018-19 और 2019-20 में आयातों की मात्रा में कमी हुई। तथापि लाभप्रदता के मापदंडों में सुधार होने के बजाए उनमें काफी गिरावट हुई। जब आयातों में हल्की-सी बढ़ोतरी हुई, तब लाभप्रदता के मापदंडों में बढ़ोतरी हुई। यही बात कीमत में कटौती के लिए भी देखी गई है।
- डड. विक्रय मूल्य में गिरावट होने के बारे में प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के आंकड़ों की भी जांच करनी चाहिए, जो विचाराधीन उत्पाद की कीमत संबंधी प्रवृत्ति के बारे में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना के प्रतिकूल है।
- चच. याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में गिरावट का कारण विक्रियों की लागत में बढ़ोतरी होना है, जबकि पीओआई से पीओआई के बाद विक्री की लागत में 30 सूचकांकों की अत्यधिक बढ़ोतरी हुई थी।
- छछ. याचिकाकर्ता ने अपना बाजार हिस्सा 50-55% के रूप में गलत बताया है, जो अपेक्षाकृत 66% है। संबद्ध आयातों से प्रतिस्पर्धा होने की वजह से याचिकाकर्ता को निर्यात करने के लिए बाध्य होने का दावा गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता की निर्यात विक्रियों में वस्तुतः क्षति अवधि में गिरावट हुई है।
- जज. आवेदक ने यह दावा किया कि उसकी वसूली 22% से कम है। क्षति रहित कीमत के लिए 22% लाभ होना वसूली के लिए कोई गारंटी नहीं है जैसा कि ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सीईएस टीएटी द्वारा निर्णय दिया गया था।
- झझ. आरओसीई के लिए दावा गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता ने निर्यात विक्रियों के लिए भी वित्तीय निष्पादन को शामिल करके आरओसीई की गणना की है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता को घरेलू प्रचालनों के लिए ही आरओसीई के निष्पादन को दर्शाना चाहिए।
- ञञ. कोविड महामारी की वजह से वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में देरी हुई।
- टट. मौखिक सुनवाई के दौरान, आवेदक ने अपनी क्षमता लगभग 87,000 मी.ट. पीए का दावा किया था लेकिन उसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह 64,000 एमटीपीए है और उसकी वेबसाइट में यह 67,000 एमटीपीए होने का दावा करता है।
- ठठ. आवेदक की उत्पादन सुविधाएं पश्चिमी दिशा में अवस्थित हैं जिससे पूर्वी एवं सुदूर दक्षिणी ग्राहकों के लिए आपूर्ति करने की व्यवस्था कठिन हो रही है। एकमात्र उत्पादक पर निर्भर रहने के बजाए पत्तनों से आयात करना अधिक व्यावहारिक है।

- डड. आवेदक ने ईपीसीजी के तहत निर्यात इकरार-नामा कि है जिसके बारे में उसकी वार्षिक रिपोर्ट से पुष्टि होती है, रिपोर्ट यह बताती है कि ईओयू और एसईजैड के लिए समझी गई निर्यात स्कीमों के तहत पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया गया।
- ढढ. आवेदन के पैरा 70 और फार्मेट IV क-II के तहत आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े भ्रामक एवं परस्पर-विरोधी हैं। इसी प्रकार, पैरा 58 और पैरा 66 में घरेलू बिक्रियां और मांग के लिए दिए सूचीबद्ध आंकड़े एक-दूसरे के परस्पर-विरोधी हैं, जिससे आंकड़े अविश्वसनीय हो जाते हैं।
- णण. इस दावा में किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में यद्यपि गिरावट हुई है, परंतु उनकी मात्रा काफी परोक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी रही है।

ज2. उद्योग द्वारा अनुरोध घरेलू

76. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- i. जांच अवधि के दौरान निष्पादन तीन कारकों से प्रभावित हुआ है ये कारक हैं— (क) कोविड-19, (ख) संबद्ध देशों से पाटित आयात और (ग) भारत में पाटन के लिए आश्रय वाले अन्य देशों से आयात।
- ii. कोविड-19 महामारी की वजह से वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच अवधि में मांग में गिरावट हुई है।
- iii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में यद्यपि गिरावट हुई है, परंतु उनकी मात्रा काफी परोक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी रही है।
- iv. चाहे मात्रा की आगे बढ़ोतरी न हो, परंतु यह मात्रा, आवेदक को क्षति पहुंचाने के लिए स्वभावतः पर्याप्त है।
- v. संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय-मूल्य से कम था। इसलिए, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी।
- vi. आयातों की कीमतों में पर्याप्त घट-बढ़ होने की वजह से प्राधिकारी से महीनेवार कीमत कटौती की गणना करने के लिए अनुरोध किया जाता है।
- vii. एडीडी का बचाव करने सहित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हो रहा था।
- viii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान नहीं है और यह देश में मांग से अधिक है।
- ix. आवेदक के पास 50-55% बाजार हिस्सा है और अवांछित तथा कम लाभकारी निर्यात करने के लिए बाध्य है।
- x. जांच अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा घरेलू बिक्रियों में गिरावट हुई, जबकि आयातों में बढ़ोतरी हुई।
- xi. आवेदक, देश में संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता है, लेकिन इसका बाजार हिस्सा काफी कम है।
- xii. जिस देशों पर शुल्क लगाया है, ऐसे अन्य देशों से आयातों की वजह पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20 में आवेदक को हानियां हुई थी। जबकि जांच में निष्पादन में सुधार हुआ है, परंतु वर्तमान लाभ बहुत कम हैं।
- xiii. किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा अर्जित वर्तमान लाभ काफी कम है।
- xiv. जांच अवधि के अंत में आवेदक पड़ी अन्तः सामान-सूचियों का मूल्य *** रुपए से काफी ज्यादा था।
- xv. पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की सामर्थ्य कम हो गई है। विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं अधिक पूंजी वाली हैं।
- xvi. क्षति अवधि के दौरान पाटन अधिक हो गया है। चीन जन.गण. को छोड़कर, पाटन मार्जिन पर शुल्क की सिफारिश की गई थी। यह इस बात को दर्शाता है कि चीन जन.गण. को छोड़कर मूल जांच में पाटन मार्जिन क्षति मार्जिन से कम था।
- xvii. चाहे आयातों की मात्रा में स्वभावतः बढ़ोतरी न होती हो, पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए वर्तमान मात्रा पर्याप्त है।
- xviii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच अवधि के बाद और अधिक विकृत हो गया और वह केवल संबद्ध देशों से हुए आयातों के वजह से हुआ।

- xix. प्राधिकारी से विभिन्न संगत मापदंडों के लॉकडाउन एवं अन-लॉकडाउन की अवधि के लिए उचित समायोजन करने तथा सभी हितवद्ध पक्षकारों के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध है।
- xx. उत्पादन लागत में कोई वस्तुपरक अक्षमता नहीं। आवेदक का दाहेज संयंत्र एक नया संयंत्र है, जबकि पुराना संयंत्र, भरूच संयंत्र पूरी तरह से मूल्यह्रासित है। जांच अवधि के दौरान अक्षमता की वजह से एक दिन के लिए भी बंदी नहीं हुई है।
- xxi. कैप्टिव खपत टीडीआई- एमडीआई सम्मिश्रण के लिए होती है, जिसको बाजार में आगे दुबारा से बेचा गया था।
- xxii. नए संयंत्र के बारे में आवेदक का निर्यात इकरार-नामा प्रस्तुत करने पर जांच अवधि के दौरान आवेदक के लिए कोई निर्यात इकरार-नामा नहीं है। आवेदक का निर्यात इकरार-नामा पूर्ववर्ती वर्षों में पूरा किया गया था।
- xxiii. यदि निर्यात लाभों पर भी विचार किया जाता है, तो आवेदक द्वारा अर्जित लाभ काफी कम है।
- xxiv. आवेदक की कुल विक्रियों के बारे में विचार करते हुए उसके द्वारा अर्जित लाभ, बैंक की ब्याज के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है।
- xxv. प्राधिकारी कृपया सभी हितवद्ध पक्षकारों के लिए विभिन्न संगत मापदंडों के लॉकडाउन एवं अन-लॉकडाउन की अवधि के लिए उचित समायोजन कर सकते हैं।
- xxvi. 48% तक अधिक उत्पादन का घरेलू कीमतों से कम वस्तुपरक कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया गया था। देश में उपभोक्ताओं ने कम कीमत के पाटित आयातों को वरीयता दी है।
- xxvii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों में उसके प्रतिकूल निष्पादन के लिए देश में उत्पाद का पाटन उत्तरदायी है।
- xxviii. घरेलू और निर्यात प्रचालनों की कीमत में पर्याप्त अंतर प्रस्तुत करने पर घरेलू और निर्यातों की उत्पादन की लागत में कोई विशेष अंतर नहीं पाया है। यह अंतर दो संयंत्रों की उत्पादन लागत में होता है।
- xxix. आधार वर्ष में आवेदक के लाभ असाधारण थे तथा इनकी उपेक्षा कर दी जानी चाहिए, यह प्रस्तुत करने पर यह प्रमाण नहीं दिया गया है कि उसकी क्यों उपेक्षा करनी चाहिए। घरेलू उद्योग अपनी कीमतें आयात कीमत के बराबर रखता है। चूंकि आधार वर्ष में आयात कीमतें अधिक थीं, इसलिए आवेदक पर्याप्त कीमतें आकर्षित कर सका।
- xxx. दाहेज संयंत्र, चूंकि एक नया संयंत्र है, इसलिए इसकी लागत अधिक है और मूल्यह्रास एवं अन्य नियत व्यय की घटना अधिक होती है। भरूच संयंत्र, पुराना संयंत्र होने के कारण पूर्णरूपेण मूल्यह्रासित है।
- xxxi. जांच अवधि में, की गई कैप्टिव खपत मुश्किल से 100 मी.ट. की होती है तथा आवेदक द्वारा किए गए उत्पादन का 0.02% भी नहीं होती है तथा यह टीडीआई-एमडीआई सम्मिश्रण के लिए होती है और जिसे बाजार में आगे पुनः बेचा गया था।
- xxxii. आवेदक की निवल स्थिर परिसम्पत्तियों के बारे में बढ़ोतरी को प्रस्तुत करने पर निवल स्थिर परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आयी है। बढ़ोतरी का कारण घरेलू और निर्यात विक्रियों के बीच आवंटन तथा दोनों के अनुपात में बदलाव होना है।
- xxxiii. वार्षिक रिपोर्टों में विवरणों पर अन्य पक्षकारों के अनुरोध पर आवेदक ने वार्षिक रिपोर्टों में भी यह स्वीकार किया है कि उसके संयंत्र का कम उपयोग किया गया है। जिस अवधि में हानियां हो रही थीं, उस पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निष्पादन में सुधार हुआ है।

ज3. प्राधिकारी द्वारा जांच

77. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर

पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल विक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

78. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है तथा लिखित में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का स्वतः ही समाधान हो जाता है।
79. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने की कार्यवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षति की, यदि कोई हो, जांच की है।
80. पाटनरोधी प्रपत्र और वार्षिक रिपोर्टों में सूचित क्षमता में अंतर के बारे में अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी प्रपत्रों में क्षमता के बारे में प्रदूषण बोर्ड के नियंत्रण के अनुसार क्षमता के आधार पर विचार किया गया है तथा वार्षिक रिपोर्टों में क्षमता नेम-प्लेट क्षमता के अनुसार है। आवेदक के मासिक उत्पादन के विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि आवेदक, वास्तव में, नेम-प्लेट क्षमता से अधिक उत्पादन कर सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने अपनी समनुरूप प्रथा के अनुसार प्रदूषण बोर्ड प्रमाणपत्र में यथा उपलब्ध क्षमता पर विचार किया है।
81. कोविड की अवधि की वजह से हुई क्षति के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान वर्तमान क्षति की जांच अवधि के दौरान वर्तमान क्षति की जांच की गई है। अन्य कारक की वजह से हुई क्षति की, यदि कोई हो, कारणात्मक संबंध में जांच की गई है। किसी मामले में प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में संभावित जांच पर भी विचार किया है।
82. घरेलू और निर्यात प्रचालनों की विक्रय लागत तथा नियोजित पूंजी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति में पर्याप्त अंतर पर अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने प्रवृत्ति का औचित्य उपलब्ध कराया है जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। इस संबंध में यह नोट किया है कि यह अंतर दो संयंत्रों की उत्पादन लागत में होता है। उचित जांच के बाद उपलब्ध करायी गई सूचना के बारे में क्षति विश्लेषण हेतु प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
83. क्षति मापदंडों के मासिक विश्लेषण के मुद्दे का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार एनआईपी का परिकलन करने के लिए ठीक कर देने की पद्धति को अप्रैल 2020 से जून, 2021 के दौरान कोविड की वजह से संयंत्र की बंदी होने के कारण हुई किसी विकृति के लिए ध्यान में रखा गया है। अतः प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए ठीक कर दिए गए आंकड़ों के आधार पर क्षति विश्लेषण किया है क्योंकि कोविड के आंकड़ों को छोड़कर क्षति संबंधी मापदंडों का क्षति विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो क्षति अवधि से ठीक कर दिए गए आंकड़ों पर किया गया है।

ज.3.1 मांग का आकलन

84. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का एकमात्र भारतीय उत्पादक की घरेलू विक्रियों और समस्त संसाधनों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारण किया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे सारणी में दी है-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	आवेदक की विक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	121	110
2	संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	30,484	24,038	15,608	16,418
3	शुल्क आकर्षित करने वाले देशों से आयात	मी.ट.	1,190	7,235	18,976	15,890
4	अन्य देशों से आयात	मी.ट.	1,473	1,346	1,334	1,692
5	मांग	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	106

85. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन जांच अवधि के दौरान इसमें कमी आयी है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मांग में कमी कोविड-19 महामारी की वजह से हुई है। क्षति अवधि के दौरान समग्र मांग में बढ़ोतरी हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

संबद्ध देशों के आयात की मात्रा और हिस्सा

86. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव तथा अन्य देशों से आयातों के बारे में प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए अनुसार जांच की गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	संबद्ध देश-	मी.ट.	30,484	24,038	15,608	16,418
i	चीन जनगण.	मी.ट.	11,064	10,858	7,148	7,258
ii	जापान	मी.ट.	1,280	1,320	3,880	4,040
iii	कोरिया जन.गण.	मी.ट.	18,140	11,860	4,580	5,120
2	एडीडी आकर्षित करने वाले देशों से आयात	मी.ट.	1,190	7,235	18,976	15,890
3						
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	51	56
ख	मांगखपत/	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	45	51
ग	कुल निर्यात	%	91.97%	73.69%	43.45%	48.29%

87. यह देखा गया है कि:-

- क. शुल्क लगाने के बाद संबद्ध देशों से आयातों में वर्ष 2019-20 तक कमी आयी। जबकि संबद्ध देशों से आयातों में कमी हुई, परंतु पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले अन्य देशों से आयातों में बढ़ोतरी हुई।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों में जांच अवधि के दौरान दुबारा बढ़ोतरी हुई है। तथापि, आधार वर्षों की तुलना में आयात अभी मात्रा से कम है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले अन्य देशों से आयातों में शुल्क लगाने सहित जांच अवधि में कमी आयी है।
- घ. कुल उत्पादन और कुल आयातों के संबंध में आयातों में वर्ष 2019-20 तक कमी आयी है, लेकिन जांच अवधि में इनमें दुबारा बढ़ोतरी हुई।
- ड. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा जबकि आधार वर्ष की मात्रा से कम है, वे परोक्ष एवं सापेक्ष रूप से पर्याप्त हैं।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

88. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना होगा कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना कथित पाटित आयातों से कीमत में पर्याप्त रूप से कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा कम करना अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है, जो सामान्य रूप से हुई होंगी।
89. तदनुसार, प्राधिकारी ने कीमत कटौती अथवा कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के संदर्भ में, यदि कोई हो, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच की है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत और निवल विक्रय वसूली (एनएसआर) की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच-मूल्य के साथ तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

90. प्राधिकारी ने भारत में घरेलू उद्योग की निवल विक्री वसूली के साथ संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	निवल विक्री वसूली	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
2	समग्र रूप से विषय देश					
i	पहुंच मूल्य	रुपए.ट.मी/	2,39,412	2,20,464	1,17,746	1,53,103
ii	कीमत कटौती	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	(0-10)%	0-10%	10-20%
3	चीन जन.गण.					
i	पहुंच मूल्य	रुपए.ट.मी/	2,12,733	1,90,961	1,18,466	1,63,734
ii	कीमत कटौती	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज	30-40%	0-10%	0-10%	0-10%
4	जापान					
i	पहुंच मूल्य	रुपए.ट.मी/	2,48,219	2,48,925	1,13,413	1,30,068
ii	कीमत कटौती	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	(10-20)%	0-10%	30-40%
5	कोरिया जन.गण.					
i	पहुंच कीमत	रुपए.ट.मी/	2,55,063	2,44,305	1,20,295	1,56,210
ii	कीमत कटौती	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
iii	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
iv	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	(10-20)%	0-10%	10-20%

91. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों का पहुंच-मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय-मूल्य से कम था, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती की गई।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

92. क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा-न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को कम करने के लिए अथवा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है, जो काफी हद तक हुई होंगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों एवं कीमतों में परिवर्तनों का निर्धारण किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	विक्री की लागत	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	109	104
2	विक्रय-मूल्य	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	45	63
3	पहुंच मूल्य	रुपए.ट.मी/	2,39,412	2,20,464	1,17,746	1,53,103
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	49	64

93. यह देखा गया है कि आवेदक का विक्रय मूल्य वर्ष 2019-20 में विक्रयों की लागत से कम था और उसे हानियां हो रही थीं। यद्यपि विक्रय मूल्य और आयातों का पहुंच मूल्य में पीओआई तक आधार वर्ष से लगभग उतनी ही राशि की गिरावट हुई है, परंतु वर्ष 2018-19 को छोड़कर संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान विक्रय मूल्य आयातों के पहुंच मूल्य से अधिक रहा है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

94. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में विक्री, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ अथवा क्षमता का उपयोग, में वास्तविक और संभावित कमी सहित उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक कारकों तथा घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, सामान-सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों का वस्तुगत मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के विभिन्न मापदंडों के बारे में इसमें नीचे विचार-विमर्श किया है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू विक्रियां

95. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रयों की मात्रा के बारे में विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	101	96
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	101	96
4	घरेलू विक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	121	110
5	निर्यात विक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	86	75
6	मांग	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	106

96. यह देखा गया है कि-

क. घरेलू उद्योग की क्षमता जांच अवधि के दौरान स्थिर रही और देश में मांग से यह अधिक है।

- ख. आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2018-19 में बढ़ोतरी हुई, फिर वर्ष 2019-20 में सीमांत रूप से गिरावट आयी क्योंकि अन्य देशों से आयातों में बढ़ोतरी हुई थी। आवेदक का उत्पादन और क्षमता उपयोग जांच अवधि के दौरान और गिरावट हुई है।
- ग. आवेदक की घरेलू विक्रियों में वर्ष 2019-20 तक बढ़ोतरी हुई लेकिन जांच अवधि के दौरान गिरावट हुई है। घरेलू विक्रियों में गिरावट वस्तुओं की मांग में गिरावट की अपेक्षा अधिक है।
- घ. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू विक्रियों में गिरावट हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग को निर्यात के प्रयोजन के लिए उत्पादन के काफी हिस्से का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिसका इसके बजाए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए था।

ख. बाजार हिस्सा

97. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निम्नानुसार जांच की है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	आवेदक का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	106	103
2	संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	45	51
3	एडीडी आकर्षित करने वाले देशों से आयातों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	557	1,388	1,255
4	अन्य देशों से आयातों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	79	108

98. यह देखा गया है कि-

- क. आवेदक के बाजार हिस्से में वर्ष 2018-19 में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वर्ष 2019-20 की अवधि में इसमें गिरावट हुई क्योंकि अन्य देशों से आयातों में बढ़ोतरी हुई। आवेदक के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान और गिरावट आयी है।
- ख. आवेदक देश में संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता है, लेकिन इस पर क्षति अवधि में लगभग 50-55% बाजार हिस्सा डाल दिया गया है।
- ग. शुल्क आकर्षित करने वाले अन्य देशों से आयातों में वर्ष 2019-20 तक बढ़ोतरी हुई लेकिन पाटनरोधी शुल्क लगाने से जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट हुई है।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2019-20 तक गिरावट हुई लेकिन आवेदकों की घरेलू विक्रियों में गिरावट तथा शुल्क आकर्षित करने वाले अन्य देशों से आयातों से जांच अवधि के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई है।

ग. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

99. घरेलू उद्योग के निष्पादन की लाभों, नकद लाभों, नियोजित पूंजी पर लाभ के संदर्भ में जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	विक्रियों की लागत	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	109	104
2	विक्रय कीमत	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	45	63

3	लाभ / हानि	रुपए.ट.मी/	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	-19	23
4	लाभ / हानि	रुपए लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	-23	25
5	नकद लाभ	रुपए लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	-17	35
6	पीवीआईटी	रुपए लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	37	-22	24
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	-20	15

100. यह देखा गया है कि-

- क. आवेदक वर्ष 2017-18 में लाभ अर्जित कर रहा था जिसमें वर्ष 2018-19 में अत्यधिक गिरावट आयी। अन्य देशों से पाटन बढ़ने से आवेदक का निष्पादन वर्ष 2019-20 फिर विकृत हो गया और इसे काफी वित्तीय हानियां हुई।
- ख. आवेदक की लाभप्रदता में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है क्योंकि इसको रिकार्ड लाभ हुआ है।
- ग. नकद लाभ, और ब्याज पूर्व लाभ तथा कर में लाभों के समान प्रवृत्ति हुई। उनमें वर्ष 2019-20 में नकारात्मक होने से पूर्ण वर्ष 2018-19 में काफी गिरावट आयी। तथापि, आवेदक ने जांच अवधि के दौरान नकद लाभ, तथा ब्याज पूर्व लाभ तथा कर अर्जित किया है।
- घ. आवेदक ने जांच अवधि में निवेश पर सकारात्मक लाभ अर्जित किया है।

घ. सामान-सूची

101. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की सामान-सूची की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	प्रारंभिक सामानसूची-	मी.ट.	***	***	***	***
2	अंतसूची-सामान :	मी.ट.	***	***	***	***
3	औसत सामानसूची-	मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	281	254	230

102. यह देखा गया है कि आवेदक के पास सामान-सूची में वर्ष 2018-19 में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वर्ष 2019-20 में इसमें गिरावट आई, क्योंकि आवेदक अपनी विक्रियां बढ़ा सका था। तथापि, यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान आवेदक की औसत सामान-सूची अभी काफी अधिक है। यह भी देखा गया है कि सामान सूचियों में किसी प्रकार बढ़ोतरी को रोकने के लिए आवेदक ने हानिकर कीमतों पर काफी निर्यात किया था।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

103. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	102	95
2	वेतन और मजदूरी	रुपए लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	141	124
3	प्रतिदिन उत्पादकता	मी.दिन/.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	101	96
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	99	101

104. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर वर्ष 2018-19 तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद उसमें गिरावट आयी। घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में क्षति अवधि में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जांच अवधि में इसमें गिरावट आयी। आवेदक की उत्पादकता उत्पाद के अनुरूप रही है। तथापि, यह नोट किया गया है कि उपर्युक्त मापदंड देश में अलग-अलग कानूनों से शासित हैं तथा पाटन पर ही निर्भर नहीं हैं।

च. वृद्धि

105. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मापदंडों की जांच नीचे दर्शायी जाती है

क्र.सं.	विवरण	यूजोएम	2018-19	2019-20	पीजीआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	2.61%	-1.57%	-4.80%
2	बिक्री	वाई/वाई	19.55%	1.40%	-9.15%
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वाई/वाई	-67.43%	-159.18%	-218.06%
4	सामानसूची-	वाई/वाई	181.09%	-9.77%	-9.24%
5	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	9.53%	-3.67%	-1.91%
6	कर पूर्व लाभ	वाई/वाई	-61.07%	-160.01%	-207.25%
7	नकद लाभ	वाई/वाई	-56.20%	-138.23%	-307.30%
8	पीबीआईटी	वाई/वाई	-63.13%	-159.55%	-209.95%
9	आरओआईसी	वाई/वाई	-68.72%	-162.87%	-173.88%

106. यह देखा गया है कि विभिन्न संसाधनों से पाटन की वजह से क्षति अवधि के दौरान आवेदक के मात्रा संबंधी मापदंडों नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। कीमत संबंधी मापदंडों ने वर्ष 2019-20 में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी और उन्होंने जांच अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है।

छ. नई पूंजी जुटाने की सामर्थ्य

107. यह देखा गया है कि आवेदक ने वर्ष 2014 में अपने नए संयंत्रों पर *** निवेश किए थे और इसके वर्तमान लाभ कम हैं क्योंकि इसमें पाटन के दुष्प्रभावों से बाहर आ रहा है।

ज. पाटन की मात्रा

108. यह देखा जा सकता है कि मै. हान्वाह सोल्यूशन्स कॉर्पोरेशन के मामले को छोड़कर संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त हैं।

झ. कारणात्मक संबंध

109. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा ऐसे किंही ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा जिनसे क्षति होने की संभावना हो, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होती है तथा कारणात्मक संबंध के बारे में मूल जांच में पहले ही जांच कर ली गई है, इसलिए प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है। यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए सहायक हो सकते हैं अथवा क्षति में योगदान देने की संभावना है।

क. अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

110. यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चाइनीज ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य स्रोतों से आयात न्यूनतम से कम सीमा तक ये 1 दिसंबर, 2020 इन देशों से पाटित आयातों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। इसलिए जांच अवधि में एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए पाटित कीमतों पर घरेलू बाजार में इन देशों से आयात हो रहे हैं। जैसा कि आवेदन में स्वीकार किया गया है, इन स्रोतों से हुए आयातों से भी आवेदक को क्षति हुई थी।

ख. मांग में कमी और/अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव

111. विचाराधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2019-20 तक बढ़ी थी, लेकिन देश में कोविड की वजह से जांच अवधि में इसमें कमी हुई थी। जबकि जांच अवधि में मांग में गिरावट हुई थी, तब भारत में संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में बढ़ोतरी हुई है। आवेदक की घरेलू विक्रियों में भी जांच अवधि में गिरावट आयी है।

ग. व्यापार संबंधी प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार संबंधी कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ड. निर्यात निष्पादन

114. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण करने के लिए घरेलू प्रचालनों के क्षति संबंधी आंकड़ों पर अलग से विचार किया है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

115. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन संबंधी आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं विक्री किए गए अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

व. क्षति मार्जिन की मात्रा

116. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए तथा जांच अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन की लागत संबंधी सूचना/आंकड़ों को अपना करके निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटीलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। अनावर्ती खर्चों को अलग कर दिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां और औसत चल पूंजी) पर (22% की दर से कर पूर्व) उचित लाभ की नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित एनआईपी प्राप्त करने हेतु कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और इसका अनुपालन किया गया है।
117. पहुंच मूल्य और यथा उपरोक्त निर्धारित एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	
		अमरीकी डालर/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	%	रेंज

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	
		अमरीकी डालर/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	अमरीकी डालर/ मी.ट.	%	रेंज
क	चीन जन.गण.					
1	कोवेस्ट्रो पोलिमेर चाइना कं.लि .	***	***	***	***	30-40
2	वान्हुआ केमिकल ग्रुप कं.लि .	***	***	***	***	10-20
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	80-90
ख	कोरिया जन. जण.					
1	बीएसएफ लि.	***	***	***	***	50-60
2	हान्वा सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	***	0-10
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	90-100
ग	जापान					
1	काई	***	***	***	***	50-60

118. यह देखा गया है कि सभी भागीदारी उत्पादकों के बारे में क्षति मार्जिन सकारात्मक है। इसके अलावा जापान के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

ट. क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

119. जांच अवधि के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति की संभावना अथवा पुनरावृत्ति को देखने के लिए जांच की अवधि के बाद के 6 महीनों के आंकड़ों की जांच करने के लिए अनुरोध।
- ख. आवेदक ने संबद्ध देशों से अधिक आपूर्ति समविष्ट करते हुए वैश्विक अधिक आपूर्ति को समाप्त करने हेतु वैश्विक क्षमताओं पर भरोसा किया। वर्ष 2020-21 के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।
- ग. सारणी में उपलब्ध कराए गए क्षमता संबंधी आंकड़े वैश्विक क्षमता के हैं और न कि संबद्ध देशों के बारे में हैं। इसके अलावा गैर-संबद्ध देशों से अतिरिक्त क्षमताओं से वैश्विक अधिक आपूर्ति को क्षति हो सकती है।
- घ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2004 (170) ईएलटी 144 में यह निर्णय दिया गया था कि अधिशेष उत्पादन क्षमता के होने को ही क्षति के स्पष्ट तौर पर अनुमान लगाने और सन्निकट खतरे के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
- ड. कोवेस्ट्रो चाइना इष्टतम क्षमता पर कार्य कर रहा है। कोई भी अतिरिक्त अथवा फालतू क्षमता नहीं है।
- च. क्षति अवधि के दौरान कोवेस्ट्रो चाइना के द्वारा क्षमता में कोई बड़ोतरी नहीं की गई है।
- छ. संबद्ध देशों से अधिक क्षमता के बारे में याचिकाकर्ता के दावे का कोई आधार नहीं है और ऐसे दावे के लिए आधार के रूप में याचिका में दर्शायी गई आईसीआईएस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गई है।
- ज. प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि “अधिशेष क्षमता” का संबद्ध देशों में घरेलू मांग के अतिरिक्त किसी क्षमता के लिए उल्लेख नहीं किया जा सकता है। एक वैश्विक एकीकृत बाजार में ऐसी एक समझ अपवाद स्वरूप त्रुटि है। अपितु, अधिशेष को घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के बाद में छोड़ी गई निष्क्रिय क्षमताओं के लिए देखा जाता है।

- झ. प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि बीजिंग विंटर ओलम्पिक्स ने विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने वाली यूनिटों सहित चीन में प्रदूषण करने वाली यूनिटों द्वारा उत्पादन बंद करने के लिए चीन सरकार को बाध्य किया है। इसकी गहन संक्षिप्त की गई सप्लाई हैं और अगले 12 महीनों के लिए सप्लाई का स्तर सीमित रखने के लिए एक बड़ा प्रभावित करने वाला बना रहेगा।
- ञ. याचिकाकर्ता ने चीन में मांग की गिरावट के बारे में दावा किया है जिससे पाटनरोधी शुल्क एक बार हटा लिए जाने से भारत के लिए आयातों की बढ़ोतरी हो सकती है। तथापि, याचिकाकर्ता, चीन में मांग की गिरावट होने के बारे में प्रासंगिक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है।
- ट. चीन की निर्यात संबंधी अवस्थिति 14% है जो जापान की 46% और कोरिया जन.गण. की 59% के मुकाबले में कम है।
- ठ. चूंकि पाटनरोधी शुल्क चार (4) वर्षों से अधिक समय से लागू किए गए हैं, इसलिए संबद्ध देशों से निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए वैकल्पिक बाजार पहले ही ढूंढ लिए हैं तथा अन्य देशों में आयातकर्ताओं अथवा प्रयोक्ताओं के साथ संविदात्मक अथवा अन्य व्यवस्थाएं कर ली हैं। संबद्ध देशों में उत्पादन का काफी हिस्सा निर्यात के लिए कर दिया जाता है और उसे भारत के लिए भेजा जाएगा, याचिकाकर्ता का यह तर्क बिना किसी आधार, प्रमाण का है, केवल निराधार कल्पना है तथा इसे अस्वीकार करने की जरूरत है।
- ड. चीन से निर्यात अन्य देशों के मुकाबले अधिक कीमत वाले होते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन जन.गण से आयातों पर अधिक सीमा शुल्क और कीमत कटौती नकारात्मक है।
- ढ. चीन में उत्पादन अधिकांशतः केवल घरेलू खपत के लिए होता है।
- ण. आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में टीडीआई के लिए संतुलित वैश्विक बाजार स्वीकार किया है।
- त. आवेदक ने यह भविष्यवाणी की है कि शुल्क समाप्त होने के बाद भी यह लाभप्रद होगा, जिसकी संभावना से नकार दिया है।
- थ. याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि यदि पाटनरोधी को निरस्त कर दिया जाता है तो निवेश पर उसका लाभ नकारात्मक होगा। प्रतिवादी यह स्वीकार करता है कि याचिकाकर्ता के अनुमान पूर्णतः अटकल बाजी और बिना किसी आधार के हैं। अपितु पीओआई के बाद याचिकाकर्ता का आर्थिक निष्पादन बहुत सशक्त रहा है।
- द. चीन में मांग में मंदी अथवा भारत आकर्षक बाजार होने संबंधी दावे का कोई आधार नहीं है।
- ध. क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती में कमी हुई। वास्तविक निष्पादन क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को असत्य प्रमाणित करता है।
- न. संभावना को सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं दिया गया। पीवीसी फ्लैक्स फिल्म फ्राम चाइना पीआर की निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने संभावना साबित करने के लिए प्रमाण के अभाव जांच को समाप्त कर दिया।
- प. केवल पाटन और क्षति मार्जिन होने का अभिप्राय: यह नहीं होता है कि क्षति घरेलू उद्योग को होगी। इसलिए ये अनुरोध अप्रासंगिक है। संबद्ध देशों से अन्य देशों के लिए निर्यात किए जा रहे हैं, केवल पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का इससे अभिप्राय: नहीं है। यह मानते हुए कि भारत में पीयूसी का एक मात्र विनिर्माता याचिकाकर्ता है, इसलिए प्रतिवादी जैसे प्रयोक्ताओं के लिए भारतीय बाजार की व्यवहार्यता महत्वपूर्ण होती है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रयोक्ता उद्योग के लिए आपूर्ति में अंतर होने की वजह से यह महत्वपूर्ण है कि संबद्ध देशों के उत्पादक अपने निर्यात के लिए भारत में प्रयोक्ता उद्योग हेतु भारतीय बाजार को स्वीकार करें।
- फ. भारत में चीन जन.गण से पीयूसी की आयात कीमत प्रकाशित आईसीआईएस कीमतों से कम है, घरेलू उद्योग के इस आरोप के प्रत्युत्तर में प्रतिवाद यह मानता है कि प्रतिवादियों की आईसीआईएस टीडीआई कीमतों से भारत के लिए टीडीआई निर्यात कीमत की तुलना से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादियों से भारत के लिए टीडीआई निर्यात कीमत पीओआई के दौरान प्रकाशित आईसीआईएस कीमतों के अनुरूप थीं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

120. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. जब शुल्क लगाए गए तब भी पाटन का जारी रहना पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और क्षति को जारी रखने की संभावना को सुनिश्चित करता है।
- ख. संबद्ध देशों से आयातों की कीमतें क्षति रहित कीमत से काफी कम हैं तथा क्षति मार्जिन काफी है।
- ग. आवेदक कीमत के आधार पर आयातों से प्रत्यक्षतः मुकाबला करता है और यदि शुल्क बढ़ाए नहीं जाते हैं, तो इसके घरेलू उद्योग के निष्पादन पर मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे।
- घ. शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा काफी रही है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बाद भी सकारात्मक कीमत कटौती यह सुनिश्चित करती है कि शुल्क समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- च. चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद की मांग निरंतर कम हो रही है क्योंकि फोम उद्योग में लगे विनिर्माताओं ने अपना उत्पादन आधार चीन से बदलकर ताइवान कर दिया है।
- छ. भारतीय बाजार उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कोवेस्ट्रो पोलिमर और बीएसएफ लि. अपनी क्षमता के काफी हिस्से का भारत में पाटित वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं।
- ज. चीन में उत्पादन का लगभग 14% जापान में उत्पादन का 46% और कोरिया में उत्पादन के 59% का निर्यात प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। भारत एक आकर्षक बाजार होने की वजह से उत्पादक अपने अधिशेष उत्पादन को भारत के लिए हस्तान्तरित करने की कोशिश करेंगे।
- झ. वैश्विक क्षमताएं मांग से अधिक हैं, इसलिए उत्पाद के बारे में वैश्विक अधिक सप्लाई की स्थिति होती है। इसी तरह जारी स्थिति संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए लागू है।
- ञ. चीन जन.गण., जापान और कोरिया जन.गण. से क्रमशः 83%, 59% और 70% निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं। संचयी तौर पर संबद्ध मात्रा भारतीय मांग से काफी अधिक होती है।
- ट. चीन जन.गण., जापान और कोरिया जन.गण. से 99% निर्यात क्षति रहित कीमतों पर होते हैं। संचयी तौर पर संबद्ध मात्रा भारतीय मांग से काफी अधिक होती है।
- ठ. चीन जन.गण., जापान और कोरिया जन.गण. से 48%, 63% और 46% निर्यात भारतीय कीमतों से कम कीमत पर होते हैं। संचयी तौर पर संबद्ध मात्रा भारतीय मांग से काफी अधिक होती है।
- ड. प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दायर प्रत्युत्तर भी यह दर्शाता है कि क्षति की संभावना है।
- ढ. भारत के सभी प्रतिवादी उत्पादकों की निर्यात बिक्रियों में जांच अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई है।
- ण. वान्हुआ केमिकल कारपोरेशन ने यह स्वीकार किया है कि यह भविष्य में विस्तार करने की योजना बना रहा है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

121. वर्तमान जांच, चीन जन.गण., जापान और कोरिया जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित करना होता है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति को जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
122. प्राधिकारी ने धारा 9क (5) नियम 23 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II (VII) के संदर्भ में वस्तुगत क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित में लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के बारे में जांच की है।
123. प्राधिकारी के अनुसार अन्य देशों में उत्पादकों के कीमत निर्धारण करने संबंधी व्यवहार को देखने के लिए अन्य देश के निर्यातों की जांच की गई है। इसके अलावा, यदि अन्य देशों के लिए निर्यात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की कीमतों पर हैं और भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर हैं, तो शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में भारत में आयातों में संभावित बढ़ोतरी की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने जांच भी की है।
124. यह देखा गया है कि चीन जन.गण. और कोरिया जन.गण. के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। तथापि, जापान से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और कोरिया जन. गण. के लिए क्षति की संभावना की

जांच करने हेतु प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना पर विचार किया है। जापान के लिए, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना पर विचार किया है।

ट.3.1 निष्क्रिय क्षमताएं

125. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताओं के बारे में सूचना नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने क्षति की संभावना की जांच करने के लिए जांच अवधि की सूचना की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	क्षमता	उत्पादन	निष्क्रिय क्षमता	भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में निष्क्रिय क्षमता	
		मी.ट.	मी.ट.	मी.ट.	%	रेंज
क	चीन जनगण.	***	***	***	***	20-30
1	कोवेस्ट्रो पोलिमर्स चाइना कं. लि.	***	***	***	***	40-50
2	वान्हुआ कोमिकल ग्रुप कं. लि.					
ख	कोरिया जन.गण.	***	***	***	***	60-70
1	बीएसएसएफ लि.	***	***	***	***	40-50
2	हान्वाह सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	***	20-30
ग	जापान	***	***	***	***	20-30

स्रोत: ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट

126. यह देखा गया है कि कोवेस्ट्रो पोलिमर्स की ***% क्षमता, वान्हुआ केमिकल की ***% क्षमता, बीएसएसएफ की ***% क्षमता, हान्वाह की ***% क्षमता जांच अवधि के दौरान निष्क्रिय थी। जापान के मामले में यह देखा गया है कि जापान में ***% क्षमताएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। यह देखा गया है कि उत्पादकों ने अपने-अपने देश में मांग से काफी अधिक क्षमताओं की स्थापना कर ली है तथा अपनी क्षमताओं का निर्यात के प्रयोजन के लिए उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

ट.3.2 निर्यात अनुकूलन

127. संबद्ध देशों में उत्पादकों के निर्यात अनुकूलन के बारे में सूचना नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने क्षति की संभावना की जांच करने के लिए जांच अवधि की सूचना की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	उत्पादन	निर्यात	भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में निर्यात अनुकूलन	
		मी.ट.	मी.ट.	%	रेंज
क	चीन जनगण.	***	***	***	120-130
1	कोवेस्ट्रो पोलिमर्स चाइना कं.लि .	***	***	***	250-260
2	वान्हुआ कोमिकल ग्रुप कं.लि .				
ख	कोरिया जन.गण.	***	***	***	130-140
1	बीएसएसएफ लि.	***	***	***	120-130
2	हान्वाह सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	80-90
ग	जापान	***	***	***	120-130

स्रोत: ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट

128. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों में उत्पादक अपने उत्पादन के काफी हिस्सा का निर्यात प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं।

ट.3.3 अन्य देशों का पाटन

129. अन्य देशों के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	पाटित कीमत पर अन्य देश के लिए निर्यात	अन्य देशों के लिए कुल निर्यात	भारतीय मांग के % के रूप में पाटित कीमतों पर निर्यात	
		मी.ट.	मी.ट.	%	रेंज
क	चीन जनगण.				
1	कोवेस्ट्रो पोलिमर्स चाइना कं.लि .	***	***	***	70-80%
2	वान्हुआ कोमिकल ग्रुप कं.लि .	***	***	***	20-30%
ख	कोरिया जन.गण.				
1	बीएसएफ लि.	***	***	***	60-70%
2	हान्वाह सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	70-80%
ग	जापान	***	***	***	70-80%

स्रोत: ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट

130. यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए प्रतिवादी उत्पादकों के निर्यातों का काफी हिस्सा पाटित कीमतों पर होता है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए जापान से भी निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं। अन्य देशों के लिए ये पाटित निर्यात भारत में मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं।

ट.3.4 अन्य देश के लिए हानिकर निर्यात

131. अन्य देश के लिए हानिकर निर्यातों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	हानिकर कीमत पर अन्य देशों के लिए निर्यात	अन्य देशों के लिए कुल निर्यात	हानिकर कीमत पर अन्य देशों के लिए निर्यात		भारतीय मांग की हानिकर कीमत के प्रतिशत पर अन्य देशों को निर्यात	
		मी.ट.	मी.ट.	%	रेंज	%	रेंज
क	चीन जनगण.						
1	कोवेस्ट्रो पोलिमर्स चाइना कं.लि .	***	***	***	90-100	***	110-120
2	वान्हुआ कोमिकल ग्रुप कं. .लि	***	***	***	90-100	***	80-90
ख	कोरिया जन.गण.						
1	बीएसएफ लि.	***	***	***	90-100	***	120-130
2	हान्वाह सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	90-100	***	110-120
ग	जापान	***	***	***	90-100	***	80-90

स्रोत: ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट

132. यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए सहयोगी उत्पादकों के पर्याप्त निर्यात ऐसी कीमतों पर होते हैं जो घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होती हैं। इसके अलावा, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए जापान से ***% निर्यात हानिकर कीमतों पर भी होता है।

ट.3.5 कीमत का आकर्षण

133. कीमत के आकर्षण के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	भारत के लिए कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात	अन्य देशों के लिए कुल निर्यात	भारत के लिए कम कीमत पर अन्य देशों को निर्यात		भारतीय मांग का प्रतिशत भारत के लिए कम कीमत पर अन्य देशों के लिए निर्यात	
		मी.ट.	मी.ट.	%	रेंज	%	रेंज
क	चीन जनगण.						
1	कोवेस्ट्रो पोलिमर्स चाइना कं.लि.	***	***	***	90-100	***	110-120
2	वान्हुआ कोमिकल ग्रुप कं. लि.	***	***	***	70-80	***	60-70
ख	कोरिया जन.गण.						
1	बीएसएफ लि.	***	***	***	80-90	***	100-110
2	हान्वाह सोल्यूशन्स कारपोरेशन	***	***	***	80-90	***	100-110
ग	जापान	***	***	***	60-70	***	50-60

स्रोत: ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट

134. यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए कोपरेटिव उत्पादकों के निर्यातों के काफी हिस्सा का भारत के लिए उनकी निर्यात कीमत से कम कीमतों पर निर्यात होता है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया है कि अन्य देशों के लिए जापान से *** निर्यात भारत के लिए निर्यात कीमत से कम कीमतों पर होते हैं। प्राधिकारी का अंतिम जांच परिणाम के चरण में पाटन और क्षति की संभावना के अन्य संकेतों के साथ-साथ इस पर विचार करने का प्रस्ताव है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

136. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए :

- आवेदक के उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की पद्धति उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह मानते हैं कि संबद्ध देश के संयंत्र इष्टतम स्तर पर कार्य कर रहे हैं जो आवेदक के लिए अतर्कसंगत/अनुचित है। इस प्रकार, आवेदक प्राधिकारी से घरेलू उद्योग की भारित औसत, वास्तविक लागत अथवा उत्तर देने वाले उत्पादकों की वास्तविक लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का अनुरोध करता है।
- आवेदक ने बार-बार और नियमित रूप से प्राधिकारी को लेन-देनवार मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुरोध किया। यह वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्यातक का बहुत कम निर्यात है। कीमतों में इस प्रकार की बदलती हुई प्रवृत्ति के साथ भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ भारित औसत निर्यात कीमत की तुलना प्रभावी पाटन मार्जिन को दर्शाने के लिए अत्यधिक भ्रामक है।
- ऐसी स्थिति में जहां आयात उसी माह में अथवा उस माह के आस-पास और जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक अलग-अलग कीमतों पर हुआ है, हमारी चिंता कम कीमत पर हुए आयात की है जिसके साथ-साथ संभावित मात्रा क्षति की इस सीमा तक दर्शाने के लिए संगत हो जाती है कि इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसी निर्यातक के लिए आयात कीमतों में 118 प्रतिशत का अंतर है, इस प्रकार के उतार-चढ़ाव को भारित औसत आयात कीमत का उपयोग कर उपयुक्त रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह

- एक सही मामला है जहां प्राधिकारी को पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर आधारित लेन-देन पर विचार करना चाहिए।
- v. निष्क्रिय क्षमताओं के साथ प्रचालन करने के बावजूद, संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यात के उद्देश्य से अपने उत्पादन का एक बहुत बड़े हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यात उन्मुखीकरण भारतीय मांग पर विचार करते हुए बहुत अधिक है।
- vi. भारत को तीसरे देश से अधिकांश निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हुए हैं। जैसाकि पहले ही जांच के दौरान बताया गया है, भारतीय बाजार, संबद्ध देशों में इन उत्पादकों को आकर्षक कीमतों की पेशकश करते हैं। इस कारण से, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि शुल्क को वापस लिए जाते ही वे अपने तीसरे देश के निर्यात को भारत की ओर परिवर्तित करेंगे।
- vii. भारतीय बाजार कीमत संवेदनशील बाजार है, उपभोक्ता निर्यातकों द्वारा उद्धृत कीमतों के आधार पर समझौता करते हैं। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाता है तब अवतरित आयात कीमत में गिरावट आएगी। इस प्रकार, यदि शुल्कों का समय-विस्तार नहीं किया जाता है तब आवेदक को कीमत संबंधी क्षति उठानी पड़ेगी।
- viii. चूंकि आयात कीमत लागू पाटनरोधी शुल्क से प्रभावित होती है, अतः इस तथ्य के कारण कि पाटनरोधी शुल्क लागू है, ऐसी स्थितियों में पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन में परिवर्तन से कोई निश्चयात्मक अनुमान नहीं निकाला जा सकता है।
- ix. आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि शुल्क में कोई परिवर्तन इस अधिनियम, पाटनरोधी संबंधी नियमावली और विश्व व्यापार संगठन के करार के विपरीत होगा।
- x. आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी से वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क की राशि का फिर से निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है। न केवल यह कि नियम 23 में प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है बल्कि धारा 9क(5) के सामान्य पठन से भी यह उल्लेख होता है कि प्राधिकारी से केवल इस तथ्य का निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या आगे की 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार की सिफारिश की जाए।
- xi. विभिन्न स्रोतों से आयात की कीमत में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप अविश्वसनीय मार्जिन गणना होगी, पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में शुल्कों को लगाए जाने के साथ सुधार हुआ है और यदि शुल्क समाप्त हो जाता है तब पाटन और क्षति की संभावना के स्पष्ट साक्ष्य के साथ शुल्क की मात्रा में कोई संशोधन करना उपयुक्त नहीं होगा।
- xii. आवेदक यह अनुरोध करते हैं कि शीला फोम लिमिटेड (प्रयोक्ता उद्योग) द्वारा अर्जित प्रतिफल में शुल्क को लगाए जाने के समय से निरंतर रूप से वृद्धि हुई है। यह भी देखा जा सकता है कि श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड की लाभप्रदता भी बहुत अधिक रही है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

137. विभिन्न विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश नीचे दिए गए अनुसार है:

- पाटन मार्जिन की गणना प्रकटन विवरण में निर्धारित की गई संशोधित पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन के आधार पर की जानी चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्व में उन मामलों में जहां निर्यातकों ने निर्णायक समीक्षा के दौरान गहन पाटन किया था, वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन के आधार पर संशोधित शुल्क का निर्धारण किया।
- वानहुआ का यह अनुरोध है कि यह तथ्य कि आयात करने वाले प्रतिष्ठान ने आयात कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की विक्री घाटे पर की है, संबद्ध वस्तुओं का आयात किए जाने के पश्चात बाजार स्थिति में परिवर्तन का परिणाम है। वानहुआ ने यह भी अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयात कीमत और पुनः विक्री कीमत के बीच अन्तर के आधार पर संघ अथवा मुआवजा की जांच त्रुटिपूर्ण तरीके से की है, जबकि उक्त जांच आयात के समय संबंधित और असंबंधित प्रतिष्ठानों की आयात कीमत की तुलना कर आयात के समय कीमत के आधार पर की जानी चाहिए।

- iii. निर्यातक और आयात के बीच केवल संबंध के फलस्वरूप निर्यात कीमत की अविश्वसनीयता की स्वतः घोषणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि निर्यात कीमत, निर्यातक और आयात के बीच संघ अथवा मुआवजा संबंधी व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है।
- iv. प्राधिकारी को निवल निर्यात कीमत में संबंधित आयातकों के द्वारा की गई पुनः विक्री संबंधी लेन-देन में उठाई गई हानि का समायोजन करने के लिए प्रस्ताव पर फिर से विचार करना चाहिए, जो न्यायोचित नहीं है। वैकल्पिक तौर पर, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अब भी संबंधित प्रतिष्ठानों की आयात कीमत की विश्वसनीयता के बारे में संदेह को तब वानहुआ ने प्राधिकारी से असंबंधित प्रतिष्ठानों की आयात कीमत के आधार पर निर्धारण करने का अनुरोध किया है, जो बहुत अधिक मात्रा में है।
- v. यदि यह नहीं दर्शाया जाता है कि कीमतें पक्षकारों के संबंध के रूप में प्रभावों के कारण अविश्वसनीय हैं, तब पहुंच कीमत पर विचार भारतीय सीमा शुल्क द्वारा पहले से ही आकलित कीमत के आधार पर किया जाना है और आगे कोई समायोजन आवश्यक नहीं है और किसी भी स्थिति में, सीमा शुल्क ऐसे किसी संबंध के प्रभाव पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था, लेकिन कोई प्रतिकूल निर्धारण नहीं था।
- vi. ऊपर में किए गए अनुरोध के बाद सीमा शुल्क ने पहले ही यहां प्रश्रुत वस्तुओं के मूल्य का आकलन किया है और यहां पक्षकारों के संबंध के फलस्वरूप कंपनी द्वारा घोषित मूल्यों का कोई पुनः आकलन नहीं किया गया था। यह मूल्यांकन पहले ही अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है और मूल्यांकन के नियम सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त पाए गए अनुसार लागू किए गए थे, जो इस प्रकार के सिद्धांतों को लागू करने के लिए सही प्राधिकारी है।
- vii. डीजीटीआर भारतीय सीमा शुल्क जो मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, द्वारा यथा-परिकलित पहुंच कीमत की उपेक्षा नहीं कर सकता है और सीमा शुल्क द्वारा लागू पाए गए मूल्यांकन को छोड़कर कोई अन्य पद्धति सीमा शुल्क के मूल्यांकन नियमावली का उल्लंघन होगा।
- viii. वानहुआ के मामले में यथा-प्रस्तावित पहुंच कीमत लागू मूल्यांकन नियमावली के अनुरूप भी नहीं है और उस पर निष्पक्ष तरीके से फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- ix. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक को बिल्कुल भी कोई क्षति नहीं हुई है और वह बहुत सुविधाजनक स्थिति में है, जैसा कि वर्ष 2020-21 के लिए उनकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इस आवेदन में दी गई सूचना इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि क्षति के फिर से होने की कोई संभावना भी है।
- x. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि इस आवेदन में आवेदक द्वारा किए गए क्षति संबंधी दावे की संभावना अथवा उसके फिर से होने या क्षति की प्रकृति से निर्णायक समीक्षा की शुरुआत किया जाना आवश्यक नहीं था और इस नियमावली के संबंध में आवेदन की वस्तुपरक प्रारंभिक जांच के फलस्वरूप, इस जांच की शुरुआत नहीं हुई होती।
- xi. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक के लिए यह आवश्यक था कि वह विधिवत् प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत करे और प्राधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे समीक्षा की शुरुआत करने के पूर्व उक्त आवेदन में विधिवत् प्रमाणित तथ्यों की सत्यता के बारे में अपने आप को संतुष्ट करें। इसके अलावा आईपीयूए का अनुरोध है कि आवेदक यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस आवेदन को विधिवत् इस समीक्षा की शुरुआत करने के पूर्व प्रमाणित किया गया है, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए हैं।
- xii. आईपीयूए का अनुरोध है कि आवेदक आयात के प्रायः सभी प्रमुख स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क के कारण संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्राधिकारी को पाटनरोधी कार्रवाई के माध्यम से आवेदक के पक्ष में और प्रयोक्ता उद्योगों के हित के विरुद्ध एकाधिकार बनाने और उसे कायम रखने में सहायता नहीं करनी चाहिए।
- xiii. आईपीयूए का अनुरोध है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के मुद्दे की उपेक्षा की है जिसमें केवल 80:20 के अनुपात में आइसोमर की मात्रा वाले टीडीआई शामिल हैं और जिसमें 65:35 के अनुपात में आइसोमर की मात्रा न होने वाले टीडीआई और सभी अन्य ग्रेड शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, आईपीयूए का यह अनुरोध है कि चूंकि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग के आंकड़ों तथा आयात आंकड़ों में स्पष्ट रूप से मात्रा और कीमत विश्लेषण तथा पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण, दोनों के लिए 80:20 के अनुपात में आइसोमर की मात्रा वाले टीडीआई को छोड़कर, वे सभी उत्पाद शामिल नहीं हैं, यह संभव है कि सभी निर्धारण दोनों उत्पाद प्रकारों के लिए किया गया है और उसके फलस्वरूप निर्धारणों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

- xiv. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि यह डीजीटीआर की निरंतर कार्य-पद्धति है कि उत्पाद/उत्पाद प्रकार, जिसका बाजार में वाणिज्यिक रूप से उत्पादन और आपूर्ति नहीं की जाती है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को स्वीकार करते समय कि घरेलू उद्योग वीएचटी रहित टीडीआई का उत्पादन नहीं करता है, घरेलू उद्योग ने केवल इस इस कथन को स्वीकार किया है कि उनके पास इस उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता और और इस कारण से पाटनरोधी शुल्क इस उत्पाद पर भी लागू रहना चाहिए।
- xv. आईपीयूए का अनुरोध है कि क्या उत्पाद प्रकार की मांग बहुत अधिक अथवा कम है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा अनावश्यक शुल्क भार के बिना सामग्री की आसान उपलब्धता है। निर्यात उद्देश्य से, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात में अपना स्वयं का लेन-देन लागत और समय आधिक्य होता है और इसके साथ ही निर्यातक आरओडीटीईपी लाभ से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया विकल्प निर्यातकों के लिए दोहरा खतरा है।
- xvi. आईपीयूए अनुरोध करता है कि इस क्षेत्र में शामिल सभी प्रतिष्ठानों के साथ एक सामान्य ज्ञान है कि आईपीयूए भारत में पोलियूरेथेन प्रयोक्ताओं के लिए नोडल प्रतिनिधिक निकाय है। इस कारण से, प्राधिकारी ने कार्यवाहियों में भाग लेने तथा इस आवेदन का विरोध करने के लिए संघ के अधिकार को सही तरीके से बाहर रखा है।
- xvii. आईपीयूए का अनुरोध है कि मूल कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता तथा संबद्ध वस्तु की आयात कीमत की तुलना में घरेलू उत्पादक की कीमत अतार्किकता टोलुएन की कीमत, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत और आयात कीमत के आंकड़ों, जिस पर प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटन विवरण में विचार नहीं किया गया है, से स्पष्ट है।
- xviii. आईपीयूए का अनुरोध है कि प्रयोक्ता उद्योग को इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक संबद्ध वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक है और इसके उत्पादन संबंधी मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मुद्दे हैं, संबद्ध वस्तु की वृद्धिपूर्ण आपूर्ति संबंधी मुद्दे के कारण हानि हो रही है।
- xix. आईपीयूए का अनुरोध है कि पोलियूरेथेन और फोम उत्पादक उद्योग के लिए नोडल प्रतिनिधिक निकाय के द्वारा 1 लाख टन की संबद्ध वस्तु की मांग अनुमान प्रामाणिक है क्योंकि इसने प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा, उनके खपत के आधार पर पीयूसी की मांग का आकलन किया है। इसके विपरीत, प्राधिकारी ने किसी प्रामाणिक रिपोर्ट के समर्थन के बिना घरेलू उद्योग की मांग अनुमान स्वीकार की है।
- xx. आईपीयूए का अनुरोध है कि आवेदक द्वारा निरंतर पाटन का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पद्धतियां सीमा प्रशुल्क अधिनियम अथवा पाटनरोधी करार से मेल नहीं खाती थी। इस कारण से, प्राधिकारी को पाटन के जारी रखने के आधारों पर इस समीक्षा की शुरुआत करने के लिए इस प्रकार के कानूनी रूप से बेमेल पद्धतियों के आधार पर निरंतर पाटन के ऐसे दावे को स्वीकार नहीं करने चाहिए थे। इस प्रकार से, इस जांच को इस प्रकटन विवरण के जारी किए जाने की बजाय, समाप्त किया जाना चाहिए था।
- xxi. आईपीयूए का अनुरोध है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के वास्ते ताइवान से वियतनाम तक निर्यातक कीमत को अपनाने की पद्धति गैर-कानूनी है। इसके अलावा, प्राधिकारी वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने के वास्ते पद्धति उपलब्ध नहीं करा पाए हैं।
- xxii. आईपीयूए का अनुरोध है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति का प्रकटन एक आवश्यक तथ्य है जिसे प्राधिकारी द्वारा इसके अंतिम निर्धारण के पूर्व अवश्य प्रकट किया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति का प्रकटन किए बिना, प्रकटन विवरण पूर्ण रूप से अधूरा है और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे आगे की कार्यवाही करने के पूर्व एक नया प्रकटन जारी करें।
- xxiii. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक द्वारा इस आधार पर कि 2020-21 में आयातों की सीआईएफ कीमत में इन कीमतों में शामिल भाड़े की अधिक राशि के कारण वृद्धि हुई थी, निर्यात कीमतों का निर्धारण करते समय भाड़े की लागतों में आवेदक द्वारा किए गए कुछ असामान्य समायोजन यह संकेत देते हैं कि पाटन मार्जिन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाना आवश्यक है जबकि निर्यात कीमत की वस्तुपरक जांच यह दर्शाई होती कि कोई निरंतर पाटन नहीं हुआ था।
- xxiv. आईपीयूए यह दोहराता है कि आवेदक को जांच की अवधि के दौरान कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है जो आवेदक की सार्वजनिक घोषणाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध अन्य सूचना से स्पष्ट है।

- xxv. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी ने कोविड आंकड़े को छोड़कर क्षति संबंधी मानदंडों के सामान्यीकरण का ब्यौरा प्रकट नहीं किया है।
- xxvi. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में किया गया दावा 2020-21 के लिए उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है, जहां उन्होंने स्वयं यह कहा है कि कंपनी ने प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अच्छा प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन प्राप्त किया।
- xxvii. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी प्रकटन विवरण में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि क्या आयातों की मात्रा और कीमतों आदि जैसे क्षति संबंधी मानदंडों के संबंध में अनुक्रमित आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् टीडीआई 80:20) से संबंधित हैं अथवा इसमें 65:35 अनुपात सहित सभी टीडीआई भी शामिल हैं।
- xxviii. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा विशेष रूप से दर्शाए जा रहे मुद्दे के बावजूद विभिन्न कारकों में "वास्तविक और संभावित" गिरावट का विश्लेषण करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए हैं।
- xxix. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण नहीं कर पाए हैं कि क्षमता के विस्तार के बाद भी, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता उसी स्तर पर रही है। इस कारण से, पाटित आयातों के कारण मात्रा संबंधी क्षति का कोई दावा बिल्कुल माने जाने के योग्य नहीं है।
- xxx. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी इस तथ्य की जांच नहीं कर पाए हैं कि आवेदक अपने निर्यात दायित्वों का अनुपालन करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के समय से अपने उत्पादन का एक तिहाई का निर्यात करते रहे हैं।
- xxxi. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है क्योंकि आवेदक संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और यह निर्यात बाजार की मांग को भी पूरा करता है। इस कारण से, प्रयोक्ता पिछले अनेक वर्षों से आपूर्ति के सभी संभावित स्रोतों के विरुद्ध भारी पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद इन वस्तुओं का आयात करने के लिए बाध्य है।
- xxxii. घरेलू उद्योग की विक्री की मात्रा में वृद्धि दर मांग में वृद्धि से बहुत अधिक थी। इसके अलावा, तुलनीय अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष का लगभग आधा था जो किसी मात्रा संबंधी प्रभाव, जैसाकि आरोप लगाया गया है, को संसूचित नहीं करता है।
- xxxiii. आईपीयूए का अनुरोध है कि इस आवेदन में इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों घरेलू उद्योग के लिए विक्री की लागत में 4 अंक की वृद्धि हुई है जबकि निर्यात बाजार के लिए विक्री की लागत उसी समयावधि के दौरान 20 अंक तक कम हुई है और क्यों इस तथ्य के बावजूद कि निर्यात बाजार के लिए विक्री की लागत में इतनी तीव्र गति से गिरावट आई है, आवेदक घाटे पर निर्यात बाजार में विक्री कर रहे थे।
- xxxiv. आईपीयूए का अनुरोध है कि निर्यात कीमतों ने पाटनरोधी संरक्षण के अंतर्गत एकाधिकारवादी कीमत निर्धारण स्थिति के बीच घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई असामान्य रूप से उच्च कीमतों के कारण कीमत में कटौती को दर्शाया।
- xxxv. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत संबंधी मानदंड बिल्कुल ही किसी क्षति को नहीं दर्शाते हैं जबकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन किया और बहुत अधिक लाभ अर्जित किया।
- xxxvi. आईपीयूए का अनुरोध है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने स्वयं की स्वीकारोक्ति के द्वारा, आवेदक उद्योग अच्छी स्थिति में है और उसे वर्तमान में न तो कोई वास्तविक क्षति होती है और न ही पाटित आयातों के कारण कंपनी को क्षति के निकट भविष्य में फिर से होने की कोई संभावना है।
- xxxvii. आईपीयूए ने इस बात को दोहराया कि आवेदक द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि पाटन और परिणामी क्षति के फिर से होने की संभावना है तथा आवेदक द्वारा दिए गए सभी तर्क अस्पष्ट और अप्रमाणित धारणाओं पर आधारित है।
- xxxviii. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई तीसरे देश के आंकड़े के स्रोत को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट नहीं किया गया है, जबकि निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर लेन-देनवार तीसरे देश के निर्यात आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराते हैं।

- xxxix. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक संबद्ध देशों से अन्य देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यातों की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए ईक्यूआर, आईसीआईएस रिपोर्ट से लेन-देनवार आंकड़े प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं, वे जांच के आरंभन के चरण में सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए उक्त देशों में कीमत आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
- xl. आईपीयूए का अनुरोध है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयातों की मात्रा में विभिन्न देशों के विरुद्ध शुल्क अथवा पाटनरोधी शुल्क के साथ अथवा उसके बिना वर्तमान स्तर पर बनी रही है, आयात मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, जिससे यह संसूचित किया गया है कि ऐसी कोई मांग पूरी नहीं की गई है, जिसे आयातों द्वारा पूरा किया जाना है।
- xli. आईपीयूए का अनुरोध है कि कीमत स्तर का निर्धारण प्रभावी घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है जबकि शुल्क को हटाए जाने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वापस आ जाएगी। इस प्रकार शुल्क को हटाने से आवेदक की लाभप्रदता की स्थिति पर विचार करते हुए आगे निकट भविष्य में कोई क्षति नहीं होगी।
- xlil. आईपीयूए का यह अनुरोध है कि आवेदक ने पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना की स्थिति को गलत तरीके से पेश करने के लिए भ्रामक आंकड़े और सूचना का सहारा लिया है और कुछ विरोधी तथा अस्पष्ट दावे किए हैं जिसे प्राधिकारी ने प्रतिवादियों द्वारा विस्तृत अनुरोध किए जाने के बावजूद जांच नहीं की है।
- xlili. कोवेस्ट्रो प्राधिकारी से अपने अंतिम जांच परिणाम में भी प्रकटन विवरण में निर्धारित पहुंच मूल्य और निवल निर्यात कीमत की पुष्टि करने का अनुरोध करता है।
- xliv. कोवेस्ट्रो चीन ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 में प्राधिकारी को वास्तविक क्षमता और क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे निष्क्रिय क्षमता, यदि कोई हो, का निर्धारण करते समय कोवेस्ट्रो चीन की वास्तविक क्षमता और क्षमता उपयोग के आंकड़ों पर विश्वास करें। कोवेस्ट्रो चीन ने अपनी सुनवाई पश्चात लिखित अनुरोधों में यह भी अनुरोध किया था कि कोवेस्ट्रो चीन के पास कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं है।
- xliv. कोवेस्ट्रो यह अनुरोध करता है कि कोवेस्ट्रो चीन ने अपनी एमईटी प्रश्नावली के उत्तर में उपर्युक्त भागों में भूमि के उपयोग के अधिकार, कच्चा माल, श्रमिक लागत और उपयोगिताओं की कीमत निर्धारण के संबंध में पूर्ण सूचना प्रस्तुत करते हुए विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है।
- xlvi. कोवेस्ट्रो ने यह अनुरोध किया कि टोलुएन का भी उपयोग दवा का निर्माण करने के लिए किया जाता है और इस कारण से वह सरकार के नियंत्रण के अधीन है। हालांकि, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीडीआई के निर्माण के लिए खरीदे गए टोलुएन का उपयोग दवाओं के निर्माण में नहीं किया जाता है, केवल खरीद संबंधी प्रक्रियाओं और व्यापार प्रवाह पर ही नियंत्रण रखती है। लाइसेंस इसके प्रत्येक खरीद संबंधी लेन-देन के लिए भी अपेक्षित है। इसके अलावा, प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि उस कीमत, जिस पर टोलुएन की खरीद प्रतिवादियों द्वारा की जाती है, में कोई सरकारी भागीदारी नहीं होती है। प्रतिवादी टोलुएन की खरीद प्रत्यक्ष रूप से विक्रेताओं के साथ समझौता की गई कीमतों पर करते हैं।
- xlvii. कोवेस्ट्रो का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी के लिए विशिष्ट रूप से इस तथ्य का आकलन करना अपेक्षित है कि क्या कच्चे माल की लागतें व कीमतें बाजार सिद्धांतों के अनुसार हैं। उपयोगिताओं जैसे प्राकृतिक गैस, बिजली, जल आदि की लागत और कीमतों का विशिष्ट रूप से निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आकलन किए जाने के लिए संगत मानदंड के रूप में नहीं है।
- xlviil. कोवेस्ट्रो का यह अनुरोध है कि प्राकृतिक गैस भी “प्रमुख इनपुट” नहीं है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) में उल्लेख किया गया है और इसमें केवल टीडीआई उत्पादन में प्रतिवादियों द्वारा वहन की गई कुल लागतों का 0.8 प्रतिशत है। इस प्रकार, प्राकृतिक गैस की अधिमान्य कीमत के कारण प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त किसी लाभ का विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की समग्र लागत और विचाराधीन उत्पाद के परिणामी घरेलू लागतों पर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं है।
- xlilx. कोवेस्ट्रो का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को कम से कम पूर्ण लॉकडाउन द्वारा प्रभावित अप्रैल, 2020- जून, 2020 की तिमाही को अलग रखना चाहिए। अप्रैल 2020 – जून 2020 की तिमाही को अलग रखने से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में बहुत अधिक सुधार देखा जाएगा।

- I. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि आयातों का वस्तुनिष्ठ आकलन यह दर्शाता है कि क्षति की जांच की अवधि के दौरान आयातों में गिरावट आई है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क जून, 2017 से लागू नहीं था, इस प्रकार क्षति की जांच की अवधि के दौरान आयातों में गिरावट के लिए पाटनरोधी शुल्क को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो क्षति की समग्र अवधि के दौरान प्रचलित था।
- ii. भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में निर्यातोन्मुखीकरण घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए उपयोग की गई प्रतिनिधिक मानदंड नहीं है। भारतीय मांग के साथ प्रतिवादियों के कुल निर्यातों की तुलना निर्यातोन्मुखीकरण के बारे में अप्रतिनिधिक और अतिरंजित संसूचना देता है।
- iii. प्रतिवादी का यह अनुरोध है कि भारत को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात बिक्री 6,341 एमटी मात्र है, जो जांच की अवधि के दौरान इसकी कुल बिक्री का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। प्रतिवादी प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे जांच परिणामों को जारी करने के पूर्व इन अनुरोधों पर विचार करें।
- liii. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग को हुई क्षति कोविड-19 के कारण है और तीसरे देशों से आयात के कारण है और न कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण।
- liv. प्राधिकारी का यह विवेकाधिकार है कि वह 5 वर्षों से कम की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें, जब प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हों कि पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षाकृत लघु अवधि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त होगा। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश भी की जाती है तब प्राधिकारी को पूर्ण 5 वर्ष से अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए शुल्क को इस प्रकार से जारी रखने की सिफारिश करनी चाहिए।
- iv. शीला फोम का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी ने भारत में वीएचटी रहित टीडीआई की मांग की मात्रा नहीं बताई है और न ही प्राधिकारी ने उसके लिए स्रोत उपलब्ध कराया है। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, प्रतिवादी इस तथ्य पर उपयुक्त रूप से टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हो जाएंगे कि क्या भारत में वीएचटी रहित टीडीआई के कम होने की मांग का आकलन सही है। इसके बावजूद प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि वीएचटी रहित टीडीआई की मांग अधिक है और इस प्रकार इसे बाहर करना आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग उसका निर्माण नहीं करता है। इसके अलावा, शीला फोम ने भी जांच की अवधि के दौरान भारत में वीएचटी रहित टीडीआई से निर्मित तैयार उत्पाद की बिक्री की है।
- lvi. शीला फोम का अनुरोध है कि उत्पाद को बाहर किए जाने का निर्धारण किसी विशेष ग्रेड अथवा प्रकार के लिए मांग के अधिक अथवा कम होने के आधार पर नहीं किया जा सकता है बल्कि क्या आयात किया गया उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसा है। वर्तमान मामले में, हमने पहले ही यह दर्शाया है कि वीएचटी रहित टीडीआई उस विचाराधीन उत्पाद के जैसा नहीं है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी चिंता और उपभोक्ता की पसंद के संदर्भ में संबद्ध वस्तुओं से अलग है।
- lvii. शीला फोम का यह अनुरोध है कि अग्रिम अधिकरण की उपलब्धता इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए एक कारक नहीं हो सकती है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उत्पाद प्रकार/श्रेणी को बाहर रखा जाए अथवा नहीं। प्राधिकारी को केवल इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि क्या ये उत्पाद समान उत्पाद हैं और क्या घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में वाणिज्यिक मात्राओं में इस उत्पाद का उत्पादन किया है और इसकी बिक्री की है।
- lviii. प्राधिकारी ने भारत में वीएचटी रहित टीडीआई से निर्मित उत्पादों के लिए वर्तमान मांग और भविष्य में बढ़ने वाली मांग पर विचार नहीं किया है। इस स्थिति में वीएचटी रहित टीडीआई से बनाए गए उत्पादों की घरेलू मांग में भविष्य में वृद्धि होगी, प्रयोक्ता उद्योग बहुत अधिक हानिग्रस्त हो जाएंगे।
- lix. शीला फोम का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा दावा की गई और अनुमति दी गई गोपनीयता अत्यधिक है। याचिकाकर्ता एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है और यह क्षमता, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, बिक्री मूल्य आदि जैसे आंकड़ों को प्रकट करता है।
- lx. शीला फोम का यह अनुरोध है कि कुल आयातों के अनुपात के रूप में आयातों में वृद्धि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत बिल्कुल ही एक संगत कारक नहीं है और इस कारण से उस पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस कारक के आधार पर मात्रा के प्रभाव के मौजूद होने के अपने निर्धारण को वापस लें। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि संबद्ध आयातों की पूर्ण मात्रा आधार वर्ष के स्तरों का लगभग आधा है। यह कठोर रूप से मात्रा के प्रभाव का नहीं होना बताता है।

- Ixi. शीला फोम का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी का विश्लेषण अंतिम रूप से यह उल्लेख नहीं करता है कि क्या संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा वे कम हो रही हैं। इसके बावजूद हम यह अनुरोध करते हैं कि संबद्ध देश के आयातों के द्वारा ऐसी कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।
- Ixii. शीला फोम का यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के निर्यात करने के लिए बाध्य होने के बारे में प्राधिकारी का विश्लेषण जिसका घरेलू मांग के लिए उपयोग किया जा सकता था, सही नहीं है क्योंकि घरेलू मांग में गिरावट आई है और निर्यात बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। संबद्ध देश के आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट का कारण नहीं है।
- Ixiii. प्रतिवादी प्राधिकारी से यह नोट करने का अनुरोध करते हैं कि घरेलू बिक्री की मात्रा में कोविड की स्थिति के कारण जांच की अवधि को छोड़कर वृद्धि हुई है लेकिन वह आधार वर्ष से उच्चतर है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद की कैप्टिव खपत के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों को प्रकटन विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।
- Ixiv. प्रतिवादी का यह अनुरोध है कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित बाजार हिस्से के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित बाजार हिस्से के आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं, जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का बाजार हिस्सा बहुत अधिक अर्थात् 64-70 प्रतिशत के दायरे में है।
- Ixv. यदि याचिकाकर्ता को हानि भी हो रही है तब वह इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध आयातों के द्वारा याचिकाकर्ता के आर्थिक कार्य-निष्पादन में मात्रा और कीमत में कटौती का कोई ऐसा सह-संबंध नहीं है, संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण है।
- Ixvi. संबद्ध आयातों की मात्रा में 2018-19 और 2019-20 में गिरावट आई। हालांकि, सुधार होने के बजाए, याचिकाकर्ता की लाभप्रदता मानदंडों में इन दो वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि जब संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में मामूली रूप से वृद्धि हुई, याचिकाकर्ता की लाभप्रदता के मानदंड में जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि हुई।
- Ixvii. जब संबद्ध वस्तुओं के द्वारा कीमत में कटौती में 2018 -19 और 2019-20 में बहुत अधिक गिरावट आई, याचिकाकर्ता के लाभप्रदता के मानदंड में वृद्धि होने के बजाए इन दो वर्षों में बहुत अधिक गिरावट आई। वास्तव में, कीमत में कटौती इन दो वर्षों में नकारात्मक थी। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता के वित्तीय मानदंडों में गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि जब कीमत में कटौती जांच की अवधि में सकारात्मक थी, याचिकाकर्ता के वित्तीय कार्य-निष्पादन में बहुत अधिक सुधार हुआ था।
- Ixviii. शीला फोम का यह अनुरोध है कि मालसूची में वृद्धि मात्र अपने आप में क्षति का संसूचक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी का यह कथन कि याचिकाकर्ता ने मालसूची के जमा होने को रोकने के उद्देश्य से बहुत अधिक निर्यात किया था, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के निर्यात की मात्रा में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- Ixix. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग को अनेक स्रोतों से कथित रूप से पाटित आयातों से संरक्षण मिल रहा है, फिर भी घरेलू उद्योग ने नकारात्मक वृद्धि देखी है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति कथित रूप से पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी को भारत में टीडीआई के किसी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश ही नहीं करनी चाहिए।
- Ixx. प्राधिकारी से केवल यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या याचिकाकर्ता नई पूंजी जुटाने में सक्षम होने से मजबूर था। चूंकि, याचिकाकर्ता ने 2014 में, पहले ही निवेश किया था और भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में कमी आने के बाद याचिकाकर्ता के लिए अत्यधिक निवेश करने का कोई अवसर नहीं था।
- Ixxi. यदि पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक भी है तब यह अपने आप में संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य की जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है।
- Ixxii. यद्यपि, याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में जांच की अवधि में गिरावट आई, वे आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 10 अनुक्रमित अंक अधिक थे। दूसरी ओर, जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष में

उसके आधे तक गिरावट आई। इस प्रकार, यद्यपि घरेलू मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई, घरेलू उद्योग के पास संबद्ध आयातों से अधिक बिक्री हुई थी।

- lxxiii. अतिरिक्त क्षमताओं की मौजूदगी मात्र क्षति के फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि संबद्ध देशों में उत्पादक भी निर्यातोंनुमुख हैं, इसका आशय यह नहीं है कि वे पाटनरोधी शुल्क के समाम होने ही भारत को निर्यात करना शुरू कर देंगे।
- lxxiv. केवल इस कारण से कि निर्यात तीसरे देशों को संबद्ध देशों से कथित रूप से पाटित और कथित रूप से क्षतिकारक कीमतों पर किए जा रहे हैं, उसका अभिप्राय पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना से नहीं है। प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क के समाम होने पर भारत को निर्यातों के विपथन की कोई संभावना दर्शानी है जिसे प्रकटन विवरण नहीं दर्शा पाया है।
- lxxv. याचिकाकर्ता का इस स्थिति में गिरती हुई उसके आर्थिक कार्य-निष्पादन के बारे में कथन कि पाटनरोधी शुल्क को समाम कर दिया गया है, का खंडन सार्वजनिक स्रोतों में सूचना दी गई वास्तविक आर्थिक कार्य-निष्पादन के द्वारा किया गया है। यह पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को भी खंडित करता है।
- lxxvi. प्रतिवादी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी कोविड की अवधि को छोड़कर सूचना का भी विश्लेषण करें।
- lxxvii. बीएसएफ का यह अनुरोध है कि आवेदक को न तो कोई क्षति हुई है और न ही कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण पाटन और क्षति होने की कोई संभावना है।
- lxxviii. प्राधिकारी को अन्य कारणों से और न कि संबद्ध देश से और विशेषकर कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति हुई है जिसे निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता है।
- lxxix. बीएसएफ कंपनी लिमिटेड की क्षमता उपयोग क्षति की पूरी अवधि के दौरान लगभग उसी दायरे में रही। तदनुसार यह स्पष्ट है कि क्षति के जारी रहने अथवा इसके फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- lxxx. बीएसएफ का यह अनुरोध है कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान बीएसएफ कंपनी लिमिटेड के उत्पादन का 6 प्रतिशत से कम उत्पादन का निर्यात भारत को किया गया था, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि भारत इसके लिए एक आकर्षक बाजार नहीं है।
- lxxxi. बीएसएफ का यह अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई तीसरे देश के पाटन का विश्लेषण और कीमत आकर्षकता और क्षतिकारक निर्यात के विश्लेषण के लिए पद्धति मौलिक रूप से गलत है और इसके फलस्वरूप, गलत परिणाम प्राप्त होगा क्योंकि किसी विशेष संख्या से भारित औसत संख्या की तुलना हमेशा इससे कम कुछ लेन-देन को दर्शाएगा।
- lxxxii. निर्णायक समीक्षा के फलस्वरूप, सामान्य रूप से इस अवधि के विस्तार को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए शुल्कों को प्रभावी होना माना जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां/अनुरोध पूर्व में उनके अनुरोधों की अधिकांशतः पुनरावृत्ति है जिसकी पहले ही जांच वर्तमान जांच परिणाम के प्रकटन विवरण अथवा संगत पैराओं में समुचित रूप से जांच की गई है और उनका समाधान कर लिया गया है। प्राधिकारी ने इन अनुरोधों की जांच, इसमें नीचे दी गई संगत सीमा तक की है और उनका समाधान कहीं अन्यत्र नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है:

- i. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार की गई है।
- ii. चीन के उत्पादक/निर्यातक के इन अनुरोधों के संबंध में कि प्राधिकारी ने आयात कीमत से कम कीमत पर बिक्री कर घाटे में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है, संबद्ध वस्तुओं के आयात किए जाने के बाद बाजार स्थिति में बदलाव का परिणाम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसी अवधि के दौरान, जिस कीमत पर चीन जन.गण. के अन्य उत्पादक/निर्यातक के संबंधित आयातक ने संबद्ध वस्तुओं की खरीद की है, वह उस कीमत से बहुत अंतर है, जिस पर वानहुआ इंडिया ने अपने संबंधित उत्पादक/निर्यातक से खरीद की है। इसके अलावा, दो आयातकों की पुनः बिक्री कीमत में भी स्पष्ट अंतर है, वानहुआ इंडिया की पुनः बिक्री कीमत अन्य संबंधित आयातक की पुनः बिक्री कीमत से

बहुत कम है। पुनः बिक्री कीमत और खरीद कीमत में इस अंतर के कारण का उल्लेख वानहुआ केमिकल द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वानहुआ की निर्यात कीमत अविश्वसनीय है और इस वजह से निर्यातक द्वारा अपने संबंधित आयातक को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में उठाई गई हानि का समायोजन किया है।

- iii. प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर संबद्ध जांच की शुरुआत करने के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों की चिंताओं को नोट करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी इस तथ्य को दोहराते हैं कि आवेदक ने एक विधिवत् प्रमाणित आवेदन उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पर वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत प्राधिकारी के प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बाद की गई थी कि पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने और आवेदक को परिणामी क्षति होने का पर्याप्त साक्ष्य है।
- iv. हितवद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को आवेदक के पक्ष में एकाधिकार बनाने में मदद नहीं करनी चाहिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- v. प्राधिकारी ने पहले ही यह मान लिया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आईसोमर की मात्रा वाले टीडीआई से संबंधित है और कोई अन्य श्रेणी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से परे है। इसके अलावा, वर्तमान जांच के उद्देश्य से मानी गई मात्रा और कीमत विश्लेषण से संबंधित आयात आंकड़े प्राधिकारी द्वारा पूर्व में यथा-परिभाषित विचाराधीन उत्पाद से ही संबंधित है।
- vi. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से वीएचटी रहित टीडीआई को बाहर किए जाने संबंधी अनुरोध पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लेन-देनवार आयात आंकड़े में इस तथ्य की पहचान करने के लिए पर्याप्त विवरण नहीं है कि क्या आयात की जा रही संबद्ध वस्तु वीएचटी रहित है अथवा नहीं। इस कारण से, इस तथ्य की पहचान करना संभव नहीं है कि क्या आयात किए गए उत्पाद में वीएचटी है अथवा नहीं। यदि वीएचटी रहित टीडीआई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाता है तब इस सूचना की अनुपलब्धता के फलस्वरूप पाटनरोधी शुल्क से बचा जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर वीएचटी रहित टीडीआई की मांग का अनुमान लगाया है, जिसके अनुसार यह भारत में कुल मांग का लगभग 5 प्रतिशत है। इस मांग को आसानी से अग्रिम अधिकरण योजना के माध्यम से आयात के द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- vii. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने जांच की अवधि में इससे वीएचटी रहित टीडीआई की किसी आवश्यकता का मुद्दा नहीं उठाया है और यदि इसके प्रयोक्ताओं से वीएचटी रहित टीडीआई की कोई आवश्यकता हुई होती तब घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति कर सकता था। आवेदक ने यह दर्शाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई है कि यह वीएचटी रहित टीडीआई उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, आवेदक ने उसी अवधि के दौरान यूएस को निर्यात भी किया है, जिसका इसने दावा किया है और उसमें टीडीआई शामिल है।
- viii. घरेलू उत्पादक की कीमत अतार्किकता के संबंध में, प्राधिकारी इस तथ्य को दोहराते हैं कि आवेदक की बिक्री कीमत में तथा आयातों की कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता है। आयातों की पहुंच कीमत और आवेदक की बिक्री कीमत, दोनों जांच की अवधि की पहली तिमाही में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है, अगली तिमाही में उसमें गिरावट आई और फिर आगे उसके बाद वृद्धि हुई। इसके अलावा, आवेदक ने इस आवेदन में स्वीकार किया है कि उसकी बिक्री कीमत, आयातों की पहुंच कीमत और कच्चे माल की कीमतों में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हुआ है। इस कारण से, जब आयातों में अस्थिरता आई है, तब इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आवेदक ने एक गलत कीमत निर्धारण नीति बनाई रखी है।
- ix. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि हितवद्ध पक्षकारों ने आवेदक, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है, के द्वारा संबद्ध वस्तुओं की वृष्टिपूर्ण आपूर्ति के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं, रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो इस दावे की पुष्टि करता हो।

- x. मांग का अनुमान डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों तथा प्राधिकारी द्वारा यथा-विधिवत् सत्यापित घरेलू उद्योग की बिक्री के अनुसार कुल आयातों के योग के रूप में प्राधिकारी की निरंतर पद्धति के अनुसार लगाया गया है।
- xi. चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत, उचित लाभ को जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित अनुमानों के आधार पर भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया जाता है।
- xii. वानहुआ के लिए निर्यात कीमत की गणना पूर्ववर्ती पैराओं में पहले से ही यथा-उल्लिखित निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर की गई है। संबंधित आयातक को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर निर्यातक द्वारा उठाए गए घाटे का समायोजन निर्यात कीमत में भी किया गया है।
- xiii. संबद्ध देशों से सभी सहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत की गणना उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर की गई है। संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस कारण से, आवेदन में भाड़े की लागतों में आवेदक द्वारा किए गए समायोजनों के कारण किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक को कोई हानि नहीं हुई है।
- xiv. आयातों की मात्रा और कीमतों आदि जैसे क्षति संबंधी मानदंडों के संबंध में अनुक्रमित आंकड़े केवल विचाराधीन उत्पाद से (अर्थात्, टीडीआई 80:20) से संबंधित हैं।
- xv. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है, जबकि क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है।
- xvi. हितवद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि आवेदक अपने निर्यात दायित्वों का अनुपालन करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के समय से अपने उत्पादन का एक तिहाई निर्यात करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान आवेदक का कोई निर्यात दायित्व नहीं है।
- xvii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माल-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता, भारत में मांग से अधिक है।
- xviii. घरेलू और निर्यात प्रचालनों की कीमत में बहुत अधिक अंतर के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अंतर दो संयंत्रों के उत्पादन की लागत में है।
- xix. प्राधिकारी द्वारा जांच की गई तीसरे देश के आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा यथा-प्रस्तुत लेन-देनवार तीसरे देश के निर्यात आंकड़े की संभावना के विश्लेषण के लिए, लिए गए हैं।
- xx. प्राधिकारी ने ईक्यूआर से लेन-देनवार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं और उनका विश्लेषण किया है। आवेदक की इस आंकड़े तक कोई पहुंच नहीं है।
- xxi. प्राधिकारी ने निष्क्रिय क्षमता का निर्धारण करते समय कोवेस्ट्रो चीन की वास्तविक क्षमता और क्षमता उपयोग संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xxii. कोवेस्ट्रो के इस अनुरोध के संबंध में कि प्रतिवादी ने भूमि के उपयोग के अधिकार संबंधी विवरण, श्रम प्रतिफल संबंधी विवरण और उपयोगिताओं की बाजार दर पर अधिग्रहण और एमईटी के प्रभावली के उत्तर में कच्चे माल की बाजार दर साझा की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए आवंटन करने वाले प्राधिकारी का अनुरोध पर्याप्त नहीं है क्योंकि निर्यातक यह सुझाव देते हुए साक्ष्य नहीं दे पाए हैं कि भूमि के उपयोग के अधिकारों को औपचारिक बोली प्रक्रिया किए जाने के बाद निष्पक्ष बाजार दर पर प्राप्त किया गया था।
- xxiii. श्रम इनपुट्स के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल मानक वेतन का भुगतान पर्याप्त नहीं है, यदि कंपनी द्वारा नियोजित श्रमिक के पास रोजगार दाताओं के साथ रोजगार और कार्य संबंधी स्थितियों की सही शर्तों से समझौता करने के लिए यूनिशन बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, पूरे भारत में भुगतान किए गए वेतन के साथ कुशल कामगारों और प्रबंधकों को भुगतान किए गए वेतन की तुलना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रतिवादी अर्थात् शंघाई की अवस्थिति, जिस पर चीन के वित्तीय राजधानी में विचार किया गया है, की तुलना भारत से नहीं की जा सकती है, जिसमें विकास के संदर्भ में और विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी मानक के संदर्भ में परिवर्तन है।

- xxiv. इसके अलावा, लागत और कीमतें भी उपयोगिताओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा ऋण के प्रावधान से प्रभावित होती हैं जो अधिकांशतः राज्य के नियंत्रण में हैं और जिनका संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों पर बहुत अधिक प्रभाव है। इस कारण से, प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं पाते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से चीन में घरेलू बाजार में उपर्युक्त उत्पादक की लागत और कीमतों को स्वीकार किया जाए।
- xxv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान कमी आई है। हालांकि, संबद्ध देशों से आयात अभी भी भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग का 23 प्रतिशत और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 48.29 प्रतिशत है जो पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से बहुत अधिक है। इसके अलावा, 2017-18 के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ, संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आनी शुरू हो गई, जबकि गैर-संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि शुरू हो गई। यह स्पष्ट रूप से व्यापार पैटर्न में परिवर्तन को संसूचित करता है।
- xxvi. यद्यपि भारत को कोवेस्ट्रो चीन की निर्यात बिक्री इसकी कुल बिक्री का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, यह जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में कुल आयातों का 39 प्रतिशत और चीन जन.गण. से कुल आयातों का 87 प्रतिशत है।
- xxvii. भारत में वीएचटी रहित टीडीआई से निर्मित उत्पादों के लिए वर्तमान मांग पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल एक प्रयोक्ता ने वीएचटी रहित टीडीआई की इसकी मांग की मात्रा का उल्लेख किया है। अन्य प्रयोक्ताओं ने ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया है और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकार में से किसी भी पक्षकार के द्वारा प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराई गई है। ऐसी सूचना के अभाव में, प्राधिकारी भारत में वीएचटी रहित टीडीआई से निर्मित उत्पादों की मांग का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं।

ख. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

139. हितबद्ध पक्षकारों ने जनहित के कारण शुल्क को जारी रखने के विरुद्ध निम्नलिखित अनुरोध किए:

- i. आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है और वह व्यापार उपचार की मांग कर भारतीय बाजार में एकाधिकारवादी स्थितियां बनाने की कोशिश कर रहा है।
- ii. आवेदक को 5 वर्षों से शुल्क के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है।
- iii. शुल्क को जारी रखने से एमएसएमई श्रेणी में हजारों प्रयोक्ताओं को हानि होगी। यदि जांच समाप्त की जाती है तब व्यापक जनहित पूरा होगा।
- iv. इस संघ में 400 से अधिक सदस्य हैं और 120 से अधिक "टोलुएन डाईसोसाइनेट" (टीडीआई) प्रयोक्ता गद्दों, फर्नीचर फोम आदि के निर्माण में लगे हुए हैं। अधिकांश प्रयोक्ता उद्योग एमएसएमई क्षेत्र में हैं।
- v. घरेलू प्रयोक्ताओं को आवेदक के प्रतिस्पर्धीरोधी और एकाधिकार वाली व्यवहार के विरुद्ध समान अवसर की आवश्यकता है।
- vi. मूल अंतिम जांच परिणाम में दी गई मात्राओं पर विचार करते हुए, भारत में वर्तमान मांग 80,000 से 85,000 होनी चाहिए और आवेदक भारतीय मांग का केवल 50-55 प्रतिशत पूरा कर सकता है।
- vii. अत्यधिक मांग-आपूर्ति में अंतर है और अधिकांश प्रयोक्ता एमएसएमई श्रेणी के हैं।
- viii. टीडीआई और एफएसपी – दो कच्चे माल उत्पादन किए गए फोम के कच्चे माल की लागत का 95 प्रतिशत से अधिक है और वे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन हैं, जो प्रयोक्ता उद्योग पर अतिरिक्त भार डालते हैं। प्रयोक्ता उद्योग 5 प्रतिशत से कम मार्जिन पर कार्य करते हैं।
- ix. केवल टीडीआई पर शुल्क की वर्तमान दर से, अतिरिक्त लागत लगभग 6-7 प्रतिशत है। एफएसपी और टीडीआई का संयुक्त प्रभाव 11-12 प्रतिशत है।
- x. पोलियूरेथेन फोम बेडिंग बाजार का लगभग 20 प्रतिशत पोलिथिलीन फोम, जो एक सस्ता प्रतिस्थानापन्न है, में से उत्पादन किए गए बेडिंग के कारण पहले ही खोया जा चुका है।
- xi. पोलियूरेथेन उद्योग जो टीडीआई और एफएसपी का उपयोग करता है, अपनी इकाईयों को परिचालित करने के लिए आयात पर निर्भर हैं। उन्हें पहले से ही रुपए-डॉलर की समतुल्यता, समुद्री भाड़े में वृद्धि, कंटेनर की कमी आदि

के कारण हानि हो रही है और लगभग सभी प्रमुख विदेशी स्रोतों से पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए अंतिम सहारा साबित हो रहा है।

- xii. घरेलू प्रयोक्ताओं को आवेदक के प्रतिस्पर्धी और एकाधिकार व्यवहार के विरुद्ध समान अवसर की आवश्यकता है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

140. घरेलू उद्योग ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के पक्ष में निम्नलिखित अनुरोध किए:

- विचाराधीन उत्पाद पर 2017 से पाटनरोधी शुल्क लगता रहा है और अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव एक नई घटना नहीं होगी।
- अध्रेसिव, पीवीसी कोटेड पेपर, पोलियूरेथेन रेसिन, फिनाइल आइसोसाइनेट और पीयू फोम पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	अंतिम उत्पाद	अंतिम उत्पाद की बाजार कीमत	प्रतिशत में अंतिम उत्पाद पर प्रभाव
1	एध्रेसिव	प्रति किलोग्राम .रु 5000	0.11%
2	पीवीसी कोटेड पेपर	70 रुप्रति वर्गमीटर .	1.32%
3	पोलियूरेथेन रेसिन	1300 रुप्रति किलोग्राम .	0.23%
4	फिनाइल आइसोसाइनेट	650 रुप्रति किलोग्राम .	1.22%
5	पीयू फोम की दर	420 रु प्रति .किलोग्राम	1.74%

- यदि प्रयोक्ता शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध करने में असफल रहे हैं, तब आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रभाव दर्शाता है कि इन शुल्कों ने आवेदक को अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना लाभ पहुंचाया था।
- शीला फोम लिमिटेड द्वारा अर्जित प्रतिफल में शुल्क को लगाए जाने के समय से निरंतर रूप से वृद्धि हुई है।
- श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड की लाभप्रदता भी बहुत अधिक रही है।
- मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने और आयातों पर निर्भरता नहीं होने के साथ, भारतीय टीडीआई उद्योग पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर उद्योग है।
- सभी विगत जांचों ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि आवेदक को पाटन के कारण हानि होती है और शुल्कों का समय विस्तार निश्चित रूप से आवेदक के हित में होगा।
- यदि एकमात्र उत्पादक को हानि उठाने दिया जाता है तब यह अंतिम रूप से समाप्त हो सकता है और उपभोक्ता केवल निर्यातकों की दया पर रह जाएंगे। चूंकि आवेदक प्रयोक्ताओं की तरह उसी राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित हैं, अतः प्रयोक्ता के हित सुरक्षित रहेंगे।
- उपभोक्ता को पहले से ही कोरिया गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रियायती सीमा शुल्क मिल रहा है।
- जबकि वर्तमान मामले में व्यापार आधिक्य होना चाहिए था, यह तथ्य है कि टीडीआई का व्यापार संतुलन घाटे को दर्शाता है जो गंभीर रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है और भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य में बाधक बनते हैं।
- दावा किए गए संघ में 120 टीडीआई प्रयोक्ताओं में से केवल 5 प्रयोक्ताओं ने भाग लिया है और उनमें से कोई भी एमएसएमई श्रेणी में नहीं आते हैं। इस संघ ने अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

141. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए, जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का कोई संभावित प्रभाव शामिल है, देने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के वास्ते प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने इस पर विचार किया कि क्या शुल्क को लगातार लगाए रखने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच की प्रक्रिया के दौरान, इस तथ्य की जांच करने के लिए कदम उठाए गए थे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने आवेदक, इस उत्पादक के आयातक और प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार किया है।

- i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का समय-विस्तार किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- ii. हितवद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एमएसएमई क्षेत्र के प्रयोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क के द्वारा विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित होगा, कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार से पाटन की कार्य-पद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- iii. हितवद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए बहुत अधिक लागत नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ उपभोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। जांच की प्रक्रिया के दौरान, उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितवद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना नहीं दर्शाई है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से या तो इन उपभोक्ताओं पर अथवा व्यापक रूप से आम जनता पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, आवेदक ने अधेसिव, पीवीसी कोटेड पेपर, पोलियरेथेन रेसिन, फिनाइलआइसोसाइनेट और पीयू फोम पर शुल्क के प्रभाव की मात्रा संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। यह देखा जाता है कि शुल्क का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है।
- iv. जांच की प्रक्रिया के दौरान, यह तर्क दिया गया था कि मांग और आपूर्ति में अंतर है, जिसके कारण आयात आवश्यक हो जाता है। रिकॉर्ड पर सूचना से, यह देखा जाता है कि मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और हितवद्ध पक्षकार से कहा गया था कि वह दावे के आधार उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कहे जाने के बावजूद, कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस कारण से, यह देखा जाता है कि मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और शुल्क लगाए जाने से अंतिम प्रयोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- v. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन की दीर्घ अवधि प्रतिबद्धता वर्ष 2014 में अपने संयंत्र का विस्तार कर दर्शाई है। आवेदक ने अपने नए संयंत्र पर बहुत अधिक निवेश किया था और यह आवश्यक है कि इस प्रकार के निवेशों को भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए संरक्षित किया जाए।
- vi. आगे यह नोट किया जाता है कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की कीमतें पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर आयात कीमतों के अनुरूप हैं, यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में शुल्क का कोई अनुचित लाभ नहीं वसूली है। घरेलू उद्योग शुल्क प्रदत्त आयातों से प्रतिस्पर्धा करेगा।
- vii. यह माना जाता है कि स्वस्थ घरेलू उद्योग की मौजूदगी अंततः प्रयोक्ताओं के हित में है। कोविड-19 की अवधि में हाल के अनुभव ने यह भी दर्शाया है कि यदि उत्पाद घरेलू बाजार में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हों तब व्यापक रूप से जनता को संभवतः हानि उठानी पड़ती है।

- viii. प्राधिकारी ने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से पाटनरोधी शुल्को को जारी रखने के प्रभाव का विश्लेषण भी किया है और यह टिप्पणी की है कि विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादकों का विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में सक्षम होना संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा। यह तब संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हैं। यदि वर्तमान स्थिति को जारी रखने दिया जाता है तब भारतीय घरेलू उत्पादक घरेलू उत्पादकों के विरुद्ध विदेशी उत्पादकों को बड़ी हुई लीवरेज देते हुए आगे क्षति का सामना करेंगे। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग को हानि होने दी जाती है तब यह अंततः समाप्त हो जाएगी और उपभोक्ता आयात की जाने वाली वस्तुओं की दया पर फिर रह जाएंगे।
- ix. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि शुल्क लागू था, अतः प्रयोक्ता उद्योग ने राजस्व और लाभ में वृद्धि देखी है। इसके विपरीत, आवेदक पाटन के विगत प्रभावों से उबर रहे हैं। इस कारण से, शुल्कों का समय विस्तार आवेदक को सहायता प्रदान करेगा।
- x. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा और बल्कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना व्यापक जनहित में होगा।
- xi. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। यह शुल्क घरेलू उद्योग को आगे क्षति होने से रोकेगा और उन्हें संबद्ध देश से निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय देगा।

ड. निष्कर्ष

143. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जिसे इन जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और पाटन, क्षति के निर्धारण और पाटन और क्षति के जारी रखने अथवा उसके फिर से होने के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. आवेदक घरेलू उद्योग इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और उनके द्वारा दायर किया गया आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करते हैं।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया जाना जारी है, जिसके फलस्वरूप मैसर्स हानवा सोल्युशंस कारपोरेशन जिसका पाटन मार्जिन नकारात्मक है, को छोड़कर लगातार पाटन हुआ है। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पाटित और क्षतिकारक कीमत, जिस पर वस्तुओं का निर्यात संबद्ध देशों से किया गया है, उत्पादकों/निर्यातकों की उच्च निर्यातोन्मुखीकरण और संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास बहुत अधिक अतिरिक्त क्षमताओं पर विचार करते हुए बहुत अधिक हद तक बढ़ने की संभावना है।
 - ग. संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही थी और घरेलू उद्योग को इसकी कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव के कारण हानि हुई है। इसके अलावा, क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री भी बहुत अधिक हद तक सकारात्मक है जो स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक कीमत प्रभाव को दर्शाता है।
 - घ. आवेदक को 2017-18 में लाभ हो रहा था, जिसमें 2018-19 में तेजी से गिरावट आई। अन्य देशों से पाटन के गहन होने के साथ, आवेदक के कार्य-निष्पादन में आगे 2019-20 में गिरावट आई और इसे बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। हालांकि, आवेदक की लाभप्रदता में जांच की अवधि में सुधार हुआ है क्योंकि इसने लाभ दर्ज किया है।
 - ड. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया आरपी के सहकारी उत्पादक/निर्यातकों तथा तीसरे संबद्ध देश जापान के अन्य सभी निर्यातकों के लिए पाटन और क्षति मार्जिन का विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि कोरिया आरपी और चीन पीआर के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए आयातों की मात्रा के अनुरूप हैं। चीन पीआर और कोरिया आरपी से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचित किए गए आयात, वास्तव में, डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों की तुलना में अधिक हैं। निर्यातक शिपमेंट तिथि के संदर्भ में पीओआई में निर्यात की रिपोर्ट करते हैं जबकि पीओआई में डीजीसीआईएंडएस के आयातों का मिलान संदर्भ तिथि के अनुसार किया जाता है।
 - च. निम्नलिखित के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रखने और उसके फिर से होने की संभावना है:

- i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद मैसर्स हनवा सॉल्यूशंस कॉरपोरेशन, कोरिया को छोड़कर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है।
- ii. प्राधिकारी को निष्क्रिय क्षमता, निर्यात अभिविन्यास, पाटित निर्यात, हानिकारक निर्यात और कीमत आकर्षण पर विचार करने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क की समामि की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए। डीजीटीआर नियमों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना का मूल्यांकन करते समय इन कारकों पर लगातार ध्यान दे रहा है। वर्तमान मामले में, चूंकि चीन पीआर और कोरिया आरपी में सहकारी निर्यातकों की क्षमता का उपयोग काफी अधिक है अर्थात् क्रमशः 90-100% और 70-80%, इन सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत में निर्यात का तीसरा देश डायवर्जन अत्यधिक महत्व का होगा, इसी तरह, जापान के लिए, जहां किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है, द्वितीयक स्रोतों के अनुसार क्षमता उपयोग 80-90% है जो पुनः इंगित करता है कि तीसरे देश का विचलन पाटन और क्षति की संभावना का एक प्रमुख कारक है। उपरोक्त के बावजूद, उत्पादक/निर्यातकों की क्षमता काफी अधिक है और भारत में मांग की तुलना में मौजूदा निष्क्रिय क्षमता भी काफी अधिक है।
- iii. कोरिया आरपी से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि कोरिया आरपी से तीसरे देशों को सहकारी उत्पादक/निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात का लगभग 70-80% डंप किया जाता है, 70-80% हानिकारक होते हैं और 60-70% अधिक आकर्षक कीमतों पर होते हैं। भारत।
- iv. चाइना पीआर के मामले में, चीन पीआर से तीसरे देशों को सहकारी निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात का लगभग 60-50 प्रतिशत डंप किया जाता है, -80 हानिकारक होते हैं और भारत की तुलना में %100-90 अधिक आकर्षक कीमतों पर होते हैं। %90
- v. जापान के उत्पादकों/निर्यातकों का कोई सहयोग नहीं है/, व्यापार मानचित्र पर उपलब्ध जानकारी से, यह नोट किया जाता है कि जापान से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक-70 निर्यात द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात का लगभग/ डंप किया जाता है %80, अधिक आकर्षक कीमतों %70-60 हानिकारक हैं और भारत की तुलना में %100-90 पर हैं।
- vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों द्वारा तीसरे देश के निर्यात/निर्यात के पाटन और क्षति मार्जिन की सीमा का भी मूल्यांकन किया है। भारत के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजनों को इस गणना के लिए उचित रूप से अपनाया गया है। उक्त मार्जिन को भारत के मार्जिन से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
- vii. आयातों की मात्रा भी निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- viii. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के देश में मांग की तुलना में काफी अधिक क्षमता है-निर्यातकों के पास अपने/, जो संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ix. सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के एक बड़े हिस्से का निर्यात उदरनिर्वाहक अपने उत्पाद/देश के लिए उपयोग कर रहे हैं।
- x. तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात हुए हैं जो घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर हैं। तीसरे देशों को निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी पाटित कीमतों पर और भारत में कीमत से कम कीमतों पर है।
- xi. तीसरे देशों को सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के निर्यात के लेनदेन/, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन निर्यातों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत भारत में घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम कीमत पर पाटित और हानिकारक है। उक्त निर्यात भारत की संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग है। %290-280 इन निर्यातों के पाटन और क्षति की मात्रा जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात के संबंध में वर्तमान पाटन और क्षति मार्जिन से कहीं अधिक है।
- xii. चूंकि भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क की समामि जब संबद्ध देशों से तीसरे को निर्यात कीमत भारत से पाटित कीमतों से कम है और क्षतिरहित कीमतों से कम है, यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है। भारतीय उद्योग का अस्तित्व।

- छ. यह स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है। इस कारण से, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इस बात की पूरी संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होगी।
- ज. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के हित में होगा। यह तथ्य कि यह एक पूंजी सघन उद्योग है, शुल्क को जारी रखने से आगे क्षति होना रुक जाएगा और घरेलू उत्पादकों को संबद्ध देशों के निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय मिलेगा।
- झ. प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के फलस्वरूप भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के लिए एकाधिकारवादी और अल्पाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न होगी।

ण. सिफारिशें

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की गई थी और उसे सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी हितवद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था।
145. इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की निर्णायक समीक्षा शुरू किए जाने और उसे पूरा किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाया जाना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अपेक्षित है।
146. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तब पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि शुल्क को जारी रखना संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर अपेक्षित है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि शुल्क की किस मात्रा की सिफारिश जाए जो उपर्युक्त में किए गए अनुसार संभावना के विश्लेषण के कारण पाटन/क्षति को कम कर सके। भारत को तथा विश्व के शेष देशों को सहयोगी निर्यातकों से पाटित और क्षतिकारक आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है।
147. उपर्युक्त परिस्थितियों में प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए उसे उपयुक्त मानते हैं जो संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना का निवारण करेगा और उसे कम करेगा। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि दिनांक 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 03/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाए गए मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जाए। इस कारण से, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों से शुल्क तालिका के कॉलम 3 में दिए गए विवरण के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29291020	टॉलुइन डि-आइसोसाइनेट	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स (चीन) कं., लिमिटेड	0.26	किग्रा.	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	वान्टुआ कैमिकल ग्रुप कं.,	0.26	किग्रा.	अम.डॉ.

				सहित कोई भी देश	लिमिटेड			
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र. सं. 1 और 2 पर अंकित उत्पादकों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	0.26	किग्रा.	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	0.26	किग्रा.	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हान्वहा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन	0.22	किग्रा.	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	बी ए एस एफ कंपनी लिमिटेड	0.31	किग्रा.	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्र. सं. 5 और 6 पर अंकित उत्पादकों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	0.44	किग्रा.	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई	0.44	किग्रा.	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई	0.15	किग्रा.	अम.डॉ.
10	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई	0.15	किग्रा.	अम.डॉ.

148. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9 और 94 के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

149. इन जांच परिणामों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार, सीमाशुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, the 24th June, 2022

(Case No. AD (SSR) /2021)

Subject: Sunset review investigation concerning imports of “Toluene Di-isocyanate” originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/26/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof;

1. The Designated Authority had initiated an anti-dumping investigation in respect of imports of “Toluene di-isocyanate” originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP on 5th October 2016. The Authority recommended provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 28th March, 2017. The Ministry of Finance imposed provisional duty vide Notification No. 25/2017- Customs (ADD) dated 5th June, 2017. Thereafter, final finding was issued vide notification no. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 confirming the imposition of definitive anti-dumping measures on the imports of subject goods from China PR, Japan and Korea RP which was implemented by the Central Government vide Notification No.3/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018. The said duties were levied for a period of 5 years. Vide custom Notification no. 19/2022-Cus (ADD) dated 03.06.2022, the said duty was extended till 27.09.2022

2. In terms of Section 9A(5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

" any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. "

4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of an anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘domestic industry’) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Act and the Rules, for initiation of the sunset review investigation concerning imports of “Toluene di-isocyanate” (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter referred to as ‘subject countries’).
6. In view of the duly substantiated application by the applicant, the Authority in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(B) of the Rules, initiated a sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/26/2021-DGTR for Case No. AD (SSR) - 20/2021 dated 27th August 2021 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning the subject goods issued vide Final Finding No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017.

B. PROCEDURE

8. The procedure described below has been followed in this investigation:

- i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of Rule supra.

- ii. The Authority issued a notification dated 27th August 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27th August 2021 to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their submissions available information within the prescribed time-limit in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- iv. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries. Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- vi. The Authority sent exporters' questionnaires to the following known exporters in the subject countries in accordance with the Rule 6(4) of the Rules to elicit relevant information:
 - a. Bayer Material Science (China) Co., Ltd, China PR.
 - b. Changzhou Dahua Group Co., Ltd, China PR.
 - c. Shanghai BASF Polyurethane Co., Ltd, China PR.
 - d. Wanhua Chemical Group Co., Ltd, China PR
 - e. Yantai Juli Fine Chemical Co. Ltd. China PR.
 - f. Henan GP Chemicals Co.,Ltd, China PR
 - g. Fujian Petrochemical Industrial Group Co. Ltd., China PR
 - h. Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes, Japan.
 - i. Nippon Polyurethane Industry Co., Ltd, Japan.
 - j. BASF Company Ltd, Korea RP.
 - k. Everlite Korea Co., Ltd, Korea RP
 - l. Hanwha Chemical Corporation., Ltd, Korea RP
 - m. IMS Corporation, Korea RP
 - n. OCI Corporation/ OCI Company Ltd. Korea RP.
 - o. PP and Y International Co. Ltd, Korea RP
 - p. Covestro Polymers (China) Co.
- vii. The following companies have filed the exporter questionnaire responses as producers/exporters of the product under consideration:
 - a. Covestro Polymers (China) Company Limited, China PR
 - b. Covestro (Hong Kong) Limited, China PR
 - c. Covestro (Shanghai) Investment Company Limited, China PR (MET Questionnaire)
 - d. Wanhua Chemical Group Co., Ltd, China PR
 - e. Wanhua Chemical (Singapore) PTE. Ltd., China PR
 - f. Wanhua Chemical Fujian Co., Ltd., China PR
 - g. Wanhua Chemical (Yantai) Sales Co., Ltd. , China PR
 - h. Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Ltd. , China PR
 - i. BASF Company Ltd., Korea RP
 - j. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP
 - k. Everlite Korea Co. Ltd. Korea RP
 - l. IMS Corporation, Korea RP
 - m. PP & Y International Co. Ltd., Korea RP

- viii. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/ users of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Rules:
- a. Aadi Polymers Pvt. Limited
 - b. Allied Foam Pvt. Limited
 - c. DuraPuff (Silvassa) Pvt. Limited
 - d. Fancy Foam Pvt. Limited
 - e. Hindustan Polyfoam Pvt. Limited
 - f. Jindal Foam and Co.
 - g. Kurlon Limited
 - h. MH Polymers Pvt. Limited
 - i. Tirupati Foam Limited
 - j. Pyarelal Foam (South) Pvt. Ltd
 - k. Prime Comfort Products Pvt. Limited
 - l. Springwel Mattresses Pvt. Limited
 - m. Sheela Group Co., Limited
 - n. Shree Malani Foams Pvt. Limited
 - o. Sunrise Foam Product Pvt. Limited
 - p. Springfeel Polyurethanes Pvt. Limited
- ix. The following importers/users from have responded by filing questionnaire response
- a. BASF India Limited
 - b. Covestro (India) Private Limited
 - c. Flexipol Foams Private Limited
 - d. M.H. Polymers Pvt Private Limited
 - e. PU Foams. Private Limited
 - f. Shree Malani Private Limited
 - g. Sheela Foams Limited
 - h. Tirupati Foam Limited
 - i. Wanhua International (India) Private Ltd
- x. Legal submissions have also been filed by Indian Polyurethane Association.
- xi. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S import data for computation of the volume & value of imports and injury analysis. Analysis has been done and it has been found that there is no significant difference in the analysis done by the Authority and the applicant.
- xiii. Table verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding producers in the subject countries was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this disclosure statement. Additional/supplementary information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary
- xiv. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') is based on the optimum cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to address injury to the applicant.

- xv. The Authority held oral hearing on 27th December 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xvi. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 2020 to 31st March 2021 (12 months). The injury analysis period includes the period of investigation and the preceding three, 2017-18, 2018-19 and 2019-20.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this disclosure statement, to the extent considered relevant by the Authority.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information have been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of 'facts available'.
- xx. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 12th May, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
- xxi. The exchange rate for the period of investigation has been taken by the Authority is USD = Rs 75.22.
- xxii. '****' in these final finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

9. The product under consideration in the original investigation was described as follows:

"Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula CH₃C₆H₃(NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration."

TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc., packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.

C.1 Submissions made by the other interested parties

10. The following submissions have been made by the interested parties during the course of the investigation:

- a. The applicant cannot supply BHT free material, whereas US and European markets have banned the exports of TDI that is not BHT free. The Respondent request the Authority to examine whether the petitioner produced and sold BTS free TDI during the POI in commercial quantities. Accordingly, BTS free TDI should be excluded from the scope of the PUC.
- b. The applicant is manufacturing the TDI and MDI blend in the ratio of 80:20. However, they are unable to manufacture the TDI and MDI blend with the ratio 65:35. Therefore, it must be expressly excluded from the product scope.
- c. The IPUA submits that TDI is produced in two isometric concentrations of 80:20 and 65:35. The scope of the product under consideration should specifically exclude TDI having isomer content in ratio other than 80:20.
- d. Further, the applicant has failed to clarify whether the data set in petition is pertaining to the TDI with 80:20 ratio only and other variants have been segregated while presenting the data to avoid distortion of the injury analysis.

- e. The Authority has not explained the various grades except 80:20 of TDI manufactured by the applicant domestic industry and being imported to India and if the domestic industry data and the import data clearly excludes those products.

C.2 Submissions made by the domestic industry

11. The following submissions have been made by the applicant during the course of investigation.
 - a. The present application being an application for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as was defined by the Authority in its previous finding.
 - b. The Authority in the original investigation concluded that goods produced by the applicant is a like article to the goods that is imported into the domestic market. There has been no development in the technology and the product produced by the applicant continues to remain like article.
 - c. On the submission of users requiring the BHT free material for exports to EU and USA, the applicant can supply BHT free subject goods.
 - d. Demand of BHT free TDI is insignificant, and the submission has been raised only to divert the Authority's attention to baseless arguments.
 - e. Any user who intends to use BHT free material for export purpose can import the same without payment of any anti-dumping duty under advance authorization scheme.
 - f. The applicant is not producing TDI having isomer content 65:35.
 - g. The applicant has sold TDI-MDI blend in the market and the process of blending is very simple and the ratio of blending can also be changed as per the requirement of the consumers.

C.3 Examination by the Authority

12. In the original investigation, the product under consideration in the original investigation was described as under:

"Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula $CH_3C_6H_3(NCO)_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration."

TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc., packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.

13. On the submission regarding the clarification of the product under consideration that TDI having isomer content in ratio other than 80:20 should specifically be excluded from the scope, it is noted that the scope of the product under consideration is restricted to TDI having isomer content 80:20 and TDI having any other isomer content is outside the product under consideration. Thus, the scope of PUC already excludes the TDI with isometric concentrations of 65:35. There is no ambiguity on the scope of the product under consideration.
14. Regarding the submission of the other interested parties for exclusion of TDI-MDI blend of 65:35 ratio, the Authority notes that blending of TDI & MDI involves simple mixing of TDI 80:20 (PUC) with MDI (another chemical). There is no change in chemical composition during this process. The TDI-MDI blend produces foam and the hardness of foam depends on the percentage of TDI and MDI in it. TDI and MDI may be blended in different proportions like 70% – 30%, 80% – 20%, 50% - 50% etc, respectively.
15. Thus, TDI-MDI blend is an altogether different product and is not covered in the scope of the PUC.
16. On the submission of BHT free TDI required for exporting final products to Europe and United States of America, the Authority notes that as per information available on record, demand for BHT free TDI is insignificant and the users can import BHT free TDI under advance authorization scheme without payment of duty.
17. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry and the interested parties have also not established any difference in the goods produced by the applicant and the imported product. The Authority notes that the subject goods produced by the applicant are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially

interchangeable. Accordingly, the Authority proposes to hold that the subject goods produced by the applicant are 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

18. Rule 2(b) of the Antidumping Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1 Submissions made by the other interested parties

19. The other interested parties have not filed any submissions disputing the standing of the applicant.

D.2 Submissions made by the domestic industry

20. The following submissions have been made by the applicant during the course of the investigation.

- a. The applicant is the sole producer of the subject goods in India.
- b. The applicant has not imported the the subject goods from the subject countries.
- c. The applicant is neither related to the exporter of the subject goods from the subject countries nor the importers of the subject goods in India.
- d. The applicant satisfies the requirement of the Rules

D.3 Examination by the Authority

21. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

22. The present application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has not imported the subject goods from the subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. Accordingly, the Authority determines that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application meets the requirements of 'standing' under Rule 5(3).

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Submissions made by other interested parties

23. The following submissions have been made by other interested parties during the course of the investigation:

- a. The Authority had in the review investigation of Ammonium Nitrate excluded Indonesia from the scope countries and in the Uncoated Copier Paper review investigation excluded Thailand. Similarly, Korea should be excluded from the scope of the investigation as there is no injury or likelihood of dumping and injury.
- b. Specifically, the imports from Korea have declined by 72%, LV of Korea is significantly higher (6.2 %) than NIP and LV from the other subject countries during the POI. Further, the capacity utilization of BASF company remained in the same range throughout the period of injury.
- c. The applicant has raised the issue of tariff concessions on import of subject goods from Japan and Korea under the FTA as well as inverted duty structure. The Designated Authority is not the appropriate forum to raise these issues.
- d. The applicant is enjoying duty from almost all major sources of imports.
- e. The applicant adopts an erratic pricing policy and changes prices on an average 2-3 times a month by virtue of its monopolistic position and anti-dumping duty protection.
- f. Imports are required in order to bridge the demand and supply gap as the applicant cannot cater to the entire demand.

- g. Production facilities of the applicant are located in the western corner of the country making supply chain difficult for eastern and deep southern customers. Imports become more viable from ports rather than depend on the sole producer.
- h. Extension of anti-dumping duty is not a norm but an exception. Facts of the present case do not require extension of duties.
- i. With the expiry of the anti-dumping duties, the exporters will try to recover their prices and the landed price will increase.
- j. Domestic users require level playing field against anti-competitive and monopolistic behavior of the applicant.

E.2 Submissions by the domestic industry

24. The following submissions have been made by the applicant during the course of the investigation:
- a. In case of review investigation of Ammonium Nitrate, Indonesia was removed from the scope of review as there were no imports from the country and the domestic industry in that case could not establish likelihood of dumping and injury.
 - b. Reason for exclusion of Thailand from the scope of review of uncoated paper was that (a) the dumping margin was de-minimis (b) the imports were de-minimis and (c) the Authority did not find any likelihood of injury.
 - c. As required by the Part II of the questionnaire, the responding producers were required to provide information on production, sales and exports in their respective countries. However, as per the non-confidential version of the response shared with the applicant, Covestro Polymers and BASF Limited have not provided the relevant information.
 - d. The applicant has fulfilled its obligation of providing the import data in PDF format as stated in the Trade Notice 07/2018. The Authority authorizes all the interested parties to obtain such data.
 - e. Indian Polyurethane Association (IPUA) was asked by the Authority during the Oral Hearing to substantiate its claim of demand in India being more than 1 lakh tons and reason for imports was demand and supply gap, however, no information has been provided.
 - f. IPUA has not established its credential to participate in the present investigation.
 - g. The submission made by the other interested parties that the producers in the subject countries will look to increase their prices with the expiry of duties, implies that the producers have absorbed the anti-dumping duties. Further, it is believed that exporters will increase their prices, there is a likelihood of diversion of third country exports to India as the exporters will find it beneficial to sell in the Indian market.

E.3 Examination by the Authority

25. The Authority notes that the applicant has provided a duly substantiated application based on which the present sunset review investigation was initiated. The present sunset review investigation was initiated based on the data/information provided by the domestic industry and the Authority has initiated the sunset review investigation after prima facie satisfying itself that there is sufficient evidence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the applicant.
26. On the submission of participation of Indian Polyurethane Association, the Authority notes that in accordance with Rule 2(c) and 6(5), a consumer association may participate in an anti-dumping investigation in cases when the PUC is sold at retail level. In cases where the PUC is not sold at retail level, the industrial users may participate. Further, all interested parties have been given an opportunity to present their views orally in the oral hearing and all submissions filed by the interested parties have been taken into consideration for the purpose of the present finding.
27. Regarding the erratic pricing policy adopted by the applicant domestic industry, the Authority notes that there is a significant fluctuation in the selling price of the applicant as well as the price of imports. Both the landed price of imports and the selling price of the applicant show an increasing trend in the first quarter of the period of investigation, declined in the next quarter and then further increased thereafter. Further, the applicant has admitted in the application that there has been significant fluctuation in his selling price, landed price of imports and the prices of raw materials during the period of investigation. Therefore, when the prices have fluctuated significantly due to market forces, there is no merit in the argument that the applicant has kept an erratic pricing policy.
28. Regarding the submission of inverted duty structure made by several interested parties, the Authority notes that imposition of an anti-dumping duty has an objective of neutralising unfair trade practice of dumping. Since AD

is not a normal basic duty but only a remedial measure, the argument against inverted duty structure is trivial and simply a fact. ADD cannot be used as an instrument to remedy any difficulty faced by the domestic industry due to tariff concessions under FTA.

29. With regards to DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to volume & value of imports from the exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority notes that the procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Hard copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The interested parties who requested for procurement of import data from DGCI&S and provided undertaking as per Trade Notice 07/2018 were also granted authorization to obtain import data in excel file from DGCI&S.
30. There has been submission by the other interested parties requesting exclusion of Korea RP from the scope of subject countries as there is no injury, or likelihood of dumping and injury due to exports from Korea RP. For this submission, the interested parties have relied upon SSR investigation of ammonium nitrate in which Indonesia was excluded from the scope subject countries and SSR investigation of uncoated copier paper wherein Thailand was excluded from the scope of subject countries. In this regard, the Authority notes that the facts of the investigations referred to by the interested are not similar to the facts of the present investigation. In case of sunset review of ammonium nitrate, Indonesia was excluded as there were no imports from Indonesia during the POI and the likelihood of dumping or injury w.r.t exports from Indonesia could not be established. Further, in the sunset review of uncoated copier paper, Thailand was excluded as the dumping margin during the POI was de-minimus and the likelihood of dumping or injury could not be established. However, in the present case, the applicant had established continuing injury and likelihood of dumping or injury in case the anti-dumping duties are ceased. Further, during the course of the investigation, none of the interested parties have provided any justification for exclusion of Korea RP from the scope of the subject countries.
31. IPUA has provided estimate based on production quantity of the user industry that consumes TDI as input material. Based on estimate production of the finished products including Flexible Slab Foam, Moulded Foams, Adhesives in Flexible packaging and consumption pattern for these products, IPUA has estimated total demand to be 1 lakh ton. However, the IPUA has failed to provide authentic report that can substantiate their claim.

F. CONFIDENTIALITY

F.1. Submissions made by the other interested parties

32. The following submissions have been made by the interested parties with regards to confidentiality:
 - a. The applicant has claimed excessive confidentiality which violates Rule 7 of the anti-dumping rules.
 - b. Manufacturing process, purchase/sales policy, names of raw materials, relationships with foreign producers etc. have not been disclosed by the applicant.
 - c. The Authority had in the previous finding disclosed capacity, production and sales figures of the domestic industry which has been claimed confidential by applicant.
 - d. Global capacity information is as per ICIS report data which has been claimed as confidential even though it does not contain business sensitive information.
 - e. The domestic industry has claimed excess confidentiality in complete contravention of trade notice 10/2018 dated 7th September, 2018.

F.2. Submissions by the domestic industry

33. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to confidentiality:
 - a. Sales channel has been claimed confidential by BASF Limited and Covestro Polymer.
 - b. Items of price adjustments in the normal value and export price has been claimed confidential by Hanwha Solutions Corporation.
 - c. Information on production and demand of the product under consideration in the subject countries has been claimed confidential with no indexation provided by Hanwha Solution Corporation and Wanhua Chemical Group.

- d. Reply to question on whether raw material has been purchased from related supplier or produced captive has been claimed completely confidential by Hanwha Solution Corporation.
- e. Contrary to the submission of the other interested parties, the applicant has in fact disclosed the range of non-injurious price for both the plants.
- f. The applicant has made complete disclosure of information as required by the Trade notice 10/2018 dated 7th September.
- g. All relevant information considered by the Authority for injury analysis has been provided by the applicant as per the trade notice issues.

F.3. Examination by the Authority

- 34. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7) and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 read with Trade Notice 01/2020 (as extended by the Authority till further notice).

- 35. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- 36. Submissions made by the domestic industry and the other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1 Submissions made by other interested parties

- 37. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation:

- a. Covestro China meets the criteria laid down rebutting the non-market economy presumption as per Annex I, Paragraph 8 of the Rules.
- b. Covestro China is a 100% owned subsidiary of Covestro Germany. There is no holding by the Chinese Government or Chinese company or individual.
- c. The board of directors comprise of 3 members and all three of them are appointed by Covestro Germany. A supervisor has also been appointed by Covestro Germany.
- d. Covestro China imports Toluene from Korea, Japan and also sources it locally. Covestro's purchase price of raw materials reflects the prices on the international market.
- e. There are no restrictions by the Government of China on business operations of Covestro China.
- f. Covestro China is not in derogation or exemption from any laws in China PR.
- g. Financial statements of Covestro China are prepared by GAAP of China PR and the same are audited by one of the Big 4 Audit Firms.
- h. TDI market is a price transparent market with prices posted daily by PU daily and weekly by ICIS. Covestro China sells its products on the basis of these prices.

- i. In the anti-dumping investigation of High Tenacity Polyester Yarn originating in or exported from China PR, the Authority had accepted the MET claim on the basis of same grounds.
- j. Methodology suggested to use the raw material export price from the country of origin (not the domestic selling price) and the conversion cost of the domestic industry, is without any legal basis and should not have been accepted.
- k. Decision of Hon'able CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India does not exclude the relevance of 'level of development' for selection of an appropriate third country when the export from such third country to another third country is to be considered.
- l. The Authority needs to determine that Taiwan is an appropriate market economy third country based on level of economic development.
- m. Even after engaging in imports and exports for a long time, the applicant does not have access to trade journals publishing prices.
- n. The applicant has chosen to adopt methodology inconsistent with the Anti-dumping Agreement or the Customs Tariff Act.
- o. It is evident from the past practices of the Authority in matters like Choline Chloride that resale price by the related importer is not considered for determining the landed price in case the importer is related to the exporter.
- p. Since Wanhua Chemical Group Co. Ltd. started production only in 2018, a separate dumping margin should be determined for the Wanhua Chemical Group.
- q. The application does not provide positive evidence for likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury due to alleged imports as required by Article 3(1) and 3.5 of the ADA.

G.2 Submissions made by the domestic industry

38. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of investigation:
 - a. The claim of Covestro Polymer for market economy treatment is solely on the ground that the entire share capital is held by a company set up in Europe. Shareholding of the company is not the sole criteria for claiming market economy treatment.
 - b. Two producers from China PR filed responses but only Covestro China has claimed market economy treatment and Wanhua Chemical Group has not.
 - c. If Covestro Polymers claims that it is operating under market economy conditions, it is required to show that how its costs and prices are not at the same level as for Wanhua Chemical Group. Comparison should be made between domestic selling price, cost of raw materials, cost of utilities and other expenses of both the producers.
 - d. Covestro Polymers has reported in its annual report that it competes with Wanhua Chemical, BASF, Dow Chemical and Huntsman. The fact that both producers compete in the domestic market of China establishes that the price in Chinese market are affected due to non-market conditions.
 - e. The price of Toluene in China are impacted due to the non-market conditions. The import price of Toluene in China will naturally be in line with the price of Toluene in China. The price in China is lower than the global import price and the price of the applicant.
 - f. Comparison of CFR prices and South East Asia prices show that prices in China are lower for most of the months.
 - g. Domestic price and cost cannot be considered unless the Chinese producer demonstrates that there is no state intervention in determination of cost and price, prices reflect market value and there is no restriction in the volume of sales in domestic or export market.
 - h. Covestro India Private Limited imports from its related entities Covestro Polymers in China and other related producers in other countries. The product is captively used and also sold in the domestic market. However, as per price trend observed in market, prices at which Covestro India Private Limited imports is significantly higher than the price at which it resells in the domestic market.
 - i. Constitution of China permits engagement with the non-public sector. As per Article 11 of the Constitution, the State is assigned the role of an interventionist that goes beyond protecting the rights and interests of the non-public sector and the State shall "encourage, support, and guide" their development. Article 15 of the Constitution directly states that the country practices socialist market economy and

makes it clear that the same is done by variety of different instrument such as incentivizing and restricting to guide the economy.

- j. The General Program of the Chinese Communist Party Constitution also plays an important role in development of the socialist market economy. It states that a decisive role of market forces in resource allocation and ensures the government plays its role better. It establishes a sound system for macroeconomic regulation. Covestro China has not established how they are not governed under the basic foundation program of Chinese Communist Party.
- k. President Xi Jinping, in his work report, speeches and the General Program of the amended CCP Constitution reaffirmed leadership of the Party over 'all work'. The same is also stated in Articles 6 and 7 of the Constitution and subsequent legislation such as Article 1 of the Law on State-Owned Assets in Enterprises.
- l. China has resorted to top-down interventionist industrial policy to achieve industrial modernisation and economic goals. It is done by having an elaborate system of plans covering all aspects of the economy and levels of government. It is established that Covestro China is working with the support of Chinese Government.
- m. Role of the State in the Chinese economy goes beyond mere ownership. It is not uncommon to find privately owned companies have close links to the government. Companies will not necessarily be registered in a category that reflects the ultimate ownership. It is recorded that Chinese government through creating 'special management shares', is pushing some of its largest private tech companies to offer the State a stake in them and a direct role in corporate decisions.
- n. President of Covestro China, has stated publicly that Pudong's highly efficient local government and extensive services provided to companies have helped Covestro make the move to the area.
- o. Even when it comes to allocating factors of production, the State remains completely dominant in finance. If the Covestro China has taken some form of lending from the Chinese banks, it clearly implies that there is some form of state intervention.
- p. Top Chinese chemical companies have expanded their capacities and have often focused on products for which China used to depend on imports. China has built dedicated chemical parks around user industries to fit the State policy of reducing dependency on imports. The issue of overcapacity is particularly relevant in the chemical industry. Economy in China is largely under the influence of Government control which is evident from these industrial parks set up by Government and the Chinese Five Year plans.
- q. The 13th FYP for the Petrochemical and Chemical Industry (2016-2020) defines overall quantitative development targets for growth and profitability to be achieved by the sector. It also imposes government control over production capacity where it considers it to be in excess. The plan also confirms the goal of rebalancing overcapacity levels through sales abroad. It further influences management of supply/demand in foreign markets. The Shanghai Foreign Investment Guide mentions the Plan and also proudly cites the case of 'Germany's Covestro'. This shows that Covestro enjoyed the benefits and advantages provided by the State.
- r. The Plan even provides for the use of trade remedy rules for implementing the goals mentioned above making it clear that they will intervene and support such corporate activity abroad.
- s. Besides the tax incentive programmes that China uses to support the implementation of chemical plans, a scheme of rebates on the value-added tax (VAT) of up to 17% have been available for exports and imports of certain chemicals, as well as certain raw materials that are imported to manufacture finished goods for re-export. The Chinese authorities adjust VAT rebate levels to fulfil industrial policy goals.
- t. President of Covestro China, acknowledged in an interview that the prices of natural gas in China are controlled by the Chinese government. Covestro has purchased natural gas at a price which is not at a market price and the share of natural gas is significant in total cost of production of TDI and therefore, the Authority cannot accept the cost claimed by the producer for the purpose of determination of normal value.
- u. Market distortion has been found in several anti-dumping and countervailing proceedings by other Authorities such as in case of Aluminium Converter Foil and Aluminium Extrusions decided by the European Commission. USDOC has also concluded in detailed study that China PR has not transitioned into a market economy and continues to operate under NME principles.
- v. Even the Indian Authority has not accepted MET claims in various investigations such as the anti-dumping investigation of Electrical insulators and Para Nitro aniline (PNA).

- w. As per Section 9A(b) of Act, where export price is unreliable because of association between the producer in subject country and related entity in India, export price is required to be computed on the basis of price at which the imported articles are first resold to an independent buyer.
- x. BASF has stated in response that it has made all its exports to India to related customers BASF India Limited. However, as per market information of the applicant, related entity of BASF India is not an importer on record. Either significant volume of imports are not reported in import data or related entity is only providing agency services in India.
- y. Hanwha Solutions Corporation has a related entity in India named Hanwha Chemical India Private Limited which is engaged in marketing and distribution services of all type of chemical products and to do agency business for the sale of these products. Services provided are in nature of agency services which require adjustments for commission.
- z. Responding producers were required to explain each adjustment claimed by them so as to carry out a fair comparison. However, none of the producer has provided any explanation for adjustment claimed.
- aa. Decline in import price is much more than the decline in price of raw material and the same is because the foreign producers were faced with oversupply and they started dumping their goods in the global market.
- bb. On a comparison of import price with the prices published in the trade journal. import price into India is even below the prices published.

G.3 Examination by the Authority

39. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

40. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers from the subject countries and their importers have filed exporter's questionnaire response along with their related exporters or importers:

- a. Covestro Polymers (China) Company Limited along with Covestro (Hong Kong) Limited and Covestro (Shanghai) Investment Company Limited
- b. Wanhua Chemical Group Co., Ltd along with Wanhua Chemical (Singapore) PTE. Ltd., Wanhua Chemical Fujian Co., Ltd., Wanhua Chemical (Yantai) Sales Co., Ltd., Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Ltd. and Wanhua International (India) Private Limited.
- c. BASF Company Ltd, Korea RP and BASF India Limited
- d. Hanwha Solutions Corporation along with Everlite Korea Co. Ltd., IMS Corporation and PP & Y International Co. Ltd.

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

A. China PR

41. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or*

a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- i. *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
 - b. *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.*
 - c. *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
 - d. *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.*
42. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to MET/supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.
43. The Authority notes the following relevant provisions related to normal value computation under the Anti-Dumping Rules. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:
- "7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*
8. (1) *The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).*
- (2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence*

to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

Covestro Polymers (China) Company Limited, Covestro (Hong Kong) Limited, Covestro (Shanghai) Investment Company Limited and Covestro India Pvt. Ltd.

MET Analysis

44. Covestro Polymers (China) Company Limited has claimed MET status stating that TDI being transparent market, the producer Covestro should be granted MET. Covestro Polymers has filed the MET Questionnaire and cited anti-dumping investigation of High Tenacity Polyester Yarn originating in or exported from China PR where in producer Hyosung Chemical Fiber was granted MET status based on the direct control of the entity by parent based in Korea, alignment of raw material price with the international prices, and the negotiated rate of utilities at market competitive price.
45. In this regard, the Authority notes that Market Economy status is granted to a producer, if the producer is able to show that procurement of land, provisioning of raw material and utilities, and financing of project is conducted at market price without any interference of the government.
46. The Authority notes that MET claims were granted to Hyosung Chemical Fiber in the final finding cited by Covestro based on the direct control of the entity by parent based in Korea, alignment of raw material price with the international prices, and the negotiated rate of utilities at market competitive price. In the present case, the Covestro has argued that considering the Covestro China is controlled by the parent company, raw material prices are in line with international market prices and Covestro China is not in derogation or enjoys exemption from any laws in China. Covestro China has also submitted land use right agreement with local authority in Shanghai to substantiate the MET claim. However, the domestic industry has argued that the natural gas for production of TDI is supplied to Covestro China by government owned entities, whereas the price of natural gas in China is controlled by the concerned government controlled entities.
47. Paragraph 8(3) of Annexure I of the AD Rules enlists the criteria which the Authority must consider while determining non-market economy country claims, as extracted below:

“(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs, substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets other write barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate”

48. In the present case, Covestro has failed to provide relevant information including allocation of land use rights, control of raw material cost used in production of TDI by government authority in China PR, labor cost incurred in production, and pricing of utilities consumed in production that needs to be examined by the Authority for determination of MET status. Rather, Covestro has admitted that price of Toluene, raw material for production of TDI, are regulated by Chinese government or government-controlled entities. In addition, the utility like natural gas is also supplied by the government entities to Covestro. Therefore, the Authority rejects the MET claim made by Covestro Polymers due to failure to share requisite information that can substantiate their MET claim.

Normal Value

49. As the MET claim of M/s Covestro Polymers (China) Company Limited is rejected and none of other producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value is determined in accordance with para 7 of Annexure-I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country' to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

50. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
51. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non-market economy contained in the Supreme Court judgement in *Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs M/s Exide Industries Ltd.* (Civil Appeal No. 617112003 dated 2312/2005), Guwahati High Court in *M/s Century Plyboards (I) Ltd & Anr.-vs- Union of India & tur.* (W.P No. 6568/2017 dated 411012018) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in *Apollo Tyres Ltd, vs Union of India* (Appeal No. C1768,600,601,773,769/2005-AD-dated91912005), *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India* (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding implementation of para 7 of annexure 1 to AD Rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
52. The Authority notes that normal value could not be determined on the basis of prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the export prices from such a third country to other countries, as the relevant information has neither been made available by the applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source.
53. Accordingly, normal value is determined on the basis of the price actually paid or payable in India on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.

Export Price

54. Covestro Polymers (China) Company Limited ("Covestro China") is a producer of subject goods in China PR. Covestro China has one related exporter namely Covestro (Hong Kong) Limited ("Covestro Hongkong"), one related entity involved in sale of PUC in the domestic market namely, Covestro (Shanghai) Investment Company Limited ("Covestro Shanghai") and related importer namely, Covestro India Pvt. Ltd. ("Covestro India"). All these companies have participated in the present investigation and have provided the relevant details to the Authority in the prescribed formats.
55. Covestro China has exported the subject goods directly to related importer in India and also through its related exporter Covestro Hongkong. It is noted that during the POI, Covestro China has produced and exported

670MT of subject goods directly to Covestro India and 5,672 MT of subject goods through Covestro Hongkong to related and unrelated customers in India. Covestro India has consumed the subject goods for manufacturing value added products and has also resold some quantity of the subject goods to unrelated customers in India. Covestro China has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses and credit cost.

56. The adjustments towards ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, and credit cost have been verified and accepted by the Authority. The Authority has examined the profitability of Covestro Hongkong in relation to exports of subject goods to India and it was noted that Covestro Hongkong is earning profits on exports of subject goods to India. The Authority has also examined the profitability of Covestro India with respect to resale of the subject goods in India and it was noted that Covestro India is earning profits on resale of subject goods in India. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for the group has been determined and shown in the dumping margin table below.

Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (Producer) and Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd (Exporter)

Normal value

57. The producer has not claimed market economy treatment. Therefore, the normal value has been determined as per the methodology explained above.

Export price

58. As noted, Exporter Questionnaire Responses has been filed by Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (Producer) and Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd (Exporter), along with their related importer in India namely Wanhua International (India) Pvt. Ltd. They have also filed EQR of three of other related company in China namely Wanhua Chemical Fujian Co., Ltd, Related producer, Wanhua Chemical (Yantai) Sales Co., Ltd., Related Trader in Domestic market, Wanhua Chemical (Ningbo) Trading Co., Ltd., Relater Trader. However, these three companies are not involved in sales to India hence EQR for these three companies are not taken in to consideration for calculation of net export price.
59. The subject goods produced by Wanhua Chemical Group Co., Ltd. have been exported to India by related exporter namely Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. The sales by the exporter are both to related importer Wanhua International (India) Pvt. Ltd. as well as to the unrelated customers in India. It is noted from the response that during the POI, Wanhua has exported *** MT of the subject goods out of which *** MT are sold to unrelated customers and balance *** MT to related importer.
60. Exporters have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port expenses and inland transportation and the same is allowed by the Authority after examination.
61. From the information on record, it is noted that M/s Wanhua International (India) Pvt. Ltd., the related importer, has resold *** MT of subject goods during the period of investigation at a loss. There is a consistent tendency of M/s Wanhua International (India) Pvt. Ltd., the related importer, of importing the subject goods at a higher price and selling the same in Indian market at a lesser price and incurring losses. This consistent importing at a price higher price than the others, has not been explained. The Authority, therefore has adjusted the loss both in the net export price and the landed value.
62. Accordingly, the net export price at ex-factory level for the group has been calculated and is mentioned in dumping margin table below.

Other producers

Determination of net export price

63. The net export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

B. Korea RP

BASF Company Limited, Korea

Normal value

64. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that BASF Company (hereinafter referred to as "BASF / Exporter") is a producer of the subject goods. The exporter has exported the subject goods in the Indian market to its related company, namely, BASF India Ltd., which has also filed the questionnaire response.

65. BASF has sold ***MT of the subject goods in the domestic market during the POI whereas, it has exported ***MT of the subject goods to India. The Authority has examined whether their sales are made in ordinary course of trade in terms of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.

Export price

66. It is noted that BASF exported ***MT of the subject goods to India during the POI. The Authority has verified the responses of exporter and BASF India Ltd. BASF has claimed adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port charges, packing cost and credit cost and the same have been allowed by the Authority.
67. It is noted from the response that producer/exporter has exported ***MT to India through its related entity namely M/s BASF India to customers in India. From the response filed by related importer, it is seen that the sales made by importer shows profit. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

M/s Hanwha Solutions Corporation, M/s Everlite Korea Co. Ltd., M/s IMS Corporation and M/s PP & Y International Co. Ltd. (Producer/Exporter)

Normal Value

68. During the POI, Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has sold ***MT of subject goods in the domestic market to unrelated parties only. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions is more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value.
69. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has claimed adjustment on account of inland transportation, packing expenses and credit cost and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, normal value at ex-factory level for Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

70. During the POI, Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has sold *** MT of subject goods of invoice value *** indirectly to India through three unrelated traders namely, Everlite Korea Co. Ltd., IMS Corporation and PP & Y International Co. Ltd., Korea RP.
71. Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has claimed adjustment on account of inland transportation, domestic handling charge, credit cost, bank charges and packing expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, export price at ex-factory level for Hanwha Solutions Corporation, Korea RP, has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Other producers

72. The Normal value and export price for non-cooperative producers/exporters from Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The values so determined is mentioned in the dumping margin table.

C. Japan

73. The Authority notes that none of the producers/exporters from Japan have participated in the present investigation. For the non-cooperative producers/exporters, the Authority has determined normal value and net export price on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The values so calculated is provided in the dumping margin table below.

F.4.3 Dumping Margin

74. Considering the normal value and export price determined as explained above, the dumping margin is calculated and shown below. It is seen that the dumping margin is positive in respect of all the responding producers except M/s Hanwha Solutions Corporation and for exports from Japan.

SN	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	%
A	China PR					
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	***	0-10
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	***	20-30
3	Any other producer	***	***	***	***	30-40
B	Korea RP					
1	BASF Limited	***	***	***	***	20-30
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	-
3	Any other producer	***	***	***	***	60-70
C	Japan					
1	Any	***	***	***	***	20-30

Section - III**H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1 Submissions made by other interested parties**

75. The submissions of the interested parties with regard to injury and causal link are as under:

- a. If April-June 2020 quarter is excluded from the injury and likelihood analysis, it will show significant improvement in the performance of the domestic industry in the period of investigation.
- b. Imports from China PR have not been very high even prior to the levy of the duty and remained in the region of 5000-11000MT in view of the huge demand supply gap.
- c. The applicant is operating at 96% of the capacity utilization. A decline of 4 points compared to base year where significant period was without economic activity shows robust growth of the applicant.
- d. As per the annual report of 2020-21, the applicant's market share has increased to become 66%. Market share of the applicant increased by 3%, and that of the subject countries has declined by 49%.
- e. There is no decline in production, capacity utilization and productivity and significant decline in the inventory.
- f. Domestic sales of the applicant have increased. Any decline in the sales is due to the decline in the demand.
- g. The applicant was in abnormally high profits in the base year and comparison cannot be made with the base year profits.
- h. The applicant's performance has improved as it was suffering losses in 2019-20 with duty on the imports and has started making profits in the period of investigation.
- i. Decline in performance of these parameters is because depreciation costs of the domestic industry which have doubled in the injury period.
- j. The Authority in the safeguard investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series, held that high depreciation and finance charges were responsible for the losses as a result of which the causal link failed.
- k. Total sales have declined due to excessive captive consumption which has increased by more than 13 times from 100 to 1259 during the period of investigation.
- l. Cost of sales of the applicant for export operation and domestic operations is disproportionate during the period of investigation.

- m. Net fixed assets, working capital and capital employed of the applicant have increased without corresponding increase in capacity.
- n. As per annual report of the applicant, it has performed exceedingly well in the period of investigation and TDI plant achieved highest ever capacity utilization.
- o. There is no requirement of the monthly comparison of parameters as there is no significant variation in the prices of raw material in the next 7 months of the POI, whereas the POI was the period of lockdown due to covid 19. Further, it is not the consistent practice of the Authority to examine the aforesaid parameters on a month-wise basis. Examination of such data on a month-wise basis does not provide an accurate picture of the aforesaid parameters for the POI as a whole.
- p. Demand analysis done by the applicant excluded COVID period but the COVID period was not excluded in analysis of other parameters. The Authority is requested to analyze information with and without the COVID period.
- q. Injury faced by the domestic industry was on several factors such as Covid, imports from other countries, shutdown, imports from Japan, decline in demand and other internal inefficiencies. Petitioner itself has admitted that Covid-19 related lockdowns in the POI has impacted its economic performance. Despite the lockdown, the petitioner's economic performance has been healthy.
- r. The petitioner's submissions regarding injury during this period are incorrect.
- s. The Authority must also call for records of number of days of closure of TDI plant by GNFC during the period of investigation.
- t. There is no suppression or depression effect as the applicant has been able to increase its prices.
- u. Contrary to the submission that it exported due to adverse domestic market condition, the applicant has stated in the annual report that the exports are on account of its dominant positioning in the global market.
- v. Positive price undercutting is not because imports are at dumped prices but because of the high prices charged by the applicant under monopolist pricing situation.
- w. Imports from Korea RP cannot be cumulated as they have sharply declined.
- x. Japanese exporters had exported certain quantities at lower price because of their ethical standards and commitment to honor old contracts against which there was a delay in supply despite prices being high. This should not be considered as high price undercutting.
- y. No volume effect as imports significantly and continuously declined from the base year to the period of investigation. Increase in imports in the period of investigation is only to bridge the gap to supply to the domestic market ducking the lockdown.
- z. There is no price effect because even when price undercutting became positive, landed price increased by 30% indicating that the applicant suppressed its domestic selling prices to show price undercutting.
- aa. Decline in the return on investment is attributed to the sudden and sharp increase in the capital employed over the injury period.
- bb. The increase in inventory is required to be seen in connection with the increase in domestic sales. Inventory hasn't increased in isolation.
- cc. Though the production and capacity utilization have declined in the post POI, domestic sales have increased. On the other hand, export sales have significantly declined for the petitioner. Due to the lack of segregation of production as intended for domestic sales or export sales, the respondent submit hat decline in export sales has caused decline in production and capacity utilization.
- dd. Volume of the imports decreased in 2018-19 and 2019-20. However, instead of the profitability parameters improving, they significantly declined. When imports increased slightly, the profitability parameters also increased. Same is also noticed for price undercutting.
- ee. The Authority should verify the petitioner's data regarding decline in selling price, which contradicts the publicly available information regarding the price trend of the PUC.
- ff. The reason for decline in the petitioner's profitability is the increase in cost of sales, whereas there was steep increase in cost of sales by over 30 indexed points in post POI from the POI.
- gg. The petitioner has incorrectly stated their market share as 50-55 %, which is rather 66%. The petitioner's claim of being forced to export due to competition from subject imports is incorrect, as the petitioner's export sales have in fact decreased over the injury period.

- hh. The applicant claimed that its recovery is below 22%. 22% return for non-injurious price is not a guarantee for recovery as held by CESTAT ruling in Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority.
- ii. The claimed ROCE is incorrect as the petitioner has calculated ROCE by including financial performance for export sales as well, rather petitioner must show performance of ROCE for domestic operations only.
- jj. Due to Covid pandemic, there was time lag issue in the pricing of the goods.
- kk. During the oral hearing, the applicant claimed its capacity was around 87,000 MTPA but by its annual report it is 64,000 MTPA and its website claims it to be 67,000 MTPA.
- ll. Production facilities of the applicant are located in the western corner making the supply chain difficult for eastern and deep southern customers. Imports become more viable from ports rather than depend on the sole producer.
- mm. The applicant has export obligations under EPCG scheme which is confirmed by its annual report. The report states that a substantial quantity exported under deemed export schemes to EOUs and SEZs
- nn. Data provided by the applicant under para 70 of the application and format IVA-II are misleading and contradictory. Similarly, indexed data given for domestic sales and demand in Para 58 and Para 66 are contradictory to each other making the data unreliable.
- oo. There is no substance in the claim that though the volume of imports from the subject countries have declined over the injury period, they have remained quite significant in absolute and as well as in relation to production and consumption.

H.2 Submissions made by the domestic industry

76. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:

- i. Performance in the period of investigation has been impacted by three factors – (a) COVID-19 (b) dumped imports from the subject countries and (c) imports from other countries resorting to dumping in India.
- ii. The demand has declined in the period of investigation as compared to 2018-19 because of the COVID-19 pandemic.
- iii. Volume of imports from the subject countries declined over the injury period but have remained significant in absolute and also in relation to production and consumption.
- iv. Even if the volume does not increase further, this volume per se is sufficient to cause injury to the applicant.
- v. Landed price of imports from the subject countries was below the selling price of the domestic industry. Therefore, the imports were undercutting the prices of the domestic industry.
- vi. Due to significant fluctuation in prices of the imports, the Authority is requested to calculate month-wise price undercutting.
- vii. Imports were not suppressing or depressing domestic industry prices with the protection of ADD.
- viii. The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period and is more than the demand in the country.
- ix. The applicant holds 50-55% market share and is constrained to undertake unwanted and less remunerative exports.
- x. The production, capacity utilisation and domestic sales declined in the period of investigation whereas the imports increased.
- xi. The applicant can cater the entire demand in the country, but its market share is significantly low.
- xii. The applicant suffered losses in the previous year 2019-20 due to imports from the other countries now attracting duty. While the performance has improved in the period of investigation, the current profits are very low.
- xiii. The current return earned by the applicant is significantly low considering the investments made.
- xiv. The value of closing inventory lying with the applicant at the end of the period of investigation was for more than Rs ***.
- xv. The ability of the domestic industry to raise capital investment is impaired. The production facilities for the product under consideration are highly capital intensive.

- xvi. Dumping has intensified over the injury period. Barring China PR, the duties were recommended on dumping margin, it shows that barring China PR, the dumping margin was lower than the injury margin in the original investigation.
- xvii. Even if the volume of imports does not increase per se, the current volume is sufficient to cause injury to the domestic industry.
- xviii. Performance of the domestic industry deteriorated further in the post-period of investigation and that is only due to the imports from the subject countries.
- xix. The Authority is requested to make appropriate adjustments for the period of the lockdown and unlockdown in various relevant parameters and issue appropriate direction to all interested parties.
- xx. No material inefficiencies in the cost of production. Dahej Plant of the applicant is a new plant whereas Bharuch Plant being an old plant is fully depreciated. Not a single day of shutdown in the period of investigation is due to inefficiency.
- xxi. Captive consumption is for creating TDI-MDI blend which was further resold in the market.
- xxii. On the submission of export obligation of the applicant on the new plant, there is no export obligation for the applicant during the period of investigation. The export obligation of the applicant was completed in the earlier years.
- xxiii. The return earned by the applicant is significantly lower, if export profits are also considered.
- xxiv. The return earned by the applicant considering its total sales is not even sufficient to earn bank rate of interest.
- xxv. The Authority may kindly make appropriate adjustments for the period of lockdown and unlockdown in various relevant parameters to all interested parties.
- xxvi. As high as 48% of the production was exported by the domestic industry at a price materially below the domestic prices. The consumers in the country have preferred the low-priced dumped imports.
- xxvii. Adverse performance of the domestic industry in the exports undertaken by it is attributed to the dumping of the product in the country
- xxviii. On the submission of significant difference in the price of domestic and export operations, there is no material difference in the cost of production for domestic and exports. The difference is in the cost of production of the two plants.
- xxix. On the submission that the applicant's profits in the base year were abnormal and should be disregarded, it has not been substantiated why should it be disregarded. The domestic industry aligns its prices to the import price. As the import prices in the base year were higher, the applicant was able to fetch adequate prices.
- xxx. Cost of Dahej plant is higher as it is a new plant and has higher incidence of depreciation and other fixed expenses. Bharuch Plant being an old plant is fully depreciated.
- xxxi. Captive consumption undertaken is hardly 100 MT in the period of investigation and is not even 0.02% of the production undertaken by the applicant and is for creating TDI – MDI blend which was further resold in the market.
- xxxii. On the submission of increase in the net fixed assets of the applicant, net fixed assets have actually declined. The increase is because of allocation between domestic and export sales and change in the ratio of the two.
- xxxiii. On the submission of the other parties on the statements in the annual reports, the applicant has even in the annual reports admitted that its plant is underutilized. Performance in the period of investigation has improved as compared to the previous year when it was in losses.

H.3 Examination by the Authority

- 77. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the

domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

78. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
79. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
80. As regards the submission of other interested parties on the difference in the capacity reported in the anti-dumping formats and the annual reports, the Authority notes that the capacity in the anti-dumping formats has been considered on the basis of capacity as per pollution board control and capacity in the annual reports is as per the name plate capacity. On an analysis of the monthly production of the applicant, it is seen that the applicant can infact produce more than the name plate capacity. The Authority has therefore, as per its consistent practice, considered the capacity as provided in the pollution board certificate.
81. Regarding the submissions of injury due to Covid period, the Authority notes that the current injury is examined over the period of investigation. Injury if any due to other factor has been examined in the causal link. In any case, the Authority has also considered likelihood examination in this disclosure statement.
82. On the submission of the other interested parties on significant difference in trend of cost of sales of domestic and export operations and increase in capital employed, the applicant has provided justification for the trend which has been examined by the Authority. In this regard, it is noted that the difference lies in the cost of production of two plants. The information provided after due examination has been considered by the Authority for injury analysis.
83. As regards the issue of monthly analysis of injury parameters, the Authority notes that the practise of normalization adopted for computation of NIP in accordance with Annexure III of the AD Rules has taken care of any distortion due to closure of plant on account of covid during April 2020 to June 2021. Thus, Authority has performed the injury analysis based on the normalized data for the injury period, as the injury parameters excluding COVID data will not have any impact on the injury analysis, which has been performed on the normalized data from the period of injury.

H.3.1 Assessment of Demand

84. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of the domestic sales of the sole Indian producer, and the imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Sales of the applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	120	121	110
2	Imports from the subject countries	MT	30,484	24,038	15,608	16,418
3	Imports from the countries attracting duty	MT	1,190	7,235	18,976	15,890
4	Import from other countries	MT	1,473	1,346	1,334	1,692
5	Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	109	115	106

85. It is seen that the demand for the subject goods increased till the year 2019-20 but has declined in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the decline in demand is due to the Covid-19 pandemic. Overall, the demand has increased over the injury period.

H.3.2 Volume effect of dumped imports

Import volume and share of subject countries

86. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Subject countries-	MT	30,484	24,038	15,608	16,418
i	China P RP	MT	11,064	10,858	7,148	7,258
ii	Japan	MT	1,280	1,320	3,880	4,040
iii	Korea RP	MT	18,140	11,860	4,580	5,120
2	Imports from countries attracting ADD	MT	1,190	7,235	18,976	15,890
3	Subject countries imports in relation to-					
A	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	77	51	56
B	Demand/Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	72	45	51
C	Total Imports	%	91.97%	73.69%	43.45%	48.29%

87. It is seen that :-

- Imports from the subject countries declined after the imposition of duties till the year 2019-20. While the imports from the subject countries declined, the imports from other countries attracting anti-dumping duty increased.
- The imports from the subject countries have increased again in the period of investigation. However, the imports are still below the volume as compared to the base years.
- Imports from other countries attracting anti-dumping duty have declined in the period of investigation with the imposition of duty.
- Imports in relation to total production, consumption and total imports have declined till the year 2019-20 but increased again in the period of investigation.
- While the volume of imports from subject countries are below the volume of base year, they are significant in absolute and relative terms.

H.3.3 Price effect of dumped imports

88. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
89. Accordingly, the Authority has examined the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject countries.

a. Price undercutting

90. The Authority has determined the Price undercutting by comparing the landed price of imports from the subject countries with the net sales realisation of the domestic industry in India.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
2	Subject Countries as a whole-					
i	Landed Price	₹/MT	2,39,412	2,20,464	1,17,746	1,53,103
ii	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***

iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range	10-20%	(0-10)%	0-10%	10-20%
3	China P RP					
i	Landed Price	₹/MT	2,12,733	1,90,961	1,18,466	1,63,734
ii	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range	30-40%	0-10%	0-10%	0-10%
4	Japan					
i	Landed Price	₹/MT	2,48,219	2,48,925	1,13,413	1,30,068
ii	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range	10-20%	(10-20)%	0-10%	30-40%
5	Korea RP					
i	Landed Price	₹/MT	2,55,063	2,44,305	1,20,295	1,56,210
ii	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
iii	Price Undercutting	%	***	***	***	***
iv	Price Undercutting	Range	0-10%	(10-20)%	0-10%	10-20%

91. It is seen that the landed price of imports from the subject countries was below the selling price of the domestic industry resulting in price undercutting.

b. Price suppression/depression

92. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress the prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	116	109	104
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	74	45	63
3	Landed price	₹/MT	2,39,412	2,20,464	1,17,746	1,53,103
	Trend	Indexed	100	92	49	64

93. It is seen that the selling price of the applicant was below cost of sales in the year 2019-20 and it was in losses. Though, the selling price and the landed price of the imports have decreased by almost the same amount from base year upto the POI, but still the selling price has remained above the landed price of the imports during the entire injury period except 2018-19.

H.3.4 Impact on economic parameters of the domestic industry

94. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages,

growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales.

95. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	101	96
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	101	96
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	120	121	110
5	Export sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	78	86	75
6	Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	109	115	106

96. It is seen that: -

- The capacity of the domestic industry remained constant over the injury period and is more than the demand in the country.
- The production and capacity utilization of the applicant increased in the year 2018-19, then declined marginally in the period 2019-20 as the imports from the other countries increased. The production and capacity utilization of the applicant have further declined in the period of investigation.
- The domestic sales of the applicant increased till the year 2019-20 but have declined in the period of investigation. The decline in the domestic sales is more than the decline in the demand of the goods.
- The production, capacity utilisation and the domestic sales have declined over the injury period.
- The domestic industry is being forced to use a significant share of production for export purpose which instead could have been used to cater the domestic demand.

b. Market share

97. The Authority has examined effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry as under.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Share of the applicant	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	110	106	103
2	Share of imports from the subject countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	72	45	51
3	Share of imports from countries attracting ADD	%	***	***	***	***

	Trend	Indexed	100	557	1,388	1,255
4	Share of imports from other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	84	79	108

98. It is seen that-

- The market share of the applicant increased in the year 2018-19 but declined in the period 2019-20 as the imports from other countries increased. The market share of the applicant has further declined in the period of investigation.
- The applicant could have catered the entire demand in the country, however, it is saddled with a market share of around 50-55% over the injury period.
- Imports from the other countries attracting duty increased till 2019-20 but has declined in the period of investigation with the imposition of anti-dumping duty.
- The market share of imports from the subject countries declined till 2019-20 but have increased in the period of investigation with a decline in domestic sales of the applicant and imports from other countries attracting duty.

c. Profit or loss, cash profits and return on investment.

99. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	116	109	104
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	74	45	63
3	Profit / Loss	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	33	-19	23
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	39	-23	25
5	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	44	-17	35
6	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	37	-22	24
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	31	-20	15

100. It is seen that-

- The applicant was earning profits in 2017-18, which declined drastically in 2018-19. With dumping intensifying from other countries, the performance of the applicant deteriorated further in 2019-20 and it suffered significant financial losses.
- Profitability of the applicant has improved in the period of investigation as it has recorded profits.
- The cash profit and profit before interest and tax have followed the similar trend of profits. They declined significantly in the year 2018-19 before turning negative in the year 2019-20. However, the applicant has earned cash profits and profit before interest and tax in the period of investigation.
- The applicant has made positive return on investment in the period of investigation.

d. Inventory

101. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	281	254	230

102. It is seen that the inventory with the applicant increased in the year 2018-19 but declined in the year 2019-20 as the applicant was able to increase its sales. It is however seen that the average inventory held by the applicant in the period of investigation is still significantly high. It is also seen that the applicant had undertaken significant exports at adverse prices in order to prevent any pile up of inventories.

e. Employment, wages and productivity

103. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	No of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	104	102	95
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	139	141	124
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	101	96
4	Productivity per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	99	99	101

104. It is seen that employment levels of domestic industry increased till the year 2018-19 but have declined thereafter. The salary and wages of the domestic industry have increased over the injury period but declined in the period of investigation. Productivity of the applicant has moved in line with the production. It is however also noted that the above parameters are not solely dependent on dumping and governed by different laws in the country.

f. Growth

105. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	POI
1	Production	Y/Y	2.61%	-1.57%	-4.80%
2	Sales	Y/Y	19.55%	1.40%	-9.15%
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-67.43%	-159.18%	-218.06%
4	Inventory	Y/Y	181.09%	-9.77%	-9.24%
5	Market Share	Y/Y	9.53%	-3.67%	-1.91%
6	Profit before Tax	Y/Y	-61.07%	-160.01%	-207.25%
7	Cash Profit	Y/Y	-56.20%	-138.23%	-307.30%

8	PBIT	Y/Y	-63.13%	-159.55%	-209.95%
9	ROI	Y/Y	-68.72%	-162.87%	-173.88%

106. It is seen that the volume parameters of the applicant have recorded a negative growth over the injury period due to dumping from various sources. The price parameters showed negative growth in 2019-20 and they have shown a negative growth in the period of investigation.

g. Ability to raise fresh capital.

107. It is seen that applicant had invested Rs *** crores on its new plant in the year 2014 and its current profits are low as it is recovering from ill effect of dumping.

h. Magnitude of dumping.

108. It can be seen that the dumping margins is positive and significant from the subject countries except in case of M/s Hanwha Solutions Corporation.

I. CAUSAL LINK

109. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

110. It is seen that there were imports above de-minimis limits from other sources including European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates. An anti-dumping duty has been imposed against the dumped imports from these countries in the December 2020. Therefore, for a significant period in the period of investigation, imports from these countries were entering the domestic market at dumped prices. As has also been admitted in the application, the imports from these sources were also a cause of injury to the applicant.

b. Contraction in Demand and / or change in pattern of Consumption

111. The demand of the product under consideration increased till the year 2019-20 but has declined in the period of investigation because of COVID in the country. While the demand declined in the period of investigation, the imports from subject countries in India have increased in the period of investigation. The domestic sales of the applicant have also declined in the period of investigation.

c. Trade restrictive practices

112. The Authority notes that there is no trade restrictive practice.

d. Development of technology

113. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance

114. The Authority has considered injury data for the domestic operations separately for the injury analysis.

f. Performance of other products

115. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

116. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or

non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

117. Based on the landed price and NIP determined as above, the proposed injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below.

SN	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
A	China PR					
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	***	30-40
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	***	10-20
3	Any other producer	***	***	***	***	80-90
B	Korea RP	***	***	***	***	
1	BASF Limited	***	***	***	***	30-40
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	0-10
3	Any other producer	***	***	***	***	90-100
C	Japan	***	***	***	***	
1	Any	***	***	***	***	50-60

118. It is seen that the injury margin in respect of all the participating producers is positive. Further injury margin is positive for Japan.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

K.1 Submissions made by other interested parties

119. The following submissions have been made by other interested parties during the course of investigation:
- Request to examine 6 months of post-period of investigation data to see likelihood or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
 - The applicant relied on global capacities to conclude global oversupply implying oversupply from the subject countries. No information has been provided for 2020-21.
 - The capacity figures provided in the table are of global capacity and not of the subject countries. No information has been provided for 2020-21. Further, the excess capacities in non-subject countries can be the cause of global oversupply.
 - In the Indian Spinners Association v. Designated Authority, 2004 (170) ELT 144, it was held that mere existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.
 - Covestro China has been operating at optimum capacity. There exists no excess or spare capacity.
 - No capacity addition was done by Covestro China during the injury period.
 - The petitioner's claim of overcapacity in the subject countries has no basis and ICIS report mentioned in the petition as basis for such claim has not been provided.
 - Respondent submit that "surplus capacity" cannot refer to just any capacity over and above the domestic demand in the subject countries. Such an understanding is exceptionally flawed in a globally integrated market. Rather, "surplus" refers to idle capacities left over after meeting domestic and global demand
 - Respondent submit that Beijing Winter Olympics have forced the Chinese Government to shut down production by polluting units in China including those manufacturing the PUC. This has deeply contracted the supply and will continue to be major influencer to keep supply level restricted for next 12 months.

- j. The petitioner has claimed decline of demand in China, which could lead to increased imports to India once ADD is lifted. However, the petitioner has failed to provide relevant evidence substantiating the decline of demand in China.
- k. Export orientation of China is as low as 14% compared to 46% of Japan and 59% of Korea RP.
- l. Since anti-dumping duty has been in force for more than four (4) years, the exporters from the subject countries have already found alternative markets for exporting the PUC and made arrangements contractual or otherwise with the importers or users in the third countries. The petitioner's argument that significant share of production in the subject countries is diverted towards export and the same will be diverted to India is without any basis, evidence, constitute mere conjecture, and needs to be dismissed.
- m. Imports from China are priced higher than other countries. Higher customs duty on imports from China PR and price undercutting is negative after imposition of anti-dumping duty.
- n. The production in China is largely intended for domestic consumption only.
- o. The applicant has in its annual report admitted balanced global market for TDI.
- p. The applicant has predicted that it will be profitable even after expiry of duties which rules out likelihood.
- q. The petitioner has alleged that if anti-dumping is revoked, its return on investment will be negative. Respondent submits that petitioner's projections are pure conjecture and without any basis. Rather, the economic performance of the petitioner post POI has been very strong.
- r. No basis to claim regarding slump in demand in China or India being a lucrative market.
- s. Price undercutting declined in the injury period. Actual performance disproves any likelihood of recurrence of injury.
- t. No positive evidence given by the domestic industry to prove likelihood. In the sunset review investigation of *PVC Flex Film from China PR*, Authority terminated the investigation because of a lack of evidence to prove likelihood.
- u. Mere existence of dumping and injury margins do not mean that injury will be caused to the domestic industry. Therefore, these submissions are irrelevant. Merely because exports are being made to third countries from the subject countries does not mean likelihood of recurrence of dumping and injury. The viability of the Indian market for users such as the respondent is important given that the petitioner is the only manufacturer of the PUC in India. Due to gap in supply by DI to user industry, it is important that producers from the subject countries consider Indian market for their export for benefit of user industry in India.
- v. In response to the allegation of the domestic industry that import price of the PUC from China PR into India is lesser than the published ICIS prices, respondent submit that comparison of TDI export price to India from the respondents with the ICIS TDI prices, it can be seen that TDI export price to India from the Respondents was in line with published ICIS prices during the POI.

K.2 Submissions made by the domestic industry

120. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -

- a. Continued dumping even when duties were imposed itself establishes the likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- b. Imports from the subject countries are priced much below the non-injurious price and injury margin is significant.
- c. The applicant competes with imports directly on the basis of the price and if the duties are not extended, it will have adverse volume and price effects on the performance of the domestic industry.
- d. The volume of dumped imports from the subject countries have remained quite significant even after the imposition of the duties.
- e. Positive price undercutting even after anti-dumping duty in force, itself establishes that the cessation of duties will lead to a significant adverse effect on the prices of the domestic industry.
- f. The demand of the product under consideration in China PR has been facing a continuous decline as manufacturers involved in foam industry have shifted their production base from China to Taiwan.
- g. Covestro Polymer and BASF Limited use significant portion of their capacity to dump goods into India establishing that Indian market is important for the producers.

- h. Around 14% of production in China, 46% of production in Japan and 59% of production in Korea is being used for export purposes. India being a lucrative market, the producers will try to shift their surplus production to India.
- i. Global capacities are higher than the demand and therefore, there is a situation of global oversupply with respect to the product. Similar situation persists is applicable for producers in the subject countries.
- j. 83%, 59%, 70% of exports from China PR, Japan and Korea RP respectively are at dumped prices. Cumulatively, the associated volumes are far higher than Indian demand.
- k. 99% exports from China PR, Japan and Korea RP are at injurious prices. Cumulatively, the associated volumes are far higher than Indian demand.
- l. 48%, 63%, 46% of exports from China PR, Japan and Korea RP are at prices below than Indian prices. Cumulatively, the associated volumes are far higher than the Indian demand.
- m. Response filed by the responding producers also show that there is likelihood of injury.
- n. Export sales to India of all the responding producers have increased in the period of investigation.
- o. Wanhua Chemical Corporation has admitted that it is planning to expand in future.

K.3 Examination by the Authority

- 121. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China PR, Japan and Korea RP. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 122. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
- 123. In accordance with the practice of the Authority, the third country exports have been examined to see the pricing behaviour of the producers in the subject countries. Further, the Authority has also examined if the exports to the other countries are at prices injurious to the domestic industry and prices below the Indian prices to examine the likely increase in imports to India in the event of cessation of duties.
- 124. It is seen that producers from China PR and Korea RP have participated in the present investigation. However, there is no response from Japan. Therefore, the Authority has considered information provided by the responding producers for examining likelihood of injury for China PR and Korea RP. For Japan, the Authority has considered information provided by the applicant.

K.3.1 Idle capacities

- 125. Information with respect to surplus capacities with the producers in the subject countries is given below. The Authority has examined the information for period of investigation to examine likelihood of injury.

SN	Particulars	Capacity	Production	Idle capacity	Idle capacity as % of Indian demand	
		MT	MT	MT	%	Range
A	China PR					
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	***	20-30
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	***	40-50
B	Korea RP					
1	BASF Limited	***	***	***	***	60-70
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	***	40-50
C	Japan	***	***	***	***	20-30

Source: EQR, ICIS Report

126. It is seen that ***% of capacity of Covestro Polymers, ***% of capacity of Wanhua Chemical, ***% of capacity of BASF, ***% of capacity of Hanwha were idle in the period of investigation. In case of Japan, it is seen that ***% of capacities in Japan are lying idle. It is seen that the producers have set up capacities significantly higher than the demand in their respective country and will try to utilise their capacities for export purpose.

K.3.2 Export orientation

127. Information with respect to export orientation of the producers in the subject countries is given below. The Authority has examined the information for period of investigation to examine likelihood of injury.

SN	Particulars	Production	Exports	Export orientation as % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range
A	China PR				
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	120-130
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	250-260
B	Korea RP				
1	BASF Limited	***	***	***	130-140
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	120-130
C	Japan	***	***	***	80-90

Source: EQR, ICIS Report

128. It is seen that the producers in subject countries are utilizing a significant share of their production for export purpose.

K.3.3 Third country dumping

129. Information with respect to third country dumping is given below.

SN	Particulars	Exports to third countries at dumped price	Total exports to third countries	Exports at dumped prices as % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range
A	China PR				
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	70-80%
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	20-30%
B	Korea RP				
1	BASF Limited	***	***	***	60-70%
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	70-80%
C	Japan	***	***	***	70-80%

Source: EQR, ICIS Report

130. It is seen that a significant share of exports of the responding producers to third countries are at dumped prices. Further, on the basis of data provided by the applicant, it is seen that even exports from Japan to third countries are at dumped prices. These dumped exports to third countries are significant in relation to demand in India.

K.3.4 Third country injurious exports

131. Information with respect to third country injurious exports is given below:

SN	Particulars	Exports to other countries at injurious price	Total exports to third countries	Exports to other countries at injurious price		Exports to other countries at injurious price % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range	%	Range
A	China PR						
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	90-100%	***	110-120
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	90-100%	***	80-90
B	Korea RP						
1	BASF Limited	***	***	***	90-100%	***	120-130
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	90-100%	***	110-120
C	Japan	***	***	***	90-100%	***	80-90

Source: EQR, ICIS Report

132. It is seen that significant exports of cooperating producers to third countries are at prices which are injurious to the domestic industry. Further, on the basis of data provided by the applicant, it is seen that ***% of exports from Japan to third countries are also at injurious prices.

K.3.5 Price attractiveness

133. Information with respect to price attractiveness is given below:

SN	Particulars	Exports to other countries below price to India	Total exports to third countries	Exports to other countries below price to India		Exports to other countries below price to India % of Indian demand	
		MT	MT	%	Range	%	Range
A	China PR						
1	Covestro Polymers China Company Limited	***	***	***	90-100%	***	110-120
2	Wanhua Chemical Group Company Limited	***	***	***	70-80%	***	60-70
B	Korea RP						
1	BASF Limited	***	***	***	80-90%	***	100-110
2	Hanwha Solutions Corporation	***	***	***	80-90%	***	100-110
C	Japan	***	***	***	60-70%	***	50-60

Source: EQR, ICIS Report

134. It is seen that significant share of exports of cooperating producers to third countries are at prices below the price to India. On the basis of data provided by the applicant, it is seen that ***% of exports from Japan to third countries are at prices below export price to India. The Authority proposes to consider this along with other indications for likelihood of dumping and injury at the stage of final findings.

135. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

Submissions of the domestic industry

136. The domestic industry made the following submissions:
- i. The methodology of determining normal value based on the optimized cost of production of the applicant is not appropriate as it assumes that subject countries plant are operating at optimum level which is unreasonable/unfair to the applicant. Thus, the applicant requests the Authority to determine the normal value on the basis of weighted average actual cost of the domestic industry or the actual cost of responding producers.
 - ii. The applicant repeatedly regularly requested the Authority for determination of transaction wise margin. This is critical in present case since the exporter has very insignificant exports. With such varying trend in the prices, comparison of weighted average export price with weighted average normal value is highly misleading to show the effective dumping margin.
 - iii. In a situation where imports have occurred at significantly varying prices at or around the same month and over the investigation period, our concern is the low-priced imports, which coupled with the likely volume becomes relevant to show the extent of injury that the imports can cause to the domestic industry.
 - iv. Considering there is variation of 118 % in import prices for the same exporter, such fluctuation cannot be appropriately accounted by using the weighted average import price. It is a fit case where the Authority should consider transaction-based dumping margin and injury margin.
 - v. Despite operating with idle capacities, the producers in subject countries are utilizing a significant share of their production for export purposes. Export orientation of the producers in subject countries is significantly high considering the Indian demand.
 - vi. The majority of the third country exports to India are at injurious prices. As already provided during the investigation, the Indian market offers lucrative prices to the producers in the subject countries. Therefore, it is very likely that they will divert their third country exports to India once the duty is withdrawn.
 - vii. The Indian market is a price sensitive market. Consumers negotiate on the basis of prices quoted by the exporters. If the present anti-dumping duties are not continued, the landed import price will decline. Thus, the applicant will suffer price injury if the duties are not extended.
 - viii. As the import price is impacted by the anti-dumping duty in force. Thus, no definitive inference can be drawn from the change in the dumping margin or injury margin in such situations due to the fact that ADD is in place.
 - ix. The applicant submits that any variation in duty will be contrary to the Act, the Rules and WTO Agreement on Anti-dumping.
 - x. The applicant submits that the Authority is not required to redetermine the amount of anti-dumping duty in the present sunset review. Not only that Rule 23 does not require the Authority to determine the quantum of antidumping duty, but also, plain reading of Section 9A(5) states that the Authority is required to merely determine whether to recommend extension of anti-dumping duty for a further period of five years.
 - xi. Considering the import price variation from different sources which would lead to unreliable margins calculation, performance of the domestic industry has improved with imposition of duties, and clear evidence of likelihood of dumping and injury if duty expires, any modification to the quantum of duty would not be appropriate.
 - xii. The applicant submits that the return earned by Sheela Foam Limited (user industry) has increased continuously since the imposition of duty. It can be also seen that the profitability of the Shree Malani Foams Private Limited has also remained significantly high.

Submissions of the interested parties

137. The submissions of various opposing interested parties are summarized as follows:
- i. The dumping margin should be calculated based on the revised dumping margin/injury margin worked out in the disclosure statement. The Designated Authority previously, in cases where the exporters had intensified dumping during sunset review, determined revised duty based on the dumping margin/injury margin in current investigation.

- ii. Wanhua submits that the fact that the importing entity has sold the subject goods at a loss by selling at price lower than the import price is result of change in market situation after the subject goods have been imported. Wanhua has also submitted that the Designated Authority has erroneously applied test of association or compensation based on the difference between import price and resale price, whereas said test ought to be applied based on the price at the time of import by comparing the import price to the related and unrelated entities at the time of import.
- iii. Mere relation between the exporter and the importer should not lead to an automatic declaration of unreliability of the export price. Rather, it must be demonstrated that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer.
- iv. The Authority should reconsider the proposal to adjust the loss suffered in resale transactions by the related importers in the net export price, which is not justified. Alternatively, if the Designated Authority still doubts the reliability of the import price to the related entities, Wanhua has requested the Authority to make determination based on the import price to the unrelated entities which are in significant volume.
- v. If it is not shown that the prices are unreliable due to influences by way of relation of parties, then the landed price has to be considered based on the price already assessed by Indian customs and no further adjustments are essential and, in any case, customs was the competent authority to consider the effect of any such relation but there were no adverse determinations.
- vi. Having submitted as above, customs have already assessed the value of goods in question here and the relation of parties here did not lead to any reassessment of values declared by the company. The valuation has reached its finality already and the rules of valuation were made applicable as found appropriate by the customs authorities, which is the correct authority to apply such principles.
- vii. DGTR cannot overrule the landed price as calculated by Indian customs who is the competent authority to decide the valuation and any other method other than found applicable by the customs shall be in violation of the customs valuation rules.
- viii. The landed price as proposed in case of Wanhua is also inconsistent with the applicable valuation rules and warrants fair reconsiderations.
- ix. Indian Polyurethane Association (IPUA) submits that the applicant does not suffer any injury at all and is in a very comfortable position as is exemplified by their Annual Report for 2020-21. Further, the information given in the application does not substantiate that there is any likelihood of recurrence of injury as well.
- x. IPUA submits that the application, by very nature of the injury or likelihood or recurrence of injury claims made by the applicant, did not merit initiation of the sunset review and an objective preliminary examination of the application, in terms of the Rules, would not have led to initiation of this investigation.
- xi. IPUA submits that it was incumbent upon the applicant to file a duly substantiated application and the Authority was required to satisfy itself about the fact of duly substantiated facts in the said application before initiating a review. Further, IPUA submits that the Authority has failed to fulfil its obligation under Article 11.3 of ADA to ensure that the application is duly substantiated before this review was initiated.
- xii. IPUA submits that the applicant is enjoying anti-dumping duty protection from almost all major sources of import. The Authority, through the antidumping action, should not help creation and perpetuation of monopoly in favour of the applicant and to the detriment of the user industries.
- xiii. IPUA submits that the Authority has ignored the issue of PUC scope which includes TDI having isomer content in the ratio of 80:20 only and excluding TDI having isomer content in the ratio of 65:35 and all other grades. Further, IPUA submits since there is no clarification whether the domestic industry data as well as the import data clearly excludes those products other than TDI with isomer content in ratio of 80:20 both for volume and price analysis and dumping and injury margin determination, it is possible that all determinations have been made for both the product types and that is likely to have distorted the determinations.
- xiv. IPUA submits it is consistent practice of DGTR that product/product type which is not commercially produced and supplied in the market cannot be included within the scope of the PUC. While acknowledging the fact that the domestic industry does not produce BHT free TDI, the domestic industry has only made an assertion that they have the capacity to produce this product and therefore, antidumping duty should continue on this product also.
- xv. IPUA submits that whether the demand of a product type is significant or insignificant is not the issue. The issue is easy availability of the material without unnecessary duty burdens. Import under advance licence for export purpose carries its own transaction costs and time overruns and also deprives the exporters of the RoDTEP benefits. Thus, the alternative suggested by the Authority is a double jeopardy for the exporters.

- xvi. IPUA submits that it is a common knowledge with all the entities involved in this sector that IPUA is the nodal representative body for the polyurethane users in India. Therefore, the Authority has rightly upheld the right of the Association to participate in the proceedings and oppose the application.
- xvii. IPUA submits that price irrationality of the domestic producer compared to the price fluctuation of the basic raw material as well as the import price of the subject goods is evident from the data of toluene price, DI selling price and import price, which has not been considered by the Authority in its disclosure statement.
- xviii. IPUA submits that user industry is suffering due to erratic supply issues of the subject good, considering the applicant is the sole domestic producer of the subject good and have its production issues, pollution control issues.
- xix. IPUA submits that the demand estimate of the subject good as 1 lakh ton by the nodal representative body for the polyurethane and the foam producing industry is authentic as it has assessed the demand of the PUC by the user industries based on their consumption. Contrastingly, the Authority has accepted the demand estimate of the domestic industry without support of any authentic report.
- xx. IPUA submits that the methodologies adopted by the applicant for estimation of continued dumping were inconsistent with the ADA or the Customs Tariff Act. Hence, the Authority should not have accepted such claims of continued dumping based on such legally inconsistent methodologies for initiation of this review on the grounds of continuation of dumping. Therefore, this investigation should have been terminated instead of issuance of this disclosure statement.
- xxi. IPUA submits that methodology of adopting the export price from Taiwan to Vietnam for determination of Normal value for China is illegal. Further, the Authority has failed to provide methodology for determination of export price for Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
- xxii. IPUA submits that disclosure of methodology of determination of Normal value is an essential fact that must be disclosed by the Authority before its final determinations and without a disclosure of the methodology of determination of the normal value the disclosure statement is grossly incomplete and the Authority is required to issue a fresh disclosure before proceeding further.
- xxiii. IPUA submits that certain abnormal adjustments made by the applicant in the freight costs while determining export prices on the ground that the CIF price of imports in 2020-21 had increased because of the significant amount of freight included in the prices, which suggest that dumping margin is bound to get inflated whereas objective examination of the export price would have revealed that there was no continued dumping.
- xxiv. IPUA reiterates that the applicant suffered no material injury during the period of investigation and there is no likelihood of recurrence of injury, which is evident from public announcements of the applicant and other information available in the public domain.
- xxv. IPUA submits that the Authority has not disclosed the detail of normalization of the injury parameters excluding Covid data.
- xxvi. IPUA submits that the claims made by the applicant in their application is contradicting their own Annual Report for 2020-21 where they themselves have gone on record that the company has achieved good operational performance during the year under review, in spite of prevailing Covid-19 pandemic situation.
- xxvii. IPUA submits that the Authority has failed to clarify anywhere in the disclosure statement whether the indexed data with regard to the injury parameters such as volume of imports and prices etc. pertain to the PUC alone (i.e., TDI 80:20) or covers all TDI, including 65:35 ratio also.
- xxviii. IPUA submits that the Designated Authority has failed to fulfil its obligations to carry out the analysis of 'actual and potential' decline in various factors despite the issue being highlighted by the respondents in accordance with Annex II of the Antidumping Rules and Article 3.4 of ADA.
- xxix. IPUA submits that the Authority has failed to determine that even after expansion of the capacity, domestic industry's capacity utilization has remained at same level. Therefore, any claim of volume injury due to dumped imports is highly untenable.
- xxx. IPUA submits that the Authority has failed to examine the fact the applicant has been exporting one third of its production, since increasing their capacity, to comply with its export obligations.
- xxxi. IPUA submits that there is a huge demand supply gap as the applicant is the only producer of the subject goods and also caters to the export market. Therefore, the users are forced to import the goods despite heavy antidumping duties against all possible sources of supply for last several years.

- | | |
|----------|--|
| xxxii. | The rate in increase of sales volume of DI was much above the increase in demand. Further, the imports from the subject countries during the comparable period were almost half of the base year, indicating no volume impact as alleged. |
| xxxiii. | IPUA submits that the application gives no explanation why the cost of sales for the domestic market has gone up by 4 basis points while the cost of sales for the export market has gone down by 20 basis points during the same time period and why despite the fact that the cost of sales for the export market has come down so drastically, the applicant was selling in the export market at loss. |
| xxxiv. | IPUA submits that export prices showed price undercutting because of abnormally high prices charged by the DI amidst the monopolist pricing situation under antidumping protection. |
| xxxv. | IPUA submits that the volume and price parameters of the applicant domestic industry do not show any injury at all, whereas the domestic industry has made remarkable performance during the POI and made huge profits. |
| xxxvi. | IPUA submits that, by their own admission in their Annual Report, the applicant industry is in the pink of its health and neither suffers any material injury at present, nor there is any likelihood of imminent recurrence of injury to the Company on account of the alleged imports. |
| xxxvii. | IPUA reiterated that no positive evidence has been provided by the applicant to objectively establish that there is a likelihood of recurrence of dumping and consequent injury and all the arguments extended by the applicant is based on vague and unsubstantiated propositions. |
| xxxviii. | IPUA submits that the source of third country data examined by the Authority has not been disclosed to the interested parties, whereas the exporter questionnaire response does not provide any format for providing transaction wise third country export data. |
| xxxix. | IPUA submits that while the applicant appears to have been able to obtain transaction wise data from EQR, ICIS Reports to analyse the volume of exports from the subject countries to other countries at dumped and injurious prices, they were unable to get the price data in the said countries for determination of the normal values at the initiation stage. |
| xl. | IPUA submits there is no likelihood of significant increase in import volume considering the volume of imports has remained at the current level, with or without duty and antidumping duty against various countries, indicating thereby that there is an unmet demand which has to be fulfilled by imports. |
| xli. | IPUA submits that the price level is determined by the dominant domestic industry, whereas the removal of duty will bring back the healthy competition. Thus, the removal of duty would not cause any injury to the applicant in the foreseeable future considering the profitability position of the applicant. |
| xlii. | IPUA submits that the applicant has resorted to misleading data and information to fabricate a situation of likelihood of recurrence of dumping and injury and has made certain contradictory and vague claims which the Authority has failed to examine despite detailed submissions by the Respondents. |
| xliii. | Covestro request the Authority to confirm landed value and net export price determined in the disclosure statement, in its final findings as well. |
| xliv. | Covestro China had submitted the actual capacity and capacity utilization data to the Authority in Appendix 1 of the exporter's questionnaire response. The Authority is requested to rely on actual capacity and capacity utilization data of Covestro China while determining the idle capacity, if any. Covestro China had also submitted in its post-hearing written submissions that there is no idle capacity lying with Covestro China. |
| xlv. | Covestro submits that Covestro China has furnished detailed responses furnishing the complete information regarding land use rights, raw material, labour cost and pricing of utilities in the aforementioned sections in its MET questionnaire response. |
| xlvi. | Covestro submitted that Toluene is also used for producing drug and is therefore under control of the Government. However, Government only controls purchase procedures and trading flow to ensure that Toluene purchased for manufacture of TDI is not used in production of drugs. License is also required for its each purchase transaction. Further, the respondent submits that there is no government involvement in the price at which Toluene is purchased by Respondents. Respondents purchase Toluene at prices negotiated with the sellers directly. |
| xlvi. | Covestro submits that Authority is specifically required to assess whether cost and prices of raw materials are in accordance with market principles. Cost and prices of utilities, such as natural gas, electricity, water etc. is not specifically prescribed as a relevant criterion to be assessed by the Authority. |

- xlvi. Covestro submits that natural gas is also not a 'major input', as noted in Paragraph 8(3) of Annexure I of the Anti-dumping Rules, and only accounts for 0.8% of total costs incurred by Respondents in TDI production. Thus, any benefit received by Respondents owing to preferential price of natural gas has no significant impact on overall cost of production of PUC and consequent domestic prices of PUC.
- xlix. Covestro submits that the Authority should at-least exclude quarter of April 2020-June 2020 affected by complete lockdown. Exclusion of quarter of April 2020-June 2020 will show significant improvement in performance of Domestic industry in the POI.
1. Respondents submit that objective assessment of the imports shows that imports have declined during the injury investigation period. As the antidumping duty was in force since June 2017, thus decline in imports during the injury investigation period cannot be attributed to anti-dumping duty which was prevalent during the entire injury period.
 - ii. Export orientation as a percentage of Indian demand is not representative criteria used to assess likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Comparison of total exports of the respondents with Indian demand gives an unrepresentative and exaggerated indication about export orientation.
 - iii. Respondent submits that export sales to India of subject goods is merely 6,341 MT, which is not more than 3% of its total sales during the POI. Respondents request the Authority to consider these submissions before issuing the final findings.
 - liii. Respondents submit that the injury caused to the domestic industry in the POI is due to Covid-19 and imports from third countries and not due to imports from China PR.
 - liv. The Authority has the discretion to recommend antidumping duty for less than 5 years period when the Authority concludes that shorter period of antidumping duty would be appropriate in the facts and circumstances of the case. Respondents request that even if continuation of anti-dumping duty is recommended, the Authority should recommend such continuation of duty for a period shorter than the full 5-year period.
 - iv. Sheela Foam submits that the Authority has not quantified the demand for BHT-free TDI in India nor has the Authority provided the source for the same. In the absence of such data, the Respondent will not be able to appropriately comment on whether the Authority's assessment of demand for BHT-free TDI in India being low is correct. Nonetheless, the Respondent submits that the demand for BHT-free TDI is high and thus necessitates its exclusion, since the domestic industry does not manufacture the same. Further, even Sheela Foam has sold the finished goods manufactured from BHT-free TDI in India during the POI.
 - lvi. Sheela Foam submits that determination of product exclusion cannot be made based on demand for the particular grade or type being high or low, but whether the imported product is like the product produced by the domestic industry. In the present case, we have already demonstrated that BHT-free TDI is not like the PUC produced by the domestic industry, as it distinguishes from the subject goods in terms of health concern and consumer preference.
 - lvii. Sheela Foam submits that availability of advance authorisation cannot be a factor to determine whether or not to exclude a product type/grade from the scope of the PUC. The Authority must only consider whether the products are like products, and whether the domestic industry produced and sold the excluded product in the POI in commercial quantities.
 - lviii. The Authority has not considered the current demand for products made from BHT-free TDI in India and the increasing demand in the future. In the event, domestic demand for products made from BHT-free TDI increases in the future, the user industry would be severely prejudiced.
 - lix. Sheela Foam submits that the confidentiality claimed and allowed by the Authority is excessive. The Petitioner is a public listed company, its annual reports are published online and discloses data such as capacity, capacity utilization, sales volume sales value, etc.
 - lx. Sheela Foam submits that an increase in imports as a proportion of total imports is not at all a relevant factor under Annexure II to the AD Rules and hence cannot be considered by the Authority. The Authority is requested to withdraw its determination of the existence of volume effect based on this factor. The respondent submits that the absolute volume of subject imports is nearly half of base year levels. This strongly implies the absence of volume effect.
 - lxi. Sheela Foam submits that the Authority's analysis does not conclusively state whether the landed price of the subject imports is depressing or suppressing the domestic industry's selling prices. We nonetheless submit that there has not been any such price suppression or depression by the subject country imports.

- lxii. Sheela Foam submit that the Authority's analysis about domestic industry being forced to export which could have been used for domestic demand is incorrect, as the domestic demand has declined and export sales have declined over the injury period. The subject country imports are not the cause for the decline in the domestic industry's production during the POI.
- lxiii. Respondent request the Authority to note that domestic sales volume has increased except in POI attributed to COVID situation, but same is higher than base year. Further, the domestic industry data for captive consumption of the PUC is not included in the disclosure statement.
- lxiv. Respondent submits that the market share data cited by the Authority in the Disclosure Statement is inconsistent with the market share data cited by the domestic industry in its Annual Report, which shows that the petitioner's market share is healthy i.e. in the range of 64-70 %.
- lxv. Even if the petitioner is suffering losses, the same is due to factors other than the subject imports, considering there is no such correlation of the volume and price undercutting by the subject imports to the petitioner's economic performance.
- lxvi. The volume of subject imports decreased in 2018-19 and 2019-20. However, instead of improving, the petitioner's profitability parameters significantly declined in these two years. Interestingly, when the volume of subject imports increased slightly in the POI, the petitioner's profitability parameters significantly increased in the POI.
- lxvii. When price undercutting by the subject significantly declined in 2018-19 and 2019-20, the petitioner's profitability parameters significantly declined in these two years, instead of increasing. In fact, price undercutting was negative in these two years. In spite of the same, the Petitioner's financial parameters declined. Interestingly, when price undercutting was positive in the POI, there was a significant improvement in the Petitioner's financial performance.
- lxviii. Sheela Foam submits that mere increase in inventory in itself is not an indicator of injury. Further, the Authority's assertion that the petitioner had undertaken significant exports in order to prevent any pile up of inventories is factually incorrect as the petitioner's volume of exports has decreased in the injury period.
- lxix. Respondent submits that considering the domestic industry is being protected from the allegedly dumped imports from multiple sources still domestic industry has seen negative growth, thus injury to the domestic industry is due to factors other than allegedly dumped imports. Accordingly, the Authority must not recommend the continuation of anti-dumping duty on any imports of TDI into India.
- lxx. Authority is only required to examine whether the petitioner was constrained from being able to raise fresh capital. Since the petitioner had already made investments in 2014, and demand for the PUC in India having declined, there was no occasion for the petitioner to make additional investments.
- lxxi. Even if dumping margins are positive and significant, that in itself is not sufficient to continue antidumping duty on the subject imports. It needs to be examined whether there is a likelihood of continuation of dumping and injury.
- lxxii. Even though the petitioner's domestic sales declined in the POI, they were 10 indexed points higher in the POI than in the base year. On the other hand, the imports from the subject countries in the POI declined to half of that in the base year. Thus, even though the domestic demand declined in the POI, the domestic industry had more sales than the subject imports.
- lxxiii. The mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish the likelihood of recurrence of injury, even if the producers in the subject countries are export oriented, it does not mean that they will start exporting to India once the anti-dumping duty ceases
- lxxiv. Merely because exports are being made to third countries from the subject countries at allegedly dumped and allegedly injurious prices does not mean likelihood of recurrence of dumping and injury. The Authority has to show likelihood of diversion of exports to India upon cessation of ADD, which the disclosure statement has failed to show.
- lxxv. The petitioner's assertions about its economic performance declining in the event that ADD is revoked are negated by actual economic performance reported in public sources. This also negates the likelihood of recurrence of dumping and injury if ADD is revoked.
- lxxvi. The respondents humbly request the Authority to analyse the information excluding Covid period as well.
- lxxvii. BASF submits that the applicant has neither suffered any injury nor there is any likelihood of the dumping and the injury on account of the imports of the subject goods from Korea RP.

- lxxviii. The applicant has suffered the injury, if any, on account of other reasons and not on account of the imports of the subject goods from the subject country and particularly from Korea RP as evidenced from the following facts:
- lxxix. The capacity utilization of BASF Company Limited remained almost in the same range throughout the injury period. Accordingly, it is clear there is no likelihood of continuation or recurrence of the injury.
- lxxx. BASF submits that throughout the injury period less than 6% of the production of the BASF Company Limited was exported to India, which clearly shows that India is not an attractive market for it.
- lxxxi. BASF submits that the methodology of the third country dumping analysis and price attractiveness and injurious export analysis adopted by the Authority is fundamentally wrong and will lead to the absurd results as comparing a weighted average number with an individual number will always show some transactions below it.
- lxxxii. A sunset review, should normally not lead to any change other than the extension of the period for which the duties are supposed to be effective.

Examination by the Authority

138. The Authority notes that the post-disclosure comments/submissions made by the domestic industry and the other interested parties are mostly reiterations of their earlier submissions, which have already been examined adequately addressed in the disclosure statement or relevant paras of the present finding. The Authority has examined the submissions herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere are examined as under:
- i. The normal value, export price and dumping margin have been calculated as per consistent practise of the Authority.
 - ii. Regarding the submissions of the producer/exporter from China that the sale subject goods at loss is the result of change in market situation after the subject goods have been imported, the Authority notes that during the same period, the price at which the related importer of other producer/exporter from China PR has purchased the subject goods is much lesser (almost 40-50%) than the price at which Wanhua India has purchased from its related producer/exporter. Further, there is a marked difference in the resale price of the two importers as well (almost 10-20%), the resale price of Wanhua, India being much less than the resale price of other related importer. The reason for this difference in resale price and purchase price has not been explained Wanhua Chemical. The Authority, therefore, holds that the export price of Wanhua Chemical is unreliable and has therefore, adjusted the loss incurred by the exporter in selling the subject goods to its related importer.
 - iii. The Authority notes the concerns of the interested parties regarding initiation of subject investigation based on petition filed by the domestic industry. In this regard, the Authority re-iterates that the applicant has provided a duly substantiated application based on which the present sunset review investigation was initiated after prima facie satisfaction of the Authority that there is sufficient evidence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the applicant.
 - iv. Regarding the submission of interested parties that the Authority should not help in creation of monopoly in favor of the applicant, the Authority holds that purpose of imposition of an anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
 - v. The Authority has already held that the PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration. Further, the import data considered volume and price analysis for the purpose of present investigation concerns only the product under consideration as already defined by the Authority.
 - vi. On the submissions by other interested parties on exclusion of BHT Free TDI from the scope of product under consideration, the Authority notes that transaction wise import data does not contain description sufficient enough to identify whether the subject goods being imported are BHT free or not. Therefore, it is not possible to identify if the imported product contains BHT or not. If BHT free TDI is excluded from the scope of product under consideration, non-availability of this information may lead to evasion of anti-dumping duty. Furthermore, the Authority has estimated the demand for BHT free TDI based on information submitted by the interested parties as per which it is about 5% of the total demand in India and is mostly for export purposes). This demand can easily be meet through importing through Advance Authorization scheme.

- vii. The Authority also notes that as per the information provided by the applicant, none of the interested parties has raised any requirement of BHT Free TDI from it in the period of investigation and had there been a any requirement of BHT Free TDI from its users, the domestic industry could have supplied the same. The applicant has provided Lab Test Reports to show that it provides BHT Free TDI. Further, the applicant has also exported the subject goods containing BHT to US during the same period.
- viii. Regarding the submissions of interested parties on current demand for products made from BHT free TDI in India, the Authority notes that only one user has quantified its demand for BHT free TDI. Other users have made no such estimate nor is the information been made available to the Authority by any of the other interested party. In absence of such information, the Authority is unable to estimate the demand for products made from BHT free TDI in India.
- ix. Regarding price irrationality of the domestic producer, the Authority re-iterates that there is a significant fluctuation in the selling price of the applicant as well as the price of imports. Both the landed price of imports and the selling price of the applicant show an increasing trend in the first quarter of the period of investigation, declined in the next quarter and then further increased thereafter. Further, the applicant has admitted in the application that there has been significant fluctuation in its selling price, landed price of imports and the prices of raw materials during the period of investigation. Therefore, when the prices have fluctuated, there is no merit in the argument that the applicant has kept an erratic pricing policy.
- x. The Authority notes that while the interested parties have raised concerns regarding erratic supply of subject goods by the applicant who is the sole producer of subject goods in India, there is no documentary evidence on record that substantiates this claim.
- xi. The demand has been estimated as per consistent methodology of the Authority as the sum of total imports as per transaction wise import data obtained from DGCI&S and sales of the domestic industry as duly verified by the Authority.
- xii. The normal value for China is determined on the basis of the price actually paid or payable in India on the basis of estimates of cost of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits.
- xiii. The export price for Wanhua has been calculated on the basis of information submitted by the exporter as already stated in preceding paragraphs. Loss incurred by the exporter by selling the subject goods to the related importer has been adjusted in the export price as well as already explained in relevant paragraph.
- xiv. The export price for all co-operating producers from subject countries have been calculated based on information submitted by them. The export price for non-cooperative producer/exporters from the subject countries has been determined based on facts available in terms of Rules 6(8) of the Rules. Therefore, there is no prejudice caused to any of the co-operating producer/exporters due to adjustments made by the applicant in freight costs in the application.
- xv. The indexed data with regard to the injury parameters such as volume of imports and prices etc. pertain to the PUC alone (i.e., TDI 80:20)
- xvi. As regards the claim of the interested parties that the applicant has been exporting one third of its production, since increasing their capacity, to comply with its export obligations, the Authority notes that as per information on record, there is no export obligation of the applicant during the POI.
- xvii. The Authority notes that there is no demand supply gap as the capacity of the domestic industry is more than the demand in India.
- xviii. On the submission of significant difference in the price of domestic and export operations, the Authority notes that this difference is in the cost of production of the two plants.
- xix. The source of third country data examined by the Authority has been mentioned in the final findings. The transaction wise third country export data as submitted by the cooperating producer/exporter has been taken for the likelihood analysis.
- xx. On the submissions of the interested parties that the applicant appears to have been able to obtain transaction wise data from EQR, it is noted that the Authority has obtained and analysed the transaction wise import data from the EQR. The Applicant has no access to this data.
- xxi. The Authority has relied on actual capacity and capacity utilization data of Covestro China while determining idle capacity.
- xxii. On submission of Covestro that the respondent has shared the land use right details, labour remuneration details, and market rate acquisition of the utilities and raw materials in MET questionnaire response, the Authority notes submission of allocating authority for the land use rights is not sufficient, as the exporter has

failed to share the evidence suggesting that the land use rights were acquired at the fair market price after conducting a formal bidding process.

- xxiii. With respect to labour inputs, the Authority notes that mere payment of standard salaries is not enough, unless the labour employed by the company has right to form union for negotiating fair terms of the employment and the work conditions with the employers. In addition, the comparison of the salary paid to the skilled workers and managers with salary paid across India is flawed, as the location of the respondent, i.e. Shanghai, which is considered financial capital of China, cannot be compared with India which has variation in terms of the development and the wage standards across different regions.
- xxiv. Further, the cost and prices are also affected by provision of utilities and loans by the Govt. agencies, which are mostly State Controlled and have significant impact on the cost and prices of the subject goods. Therefore, the Authority does not find it appropriate to accept the cost and prices of the above producer in the domestic market in China for the purpose of determination of the normal value.
- xxv. The Authority notes that imports from subject countries have decreased during the injury period. However, the imports from subject countries still account for 23% of total demand of PUC in India and 48.29% of total imports of the PUC in India which is significant in absolute and relative terms. Further, with the imposition of AD duty on the PUC from subject countries during 2017-18, the imports from the subject countries started declining whereas the imports from non-subject countries started increasing. This clearly indicates a trade pattern shift.
- xxvi. Though the export sales of Covestro China to India is not more than 3% of its total sales, it accounts for 39% of total imports in India from the subject countries and 87% of total imports from China PR during the POI.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTTIER ISSUES

139. The interested parties made the following submissions against continuation of duty owing to public interest:

- i. The applicant is the sole producer in India and is trying to create monopolistic conditions in the Indian market by seeking trade remedies.
- ii. The applicant is enjoying benefit in the form of duty for 5 years.
- iii. Continuation of duty will cause harm to thousands of users in the MSME category. Large public interest will be served if investigation is terminated.
- iv. There are over 400 members in the Association and more than 120 "Toluene Di-isocyanate" (TDI) users are involved in the manufacture of Mattresses, Furniture Foams etc. Most of the user industry is in the MSME sector.
- v. Domestic users require level playing field against anti-competitive and monopolistic behavior of the applicant.
- vi. Considering the volumes given in the original final finding, the current demand in India should be 80,000 to 85,000 and the applicant can cater only 50-55% of the Indian demand.
- vii. Huge demand-supply gap and majority of the users belong to the MSME category.
- viii. TDI and FSP – two raw materials account for over 95% of the cost of raw material of the foam produced are subjected to ADD adding an extra burden on user industry. User industry works on a thin margin of less than 5%.
- ix. At the present rate of duty on TDI alone, additional cost is about 6-7%. Combined effect of FSP and TDI is around 11-12%.
- x. About 20% of the polyurethane foam bedding market is already lost to bedding produced out of polyethylene foam, a cheaper substitute.
- xi. Polyurethane industries which use TDI and FSP are import dependent to operate their units. They are already suffering from the Rupee-Dollar parity, Ocean Freight increase, Container shortage etc. and anti-dumping duties from almost all the major overseas sources are proving to be the last straw in the camel's back.
- xii. Domestic users require level playing field against anti-competitive and monopolistic behaviour of the applicant.

M.2 Submissions by the domestic industry

140. The domestic industry made the following submissions in favour of continuation of existing anti-dumping duty:

- i. The product under consideration has been attracting anti-dumping duty since 2017 and the impact of the duty on the end consumers will not be a new phenomenon.
- ii. Impact of anti-dumping duty on Adhesive, PVC coated Paper, Polyurethane Resin, Phenyl Isocyanate and PU Foam is as below:-

SN	End product	Market price of end product	Impact on end product in %
1	Adhesive	Rs 5000 per KG	0.11%
2	PVC coated Paper	Rs 70/sqm	1.32%
3	Polyurethane Resin	Rs 1300 per KG	0.23%
4	Phenyl Isocyanate	Rs 650 per KG	1.22%
5	PU Foam Rate	Rs 420 per KG	1.74%

- iii. If the users fail to establish the adverse impact of duties, the impact provided by the applicant shows that duties had benefitted the applicant without having adverse impact on the end users.
- iv. Return earned by Sheela Foam Limited has increased continuously since the imposition of duty.
- v. Profitability of the Shree Malani Foams Private Limited has also remained significantly high.
- vi. With no demand-supply gap and no reliance on the imports, the Indian TDI industry is a totally Atmanirbhar Industry.
- vii. All the past investigations have clearly established that the applicant suffers due to dumping and extension of the duties will definitely be in the interest of the applicant.
- viii. If the sole producer is left to suffer, it can eventually be wiped out and the consumers will be left at the mercy of only the exporters. The applicant being established in the same national territory as the users, will keep the user interest.
- ix. Consumers are already enjoying concessional customs duty on the imports of subject goods from Korea RP and Japan.
- x. While there should have been trade surplus in the present case, the fact is that trade balance of TDI shows a deficit which seriously impacts the foreign exchange reserve of India and defeats the aim of making India a 5 trillion \$ economy.
- xi. Out of the claimed 120 TDI users in the association, only 5 users have participated and none of them fall in the MSME category. The association has not provided any material to establish its credentials.

M.3 Examination by the Authority

141. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. The Authority considered whether continued imposition of duty will have any adverse impact on the public interest. During the course of the investigation, steps were taken to examine whether the imposition of the anti-dumping duties will be against the public interest. For this, the Authority has considered information on record and interests of various parties, including the applicant, importers and users of the product.
 - i. The Authority notes that the purpose of the anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. which is in the general interest of the country. Extension of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
 - ii. Regarding the submissions of the interested parties that the imposition of anti-dumping duty will adversely affect the interests of the users belonging to the MSME sector, the Authority notes that it is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic

industry. On the contrary, extension of antidumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

- iii. On the submission of the interested parties that anti-dumping duty is significant cost to the end users, the Authority notes that some consumers filed questionnaire response. The submissions made by the consumers during the course of the investigation have been taken into account. The Authority notes that these interested parties have not shown with verifiable information that the imposition of the anti-dumping duties shall have significant adverse effect either on these consumers or the public at large. On the contrary, the applicant has provided quantified information of the impact of duty on Adhesive, PVC coated Paper, Polyurethane Resin, Phenyl Isocyanate and PU Foam. It is seen that the impact of the duty is not significant.
- iv. During the course of the investigation, it had been contended that there is a demand and supply gap which necessitates the imports. From the information on record, it was seen that there exists no demand and supply gap and the interested party were asked to provide the basis of the claim. The Authority notes that despite being asked to, no information has been provided. It is, therefore, seen that there exists no demand and supply gap and the imposition of the duty will not impact the availability of the products to the end users.
- v. The Authority also notes that the domestic industry has shown long-term commitment to the production in India by expanding its plant in the year 2014. The applicant had made significant investments on its new plant and it is necessary that such investments are protected to support the Indian economy.
- vi. It is further noted that the fact that the prices of the domestic industry are in line with the import prices excluding anti-dumping duty also shows that the domestic industry has not charged any undue benefit of duty in their prices. The domestic industry will compete with the duty paid imports.
- vii. It is recognized that a presence of healthy domestic industry is ultimately in the interest of the users. The recent experience in the Covid-19 period has also shown that the public at large is likely to suffer, if the products are not sufficiently available in the domestic market
- viii. The Authority has also analysed the effect of continuation of anti-dumping duties from the consumer's point of view and observed that it would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the imports. If the current practices of dumping is allowed to continue, the Indian domestic producer would face further injury giving foreign producers increased leverage as against domestic producers. Further, if the domestic industry is allowed to suffer, it will eventually be wiped out and the consumers will be again left at the mercy of the imported goods.
- ix. The Authority also notes that even though the duties were in force, the user industry has witnessed increase in revenues and profits. The applicant on the contrary is recovering from the past effects of dumping. Therefore, extension of the duties will provide support to the applicant.
- x. The Authority in view of above is of the opinion that the continuation of the present anti-dumping duty on the imports of product under consideration from subject countries would not be against public interest and rather continuation of anti-dumping duties will be in the larger public interest.
- xi. It is noted that the imposition of the anti-dumping duties on imports of subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The measures would prevent further injury to the domestic industry and give time to them to compete against the exporters from the subject country.

N. CONCLUSIONS

143. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping, injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
 - a. The applicant domestic producer constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by them satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product under consideration continues to be exported to India at prices below the normal value resulting in continued dumping except for M/s Hanwha solutions corporation whose dumping margin is negative. The volume of imports from the subject country is likely to increase significantly, considering the dumped and injurious price at which goods have been exported from the subject countries, high export orientation of producers/exporters and significant surplus capacities with producers/exporters in the subject countries.
 - c. Imports from the subject countries were significantly undercutting the domestic industry prices & the domestic industry has suffered depressing or suppressing effect on its prices. Further, the injury margin/ price underselling is also significantly positive clearly indicating significant price effect on the domestic industry.

- d. The applicant was earning profits in 2017-18, which declined drastically in 2018-19. With dumping intensifying from other countries, the performance of the applicant deteriorated further in 2019-20 and it suffered significant financial losses. However, the profitability of the applicant has improved in the period of investigation as it has recorded profits.
- e. The Authority has analysed the dumping and injury margin for the cooperative producer/exporters from China PR and Korea RP and also for all other exporters from Japan, the third subject country. It is noted that the exports reported by cooperating producers/exporters from Korea RP and China PR are in consonance with the quantum of imports reported in the transaction wise import data of DGCI&S. The imports reported by the cooperating producers/exporters from China PR and Korea RP are, in fact, higher when compared with the transaction wise import data of DGCI&S. The exporters report exports in POI with reference to the shipment date whereas the DGCI&S imports in POI are collated as per the reference date.
- f. There is likelihood of continuation and recurrence of injury to the domestic industry due to the following:
 - i. The dumping of the subject goods have continued from the subject countries except for M/s Hanwha Solutions Corporation, Korea, despite anti-dumping duties being in force.
 - ii. The Authority to in order to evaluate the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duties considered idle capacity, export orientation, dumped exports, injurious exports and price attractiveness. DGTR has been consistently looking at these factors while evaluating the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duties as per Rules. In the instant case, since the capacity utilization of cooperative exporters in China PR and Korea RP is quite high i.e. 90-100% and 70-80% respectively, the third country diversion of exports by these cooperative producer/exporters to India would be of immense importance. Similarly, for Japan, where none of the producer/exporter have cooperated, the capacity utilization as per secondary sources is 80-90% which again indicates third country diversion to be a major factor of likelihood of dumping and injury. Notwithstanding the above, the capacities of producer/exporters are quite high and even the existing idle capacity is significant enough when compared with demand in India.
 - iii. The likelihood analysis of imports of the subject goods from Korea RP reveals that about 70-80% of export of subject goods by cooperative producer/exporters from Korea RP to third countries are dumped, 70-80% are injurious and 60-70% are at price below export price to India.
 - iv. In case of China PR, about 50-60% of export of subject goods by cooperative exporters from China PR to third countries are dumped, 90-100% are injurious and 80-90% are at price below export price to India.
 - v. There is no cooperation from producer/exporters from Japan, From the information available on Trade Map, it is noted that about 70-80% of export of subject goods by producer/exports of subject goods from Japan to third countries are dumped, 90-100% are injurious and 60-70% are at price below export price to India.
 - vi. The Authority has also evaluated the extent of dumping and injury margin of the third country exports by the cooperating producer/exporters from the subject countries. The adjustments reported for India have been appropriately adopted for this computation. The said margins are noted to be more significant than the margins from India.
 - vii. The volume of imports has also remained significant in absolute and relative terms.
 - viii. The cooperating producer/exporters have capacities significantly higher than the demand in their respective country fraction of which is sufficient to cater to entire Indian demand.
 - ix. The cooperating producer/exporters are utilizing a significant share of their production for export purpose.
 - x. There are significant exports to the third countries which are at prices below the non-injurious price of the domestic industry. A significant share of exports to third countries are also at dumped prices and at prices below the price in India.
 - xi. From the transaction wise details of exports of cooperating producer/exporters to third countries, the Authority notes that a significant percentage of these exports are dumped as well as injurious and at price below NSR of domestic industry in India. The said exports account for almost 286% of India's demand of subject goods. The magnitude of dumping and injury of

these exports is much more than the present dumping and injury margins with respect to exports to India during the POI.

- xii. Since India is a growing market, cessation of anti-dumping duties from the subject countries when export price from subject countries to third is below the dumped prices from India and are below the non-injurious prices clearly proves that continuation of duties is must for the Indian industry's survival.
- g. This gives clear indication that injury to the domestic industry is due to dumped imports from the subject countries. Therefore, in the event of expiry of existing antidumping duty, there is every likelihood that the dumped imports from the subject countries will increase.
- h. It is noted that the continuation of anti-dumping duties on the imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The fact that this is a capital-intensive industry, the continuation of measure would prevent further injury and give time to the domestic producers to compete against the exporters from the subject countries.
- i. The Authority has considered whether continuation of anti-dumping duty would have adverse public interest. The Authority notes that there is healthy competition in the Indian market and continuation of anti-dumping duty would not lead to monopolistic or oligopolistic situation in the Indian market for the subject goods as the imports would continue at fair prices.

O. RECOMMENDATIONS

144. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to all the interested to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
145. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on the subject goods from the subject countries.
146. Having concluded that there is likelihood of continuation of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject countries. The Authority examined as to what quantum of duty be recommended which would mitigate the dumping/injury on account of likelihood analysis as conducted above. The volume of dumped and injurious imports from cooperating exporters to India and to the rest of the world have been considered.
147. Under the aforesaid circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries which would address and mitigate the likelihood of dumping and injury from the subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification no. 03/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018. Therefore, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table, from subject countries for a further period of five years.

Duty Table

Sl. No. (1)	Sub-heading (2)	Description of goods (3)	Country of Origin (4)	Country of Export (5)	Producer (6)	Amount (7)	Unit (8)	Currency (9)
1	29291020	Toluene di-isocyanate	China PR	Any country including China PR	Covestro Polymers (China) Co., Limited	0.26	Kg	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	0.26	Kg	US\$

3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than producer at S.no. 1 and 2 above	0.26	Kg	US\$
4	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	China PR	Any	0.26	Kg	US\$
5	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	0.22	Kg	US\$
6	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	BASF Company Limited	0.31	Kg	US\$
7	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than producer at S.no. 5 and 6 above	0.44	Kg	US\$
8	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	Korea RP	Any	0.44	Kg	US\$
9	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any	0.15	Kg	US\$
10	-do-	-do-	Any other than the subject countries	Japan	Any	0.15	Kg	US\$

148. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 88, 9 and 94 of the said Act.

P. Further Procedure

149. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority